चौथी दुनिया

www.chauthiduniya.com

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

मूल्य 5 रुपये

1986 से प्रकाशित | 31 अगस्त–06 सितंबर 2015 | हर शुक्रवार को प्रकाशित | Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2015-17, RNI No. DELHIN/2009/30467

किसानों की आत्महत्या

राष्ट्रीय मुद्दा क्यों नहीं

फोटो–*प्रभात पाण्डेय*

जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान. लोकतंत्र में जय उसी की होती है, जिसकी ज़रूरत सबसे ज़्यादा होती है. लाल बहादुर शास्त्री ने 1965 के युद्ध में जय जवान का नारा लगाया और हरित क्रांति के दौर में जय किसान का. और, सफल परमाणु परीक्षण के बाद अटल जी ने जय विज्ञान का नारा गढ़ा. लेकिन, सवाल है कि जय जवान, जय किसान और जय विज्ञान के बीच आज किसान कहां पर खड़ा है? क्या किसान आज सचमुच जय की हालत में है? एक जवान की मौत पर सारा देश एक साथ सवाल खड़े करता है, लेकिन पिछले 20 वर्षों में लाखों किसानों की आत्महत्या पर हर तरफ़ खामोशी छाई है. ऐसा क्यों? जय किसान का नारा लगाने वाले इस देश में आख़िर किसानों की आत्महत्या राष्ट्रीय मुद्दा क्यों नहीं बन पाई?

शशि शेखर

उदारवादी अर्थव्यवस्था अपनाए हुए 25 वर्ष हो गए हैं. 1991 में जब इसकी शुरुआत हो रही थी, तब कहा गया था कि इससे देश में खुशहाली आएगी. आज 25 वर्ष बाद की एक स्याह तस्वीर या कहें कि आंकड़े देखिए. 1995 से 2014 के बीच देश में आधिकारिक तौर पर तीन लाख से अधिक किसान आत्महत्या कर चुके हैं. आइए, किसान आत्महत्या के आंकड़ों एवं कारणों पर बात करने से पहले हम देश के कुछ ऐसे किसान परिवारों से मिलते हैं, जो आज़ादी की 69वीं वर्षगांठ के मौक़े पर दिल्ली तो आए, लेकिन जश्न मनाने नहीं. वे दिल्ली आए थे, प्रधानमंत्री, मंत्री और मीडिया को अपनी दु:खभरी कहानी सुनाने. यह अलग बात है कि मानसून सत्र से जूझ रहे प्रधानमंत्री या किसी मंत्री को उनकी कहानी सुनने की फुर्सत नहीं मिली या कहें भारत की यह स्याह तस्वीर देखने में किसी की दिलचस्पी ही नहीं थी. अखिल भारतीय किसान सभा के नेतृत्व में क़रीब ढाई सौ ऐसे किसान परिवार दिल्ली के जंतर–मंतर पहुंचे, जिनके किसी न किसी सदस्य ने फसल क्षति या कर्ज के दबाव में आत्महत्या कर ली. जब चौथी दुनिया ने इन परिवारों से बातचीत की, तो बिना कोई खास शोध–पड़ताल के यह तथ्य सामने आया कि आख़िर देश के किसान आत्महत्या क्यों करते हैं?

जैसे ही आप चालीस वर्षीय रेखा वाडगुडे को देखते हैं, तो उनसे कोई सवाल पूछने की हिम्मत नहीं पड़ती.महाराष्ट्र के वर्धा ज़िले के पवनार निवासी रेखा के पति मनोहर महादेव वाडगुडे ने बीते नौ जुलाई को आत्महत्या कर ली. रेखा का चेहरा देखकर ही उनके परिवार की बदहाली का अंदाज़ा लग जाता है. बाकी बातचीत उनके 17 वर्षीय बेटे विक्की से होती है, जो अपनी मां के साथ दिल्ली आया था. विक्की बताता है कि बैंक, साहूकार और स्वयं सहायता समूह का कुल कर्ज क़रीब दो लाख रुपये था. 3.5 एकड़ ज़मीन में कपास और सोयाबीन लगाया था, लेकिन भारी बारिश की वजह से फसल बर्बाद हो गई. इस साल फिर बुवाई के लिए पैसे की ज़रूरत थी, उधर साहूकार और बैंक वाले उधारी चुकाने के लिए दबाव डाल रहे थे, जिसे उसके पिता झेल नहीं पाए और उन्होंने आत्महत्या कर ली. विक्की बताता है कि पुलिस ने आत्महत्या की रिपोर्ट भी लिखी, लेकिन ज़िला प्रशासन से अभी (शेष पृष्ठ 2 पर)

एनसीआरबी के आंकड़ों की सच्चाई कुछ और है

साल 2014 के आंकड़े बताते हैं कि किसानों की आत्महत्या के मामले कम हुए हैं. 2014 में यह संख्या 5,660 थी, जबकि 2013 में 11,772. आख़िर यह संख्या कम कैसे हुई? दरअसल, आंकड़े तैयार करने वाली एजेंसी एनसीआरबी ने किसानों की आत्महत्या के अधिकतर मामले नए वर्ग में डाल दिए हैं. इससे हुआ यह कि किसानों की आत्महत्या के मामलों की संख्या कम हो गई, लेकिन अन्य वर्ग-श्रेणी में यह संख्या बढ़ गई. एनसीआरबी ने 2014 में ऐसे किसानों, जो भूमिहीन हैं, को खेतिहर मज़दूर बताया है. हालांकि, एनसीआरबी का मानना है कि नए आंकड़ों की विश्वसनीयता की जांच नहीं की (शेष पृष्ठ 2 पर)

स्वामीनाथन आयोग के सुझावों पर अमल क्यों नहीं

भूमि सुधार

- सीलिंग सरप्लस और बंजर भूमि का वितरण.
- मुख्य कृषि भूमि और जंगल कॉरपोरेट क्षेत्र को ग़ैर कृषि प्रयोजनों के लिए देने पर रोक.
- आदिवासियों और चरवाहों को जंगल में चराई का अधिकार.
- एक राष्ट्रीय भूमि उपयोग सलाहकार सेवा की स्थापना.
- कृषि भूमि की बिक्री विनियमित करने के लिए एक तंत्र की स्थापना

आत्महत्या कैसे रुकेगी

- सस्ता स्वास्थ्य बीमा प्रदान करें, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को पुनर्जीवित करें.
- माइक्रोफाइनांस नीतियों का पुनर्गठन, जो आजीविका वित्त के तौर पर काम करें.
- सस्ती क़ीमत, सही समय-स्थान पर गुणवत्ता युक्त बीजों और अन्य सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करें.
- कम जोखिम और कम लागत वाली प्रौद्योगिकी, जो किसानों को अधिकतम आय प्रदान करने में मदद कर सके.
- जीवन रक्षक फसलों के मामले में बाज़ार हस्तक्षेप योजना की आवश्यकता.
- अंतरराष्ट्रीय मूल्य से किसानों की रक्षा के लिए आयात शुल्क पर तेजी से कार्रवाई की आवश्यकता. (शेष पृष्ठ 2 पर)

सरकार चाहे जिसकी हो, अगर इसी लक्ष्य पर काम होता रहा, तो आने वाले समय में इस देश में जय किसान की जगह एक था किसान का नारा गढ़ा जाना तय है.

सरेया अख्तियार की सूनी गलियां बिहार के हर गांव की यही कहानी है | P-3

विशेष पैकेज में कई झोल हैं | P-4

उत्तर प्रदेश : बर्बर लाठीचार्ज से ज़िंदा हो उठी कांग्रेस | P-6

किसानों की आत्महत्या राष्ट्रीय मुद्दा क्यों नहीं

पृष्ठ 1 का शेष

तक कोई राहत नहीं मिली है. वर्धा ज़िले के ही अष्टा गांव निवासी समीर तावड़े के पिता गजानंद तावड़े ने भी 2010 में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी. समीर के मुताबिक, 2010 में फसल बर्बाद होने और कर्ज न चुका पाने की वजह से उसके पिता ने आत्महत्या की, लेकिन आज तक उसे एक पैसे का न तो मुआवजा मिला और न किसी तरह की सरकारी मदद. समीर बताता है कि उसके गांव में पिछले चार वर्षों में चार किसान आत्महत्या कर चुके हैं. महाराष्ट्र के मराठवाड़ा के आठ ज़िलों में बीते वर्ष यानी 2014 में 574 किसानों ने आत्महत्या की, वहीं 2015 के अप्रैल माह तक दो सौ से ज़्यादा किसान आत्महत्या कर चुके हैं.

पिछले 25 सालों में कांग्रेस की सरकार रही, भाजपा की रही और अन्य दलों की भी रही. किसानों की आत्महत्या दर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा कि केंद्र या राज्य में किसकी सरकार है. और, किसी सरकार को भी यह सोचने की फुर्सत नहीं मिली कि आख़िर इस विकराल समस्या का स्थायी समाधान क्या हो सकता है? यूपीए ने 65,000 करोड़ रुपये के किसान कर्ज माफ़ करने की घोषणा की, जिसका फ़ायदा शायद ही उन किसानों को मिला हो, जो सही मायनों में हक़दार थे. बाद में स्वामीनाथन आयोग बना (देखें बाक्स). आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी, सुझाव दिए और उन सुझावों को चुनावी जुमलों के तौर पर खूब इस्तेमाल भी किया गया. लोकसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री पद के भाजपा उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने ज़ोर-शोर से कहा कि लागत का 50 फ़ीसद किसानों को अलग से एमएसपी के तौर पर दिया जाएगा. उनकी सरकार भी बन गई, लेकिन अभी तक उनकी घोषणा और स्वामीनाथन आयोग के सुझावों पर कोई अमल नहीं हो सका है.

दिसंबर, 2014 में ख़बर आई कि आईबी ने केंद्र सरकार को एक रिपोर्ट दी है, जिसमें बताया गया है कि कैसे महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक एवं पंजाब में किसान आत्महत्या का ट्रेंड बढ़ता जा रहा है. कहा गया कि यह रिपोर्ट राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्रा और कृषि मंत्रालय भेजी गई थी. रिपोर्ट में बताया गया कि आत्महत्या की वजह कमज़ोर मानसून, बढ़ता कर्ज, कम उपज, कमज़ोर सरकारी खरीद और फसल क्षति है. यह रिपोर्ट मानव जनित कारणों में प्राइसिंग पॉलिसी और अपर्याप्त मार्केटिंग सुविधा को किसानों की समस्याओं के लिए ज़िम्मेदार बताती है. रिपोर्ट साफ़ तौर पर बताती है कि सरकारी राहत पैकेज से भी किसानों का भला नहीं होने वाला, क्योंकि ज़्यादातर किसान साहूकारों से कर्ज लेते हैं, जो 24 से लेकर 50 फ़ीसद तक ब्याज वसूलते हैं, जिसका कोई समाधान ऐसे आर्थिक राहत पैकेज नहीं दे सकते.

अब सवाल यह है कि ऐसी रिपोर्ट मिलने के बाद क्या मौजूदा केंद्र सरकार कोई ठोस कृषि या किसान कल्याण नीति बनाएगी, जिससे इस समस्या का स्थायी समाधान निकल सके या फिर कृषि मंत्रालय का नाम किसान कल्याण मंत्रालय कर देने मात्र से समाधान हो जाएगा? मौजूदा सरकार आने के बाद भी किसानों की आत्महत्या का सिलसिला रुक नहीं रहा है. संसद में दी गई जानकारी के मुताबिक, वर्ष 2014 के अप्रैल माह तक महाराष्ट्र में 204, तेलंगाना में 69, गुजरात, केरल एवं आंध्र प्रदेश में तीन-तीन किसानों ने आत्महत्या की. हालांकि, कई सामाजिक संगठनों ने इसे आंकड़ों की बाजीगरी बताया. वरिष्ठ पत्रकार पी साईनाथ ने कहा है कि किसानों की आत्महत्या के आंकड़े कम करके बताए जा रहे हैं, ऐसा एनसीआरबी (नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो) द्वारा आंकड़े एकत्र करने के तरीके में बदलाव की वजह से है (देखें बाक्स).

बहरहाल, किसान आत्महत्या जैसी गंभीर समस्या की वजहों और इसे लेकर देश भर के किसान संगठनों की प्रतिक्रियाओं को जानना ज़रूरी है. यह फरवरी को ऐसे क़रीब सौ परिवारों को लेकर जंतर-मंतर पहुंची. संगठन ने अरुण जेटली को पत्र लिखकर मिलने की अपील भी की, लेकिन समय नहीं मिल सका. संगठन की मांग है कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक लागत का 50 फ़ीसद उन्हें बतौर एमएसपी मिले और साथ ही ऐसे परिवारों को दस लाख रुपये का मुआवज़ा भी दिया जाए. संगठन की योजना है कि इस मुद्दे पर देश के विभिन्न हिस्सों और प्रत्येक राज्य की राजधानी में आंदोलन चलाया जाए, ताकि लोगों को इस समस्या के बारे में पता चल सके. चौथी दुनिया ने भारतीय किसान यूनियन (राकेश टिकैत) के नेता राकेश टिकैत से भी बातचीत की. उनका कहना था कि जब तक फसलों के उचित दाम नहीं मिलेंगे, तब तक आत्महत्या होती रहेगी. हम सरकार से लगातार यह मांग कर रहे हैं कि वह किसानों को फसल का उचित मूल्य देने की व्यवस्था करे. हम इसके लिए लगातार लड़ाई लड़ते रहेंगे.

ज़ाहिर है, वक्त आ गया है कि भारतीय संसद किसानों और कृषि क्षेत्र से संबंधित पिछले 25 वर्षों में अपनाई गई नव-उदारवादी आर्थिक नीतियों की समीक्षा करे, क्योंकि यही नीतियां बढ़ते कृषि संकट के लिए ज़िम्मेदार हैं, इन्हीं की वजह से देश में लाखों किसानों ने आत्महत्या की और अभी भी आत्महत्या का दौर जारी है. क्यों नहीं केंद्रीय स्तर पर आत्महत्या पीड़ित परिवारों का बकाया कर्ज माफ़ करने के लिए केरल की तरह कर्ज सहायता कमीशन गठित किया जाना चाहिए? क्यों नहीं यह नियम बने कि मेहनतकश किसानों, बटाईदारों एवं खेतिहर मज़दूरों को खेती के लिए ब्याज मुक्त कर्ज दिया जाए और अन्य किसानों से चार प्रतिशत से ज़्यादा ब्याज न वसूला जाए? क्या यह ज़रूरी नहीं है कि भूमिहीन मज़दूरों के लिए मनरेगा के तहत कम से कम 200 दिनों का रोज़गार मिले, न्यूनतम 300 रुपये दैनिक मज़दूरी मिले और मनरेगा को पूरे देश में लागू किया जाए?

लेकिन, सबसे बड़ा सवाल सरकार की नीति और नीयत का है. कृषि क्षेत्र को लेकर सरकार की नीति और नीयत को अगर समझना है, तो एक और आंकड़ा देखिए. आज़ादी के बाद शुरुआती सालों में जीडीपी में कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी 53.1 फ़ीसद थी. 60 वर्षों बाद यह घटकर 13 फ़ीसद रह गई. वाजपेयी सरकार के कार्यकाल में योजना आयोग ने विजन-2020 बनाया था, जिसके मुताबिक, 2020 तक जीडीपी में कृषि (किसानी) योगदान कम करके छह फ़ीसद करने का लक्ष्य तय किया गया था. यानी सरकार चाहे जिसकी हो, अगर इसी लक्ष्य पर काम होता रहा, तो आने वाले समय में इस देश में जय किसान की जगह एक था किसान का नारा गढ़ा जाना तय है. ■

shashishekhar@chauthiduniya.com

समीर तावड़े

रेखा वाडगुडे

एनसीआरबी के आंकड़ों की सच्चाई कुछ और है

पृष्ठ 1 का शेष

जा सकी है. फिर सवाल यह भी है कि जहां आत्महत्या की घटनाएं होती हैं, वहां के स्थानीय अधिकारी, खासकर पुलिस विभाग के लोग क्या किसान आत्महत्या के मामले उचित तरीके से दर्ज करते हैं? एनसीआरबी के 2014 के आंकड़े बताते हैं कि पश्चिम बंगाल, राजस्थान और बिहार में किसी किसान ने आत्महत्या नहीं की. ग़ौरतलब है कि एनसीआरबी के पास आत्महत्या से जुड़ी दो कैटेगरी हैं, एक स्व-रोज़गार (खेती) और दूसरी स्व-रोज़गार (अन्य). उदाहरण के लिए छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में किसानों की आत्महत्या (खेती) का आंकड़ा कम हो रहा है, जबकि अन्य कैटेगरी में बढ़ रहा है. यही मध्य प्रदेश में हुआ, जहां किसान आत्महत्या के 82 मामले घटे, वहीं अन्य कैटेगरी में 236 मामलों की वृद्धि हुई है. ■

किसानों की दुर्दशा पर नेताओं ने जो कहा...

किसानों को खुद अपना बचाव करने दें. अगर फसल बर्बाद होती है, तो वे खुद सोचेंगे कि क्या करना है. मर रहे हैं, तो मरने दें. जो खेती कर सकेगा, करेगा और जो नहीं कर सकेगा, नहीं करेगा.

-संजय धोत्रे, भाजपा सांसद, अकोला, महाराष्ट्र.

फसल बर्बाद होने से कोई भी आत्महत्या नहीं कर रहा है. मध्य प्रदेश में किसान व्यक्तिगत समस्याओं की वजह से आत्महत्या कर रहे हैं.

-कैलाश विजयवर्गीय, भाजपा महासचिव.

आत्महत्या करने वाले लोग डरपोक और अपराधी होते हैं, भारतीय क़ानून में आत्महत्या अपराध है.

-ओम प्रकाश धनकड़, कृषि मंत्री, हरियाणा.

दिल्ली में अपने घर के पौधों को मैं अपने मूत्र से सींचता हूं. यह मुफ्त की खाद है. यह तरीका किसानों को बेहतर पौधा उपजाने में मदद करेगा.

-नितिन गडकरी, केंद्रीय मंत्री.

सरकार के पास किसानों की आत्महत्या रोकने का कोई विकल्प नहीं है.

-एकनाथ खड़से, कृषि मंत्री, महाराष्ट्र.

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार, कृषि क्षेत्र से जुड़े लोगों की आत्महत्या के कारणों में ऋण ग्रस्त होना, फसल न होना या खराब हो जाना, सूखा आदि तो हैं ही, साथ ही पारिवारिक समस्याएं, बीमारी, नशे की लत, बेरोज़गारी, संपत्ति विवाद, व्यवसायिक या रोज़गार संबंधी समस्या, प्रेम प्रसंग के मामले, बांझपन एवं नपुंसकता, विवाह न होना या विवाह विच्छेद, दहेज समस्या, सामाजिक प्रतिष्ठा में कमी आदि कारण भी जुड़े हैं.

-राधा मोहन सिंह, केंद्रीय कृषि मंत्री.

किसान संगठन क्या कहते हैं

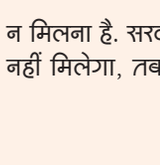

हम किसान आत्महत्या का मुद्दा पूरे देश में ले जाएंगे और प्रत्येक राज्य की राजधानी में आंदोलन करेंगे. हमारी मांग है कि किसानों को सस्ती खाद, सस्ती बिजली और सस्ता कर्ज मिले और प्रत्येक मृतक के परिवार को दस लाख रुपये का मुआवज़ा मिले.

-हन्नान मोल्ला, अखिल भारतीय किसान सभा.

किसानों की दुर्दशा का मुख्य कारण फसल का उचित मूल्य न मिलना है. सरकार से हमारी लड़ाई इसी बात को लेकर है. जब तक उचित मूल्य नहीं मिलेगा, तब तक आत्महत्या को नहीं रोका जा सकता है.

-राकेश टिकैत, भारतीय किसान यूनियन.

भी जानना ज़रूरी है कि किसान आंदोलन चलाने वाले किसान नेता आख़िर ऐसा क्या काम कर रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, जिससे यह समस्या एक राष्ट्रीय मुद्दा बन सके. इस बारे में जब चौथी दुनिया ने अखिल भारतीय किसान सभा के नेता हन्नान मोल्ला से बातचीत की, तो उन्होंने बताया कि उनका संगठन पिछले कुछ समय में देश के ऐसे 500 किसान परिवारों से मिल चुका है, जिनके किसी न किसी सदस्य ने फसल बर्बादी या कर्ज की वजह से आत्महत्या कर ली. हन्नान साहब बताते हैं कि हमने उन परिवारों से मिलकर जानकारियां जुटाईं और उसे राष्ट्रीय स्तर पर उठाने का फ़ैसला किया. इसी कड़ी में किसान सभा 10 एवं 11

स्वामीनाथन आयोग के सुझावों पर अमल क्यों नहीं

पृष्ठ 1 का शेष

किसानों की प्रतिस्पर्धा

- न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के कार्यान्वयन में सुधार. धान और गेहूं के अलावा अन्य फसलों के लिए भी न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था की जानी चाहिए.
- न्यूनतम समर्थन मूल्य उत्पादन की औसत लागत की तुलना में कम से कम 50 फ़ीसद अधिक होना चाहिए.
- ऐसे बदलाव की ज़रूरत है, जो घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय बाज़ार के लिए स्थानीय उत्पाद की ग्रेडिंग, ब्रांडिंग, पैकेजिंग और विकास को बढ़ावा दे.

चौथी दुनिया
हिंदी का पहला साप्ताहिक अखबार

वर्ष 07 अंक 26
दिल्ली, 31 अगस्त–06 सितंबर 2015

RNI-DELHIN/2009/30467

संपादक
संतोष भारतीय

संपादक समन्वय
डॉ. मनीष कुमार

एडिटर (इंवेस्टिगेशन)
प्रभात रंजन दीन

सहायक संपादक
सरोज कुमार सिंह (बिहार-झारखंड)
सरयू भवन, वेस्ट बोरिंग केनाल रोड,
हरीलाल स्वीट्स के निकट, पटना-800001
फोनः 0612 3211869, 09431421901

मैसर्स अंकुश पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक व प्रकाशक रामपाल सिंह भदौरिया द्वारा जागरण प्रकाशन लिमिटेड डी 210-211 सेक्टर 63 नोएडा उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं के- 2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001 से प्रकाशित

संपादकीय कार्यालय
के-2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001
कैंप कार्यालय एफ-2, सेक्टर -11, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश-201301

फोन न.
संपादकीय 0120-6451999, 6450888
विज्ञापन व प्रसार 022-42296060, +91-8451050786, +91-9266627379
फैक्स न. 0120-2544378

पृष्ठ-16+4 (बिहार-झारखंड, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड)

चौथी दुनिया में छपे सभी लेख अथवा सामग्री पर चौथी दुनिया का कॉपीराइट है. बिना अनुमति के किसी लेख अथवा सामग्री के पुनः प्रकाशन पर क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी.

समस्त कानूनी विवादों का क्षेत्राधिकार दिल्ली न्यायालयों के अधीन होगा.

कोई भी नेता कुछ नहीं करता, हर कोई अपने लिए राजनीति करता है. चाचा जी (अब्दुल गफूर) हर चुनाव में वोट देने गांव आते थे और बाहर से ही चले जाते थे. किसी को कुछ कहने की हिम्मत नहीं पड़ती थी.

–महमूद आलम, ग्रामीण

इस गांव के लोगों को सरकार और किसी भी नेता से कोई उम्मीद नहीं है. गांव के लोग अपने दम पर अपना विकास करने में भरोसा रखते हैं.

–शमीम आलम, ग्रामीण

सरेया अख्तियार की सूनी गलियां

बिहार के हर गांव की यही कहानी है

बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर मीडिया में भले ही तूफान मचा हो, रेडियो और अख़बारों में अंधाधुंध प्रचार हो रहा हो, लेकिन सारण के गांवों में चुनाव को लेकर कोई विशेष उत्साह नहीं है. बिहार के लोग राजनीतिक तौर पर परिपक्व हैं. वे किसी के झांसे में नहीं आते, वे नेताओं के वादों–आश्वासनों की सच्चाई भलीभांति समझते हैं. वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैकेज, नीतीश कुमार के सुशासन और लालू यादव के सोशल जस्टिस की असलियत जानते हैं. वे इससे भी वाकिफ हैं कि बिहार में सरकारें चलती कैसे हैं. पैकेज, सुशासन और सोशल जस्टिस की ऊहापोह के बीच चौथी दुनिया की टीम एक भूतपूर्व मुख्यमंत्री के गांव पहुंची. यह गांव गोपालगंज ज़िले के बरौली विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है. हमने लोगों से बातचीत कर वहां की हालत और समस्याओं का जायजा लिया.

मनीष कुमार

सरेया अख्तियार गांव में सन्नाटा पसरा है, सड़कें सूनी पड़ी हैं, घरों के दरवाजे दिन में भी बंद रहते हैं. गांव के ज़्यादातर लोग अब यहां नहीं रहते. रोजी–रोटी की तलाश में कोई दिल्ली में है, तो कोई सूरत में, तो कोई विदेश में. जिस तरह यह गांव बाहर से नीरस नज़र आता है, ठीक वैसी ही निराशा विधानसभा चुनाव को लेकर यहां के लोगों में है. सरकार, राजनीतिक दलों एवं नेताओं की विश्वसनीयता इस कदर ख़त्म हो चुकी है कि लोगों को उनसे कोई उम्मीद तक नहीं बची है. इस गांव के लोग अपना मुकद्दर अपने हाथों से लिख रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और अपना भविष्य संवार रहे हैं. इस इलाके के ज़्यादातर गांवों की यही कहानी है. इलाके की ज़मीनी सच्चाई जानने के बाद नेताओं के चुनावी जुमलों और आश्वासनों पर हंसी आती है. उन ज्ञानी विश्लेषकों की बातें हवा–हवाई सी लगती हैं, जो कहते हैं कि प्रजातंत्र एवं चुनाव के ज़रिये सामाजिक न्याय और आर्थिक विकास हो सकता है. सारेया अख्तियार गांव बिहार के गोपालगंज ज़िले के मांझागढ़ ब्लॉक में है. यह मुस्लिम बाहुल्य इलाका है. सरेया में भी मुस्लिम आबादी अच्छी–खासी है. क़रीब साढ़े तीन सौ परिवारों और 2,000 के आसपास आबादी वाला यह एक बड़ा गांव है. यहां के ज़्यादातर मकान पक्के हैं, एक सुंदर मस्जिद भी है. दोपहर (ज़ोहर) की नमाज के वक्त इसमें दस–बाहर लोग ही नज़र आए. गांव में काफी साफ़–सफाई है, गंदगी का नाम–ओ–निशान नहीं है, गांव की गलियों में गाय–बकरियां या मुर्गे घूमते नज़र नहीं आते. इलाके के दूसरे गांवों की तरह यहां ग़रीबी नहीं है. यह गांव बाहर काफी समृद्ध नज़र आता है. दरअसल, इसके पीछे किसी सरकारी इमदाद का कमाल नहीं है. हक़ीक़त यह है कि इस गांव में जो कुछ अच्छा है, वह यहां के लोगों की मेहनत की बदौलत है. और, जो कुछ नहीं है, वह सरकारों की लापरवाही और उदासीनता का प्रमाण है.

इस गांव के ज़्यादातर युवा बाहर रहते हैं. गांव में कुछ ही लोग बचे हैं, जो सरकारी नौकरी करते हैं या फिर उनका अपना व्यवसाय है. इस गांव में ऐसा कोई परिवार नहीं है, जिसका कोई सदस्य बाहर नौकरी न करता हो. इस गांव के 150 से ज़्यादा युवक सऊदी अरब, अमीरात एवं कुवैत में मज़दूरी करते हैं और क़रीब 150 लोग सूरत की विभिन्न कपड़ा मिलों में काम करते हैं. इसके अलावा रोज़गार के लिए यहां के नौजवानों का देश के अन्य शहरों की ओर भी पलायन हुआ है. वे साल–दो साल में गांव आते हैं और फिर वापस चले जाते हैं. परिवार उनके द्वारा भेजे गए पैसों से ही चलता है. उन्हीं के पैसे से गांव का हर मकान पक्का हो गया. घर–गांव में पैसा तो आ गया, लेकिन उसकी एक बड़ी क़ीमत हर रोज़ चुकानी पड़ती है. घर और गांव की रौनक चली गई है. रोजी–रोटी के सवाल ने परिवार को परिवार नहीं रहने दिया. बूढ़े मां–बाप बिना बेटे के, पत्नी बिना पति के और छोटे–छोटे बच्चे बिना पिता के जीवन बिता रहे हैं. इस गांव में ऐसा कोई नहीं है, जिसके चेहरे पर शिकन न हो, ज़िंदगी से शिकायत न हो. गांव वाले बताते हैं कि पंद्रह–बीस साल पहले इस गांव में एक–दो घर छोड़कर सारे मकान कच्चे थे, लेकिन रौनक भरपूर थी, तब यह एक ज़िंदा गांव था.

यहां के जो लोग जीविका के चलते देश के विभिन्न हिस्सों में या विदेश गए, वे अकुशल (अनस्किल्ड) हैं, मजदूरी करते हैं. दूसरी समस्या यह है कि इन सबके परिवार यहीं गांव में रहते हैं. कुछ लोग ईद–बकरीद में आते हैं, लेकिन परिवार के साथ त्योहार मनाना सबके नसीब में नहीं होता. इन सवालों पर गांव के बुजुर्गों की आंखें डबडबा जाती हैं. सच है, भला कौन नहीं चाहता कि त्योहार में पूरा परिवार साथ हो. रुंधी आवाज़ में एक बुजुर्ग ने कहा कि अगर यहीं कोई रोज़गार या नौकरी होती, तो बच्चे क्यों बाहर जाकर दुनिया की ठोकरें खाते. सारण के ज़्यादातर मुस्लिम बाहुल्य गांवों की यही कहानी है. परिवार गांव में रहता है, लेकिन परिवार चलाने वाला काफी दूर. हर राजनीतिक दल के नेता–कार्यकर्ता इन गांवों में वोट मांगने आते हैं. सबको इन परिवारों का दु:ख–दर्द मालूम है. उन्हें यह भी पता है कि बिहार के नौज़वान रोजी–रोटी की ख़ातिर घर–गांव छोड़कर बाहर जाने के लिए क्यों मजबूर हैं. लेकिन, देश की राजनीतिक जमात इतनी बेरहम और अमानवीय हो चुकी है कि उसका ध्यान इस तरफ़ जाता ही नहीं है. लगता है, यह बिहार का नसीब बन गया है. चुनाव होते रहेंगे, सरकारें बनती–गिरती रहेंगी, मुख्यमंत्री बनते–बदलते रहेंगे और नौजवान घर–गांव छोड़कर रोजी–रोटी के लिए अन्यत्र पलायन करते रहेंगे.

शिक्षा व्यवस्था के नाम पर इस गांव में सिर्फ़ एक प्राइमरी स्कूल है, जो डेढ़ साल पहले खुला है. पढ़ाई जारी रखने के लिए गांव के बच्चों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है. सबसे नज़दीक कॉलेज 10 किलोमीटर की दूरी पर है. ऐसा नहीं है कि यहां के लोग पढ़े–लिखे नहीं हैं. इस गांव के कई लोग पढ़ाई करके भी अपनी किस्मत बनाई. उन्होंने अलीगढ़ विश्वविद्यालय एवं जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) में शिक्षा हासिल की और आईपीएस बने, बनारस विश्वविद्यालय में लेक्चरर बने, पत्रकार बने. लेकिन, ऐसी किस्मत सरेया अख्तियार के सभी बच्चों की नहीं है. सवाल यह है कि अगर स्कूल नहीं होंगे, तो बच्चों का भविष्य कैसे सुरक्षित होगा? इलाके में बड़े किसान नहीं हैं, इसलिए जीविका के लिए खेतों पर निर्भर नहीं हो सकते. इस गांव तक पहुंचने के लिए पक्की सड़क तक नहीं है. गांव वाले बताते हैं कि 1992 में यहां के लिए सड़क का प्रस्ताव मंजूर हुआ था, तबसे लेकर अब तक बिहार में हर विचारधारा और मॉडल की सरकार आई, लेकिन इस गांव के हिस्से में सड़क नहीं आई. दबी ज़ुबान से, लेकिन शिकायती लहजे में एक बुजुर्ग ने कहा कि यह गांव मुसलमानों का है, इसलिए सड़क नहीं बनी. गांव के बगल से गुज़रने वाली सारी सड़कें बन गईं, लेकिन सारेया की नहीं. एक और समस्या है बिजली. सरकार चाहे जो दावा करे, लेकिन हक़ीक़त यह है कि सरेया और आसपास के गांवों में सिर्फ़ पांच–छह घंटे बिजली रहती है, वह भी दिन के समय. शाम होते ही बिजली चली जाती है और पूरी रात गांव वालों को अंधेरे में गुज़ारनी पड़ती है.

- पूर्व मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर का गांव है सरेया अख्तियार
- गांव के 150 से ज़्यादा युवक सऊदी अरब एवं कुवैत में मज़दूरी करते हैं.
- गांव में सिर्फ़ एक प्राइमरी स्कूल है, नज़दीकी कॉलेज 10 किमी दूर है.
- गांव तक पहुंचने के लिए पक्की सड़क तक नहीं है.

सरकार की तरफ़ से पेयजल की कोई व्यवस्था नहीं है. ज़मीन का पानी दूषित हो चुका है. गांव वालों ने पानी की जांच कराई, तो पता चला कि गांव और इलाके का पानी मनुष्यों के पीने लायक नहीं है. जो ग़रीब हैं, वे उसी दूषित पानी को पीने के लिए मजबूर हैं. जिनके पास पैसा है, वे आरओ लगाकर पानी पी रहे हैं. दूषित पानी से बीमारियां भी होती हैं, लेकिन इतने बड़े गांव में अस्पताल तो दूर, एक डिस्पेंसरी तक नहीं है. इलाज कराने के लिए लोगों को 20 किलोमीटर दूर सीवान जाना पड़ता है. महिलाओं के लिए प्रसव केंद्र भी नहीं है. ग़रीब परिवारों की महिलाएं घर में प्रसव के लिए मजबूर हैं. लोगों ने बताया कि आशा नामक एक एजेंसी है, जो ऐसे वक्त में महिलाओं को अस्पताल लेकर जाती है, लेकिन उसके लिए भी पैसे देने पड़ते हैं. सरकार की इस आपराधिक लापरवाही ने सारेया अख्तियार के लोगों को एकजुट कर दिया है. अगर किसी की तबीयत बिगड़ती है, तो गांव के लोग मदद करने में पीछे नहीं रहते. पूरा गांव खड़ा हो जाता है. हिंदुस्तान के गांव वाले भी अजीब होते हैं, हर कमी को अपनी ताकत बना लेते हैं.

राजनीतिक तौर पर इस इलाके में सरेया अख्तियार का काफी महत्व है. यह बिहार के बड़े नेता अब्दुल गफूर का गांव है. वह एक जाने–माने स्वतंत्रता सेनानी थे. स्वतंत्रता संग्राम के दौरान वह कई बार जेल गए. फिर कांग्रेस पार्टी में सक्रिय रहे. वह बिहार के अकेले मुस्लिम मुख्यमंत्री (जुलाई, 1973 से अप्रैल, 1975) रहे. वह राजीव गांधी के मंत्रिमंडल में कैबिनेट मिनिस्टर रहे. आज उनके घर पर ताला लगा हुआ है. गांव में उनके रिश्तेदार आज भी हैं. सोचने वाली बात यह है कि जब एक पूर्व मुख्यमंत्री–केंद्रीय मंत्री के गांव की हालत ऐसी है, तो बिहार के बाकी गांवों की तस्वीर कैसी होगी? न स्कूल, न स्वास्थ्य सेवाएं, न पानी, न बिजली और न युवाओं के लिए रोज़गार का कोई अवसर. स्वर्गीय अब्दुल गफूर के रिश्तेदार 82 वर्षीय महमूद आलम कहते हैं कि कोई भी नेता कुछ नहीं करता, हर कोई अपने लिए राजनीति करता है. चाचा जी (अब्दुल गफूर) हर चुनाव में वोट देने गांव आते थे और बाहर से ही चले जाते थे. किसी को कुछ कहने की हिम्मत नहीं पड़ती थी. अब्दुल गफूर की मृत्यु 2004 में हुई. उसके बाद उनके पोते राजनीति में आए. वह कांग्रेस पार्टी में हैं, लेकिन न कभी चुनाव जीत सके और न सरेया अख्तियार के लोगों का दिल. अब्दुल गफूर के एक अन्य रिश्तेदार (चचेरे पोते) शमीम आलम कहते हैं कि इस गांव के लोगों को सरकार और किसी भी नेता से कोई उम्मीद नहीं है. गांव के लोग अपने दम पर अपना विकास करने में भरोसा रखते हैं.

बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं. हर राजनीतिक दल अपने–अपने हिसाब से लोगों को भ्रमित करने के लिए उन बातों को तरजीह दे रहा है, जिनसे वोट मिलते हैं. कोई स्पेशल पैकेज का लालच देकर, तो कोई सुशासन का झांसा देकर, तो कोई ग़रीब–गुरबों को बोलने की ताकत देने की बात कहकर लोगों को बहलाने–फुसलाने की कोशिश कर रहा है. जनता त्रस्त है. सरकार है, जो समस्याओं को समझना नहीं चाहती. योजनाएं हैं, जो जनता तक पहुंचती नहीं. सरकारी तंत्र से जुड़े ऊपर से लेकर नीचे तक के लोग आलीशान गाड़ियों में हॉर्न बजाते हुए ऐसे गुज़रते हैं, मानो जनता को चिढ़ा रहे हों. अगले एक महीने में बिहार में फिर से जाति और धर्म का खेल होगा. टेलीविजन पर ज्ञान बांटने वाले बड़ी–बड़ी बातें करेंगे, प्रजातंत्र के ज़रिये सामाजिक और आर्थिक विकास की रटी–रटाई बातें दोहराएंगे. लेकिन, इस चुनाव में भी वही होगा, जो हमेशा से होता रहा है. बिहार, खासकर उसके गांवों की असल समस्या पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोज़गार के अवसर की है. लोगों का भरोसा वर्तमान तंत्र से उठता जा रहा है. यह एक चिंताजनक स्थिति है.

सरेया अख्तियार बिहार के उन चंद गांवों में से है, जहां के लोगों ने अपनी मेहनत से अपनी तकदीर संवारी है. इस गांव के लिए सरकार ने कुछ नहीं किया. मुश्किल से चार–पांच लोगों के पास सरकारी नौकरी है, बाकी पूरा गांव किसी सरकारी मदद के बगैर संघर्ष कर रहा है. देश चलाने वाले नेताओं और अधिकारियों से पूछा जाना चाहिए कि देश में चल रही सौ से अधिक योजनाओं से क्या हासिल हो रहा है? क्या देश के युवाओं की यही नियति है कि वे अपना घर–परिवार और गांव छोड़कर ज़िंदगी भर दर–दर की ठोकरें खाते फिरें. क्या यही है वह विकास का मॉडल, जिसमें कोई अपने बूढ़े माता–पिता की सेवा न कर सके, पत्नी–बच्चों के साथ जीवन न बिता सके और घर चलाने वाला सिर्फ़ छुट्टियां मनाने के लिए अपने घर–गांव जाएगा? यह सारेया अख्तियार की खुशकिस्मती है कि यहां के लोग अपने घर वालों को पैसे भेज पाते हैं. बिहार में ऐसे कई गांव हैं, जहां के हज़ारों–लाखों लोग रोजी–रोटी के लिए घर–परिवार छोड़कर देश के दूसरे शहरों में या विदेश तो चले गए हैं, लेकिन वे पैसे कमाकर भेजने की स्थिति में नहीं हैं. गांव में उनके परिवारों का क्या हाल होता होगा, यह सोचकर भी दिल दहल जाता है. सरकार चलाने और विकास का आख़िर यह कैसा मॉडल है, जिसमें ज़िंदगी ही सजा बन गई है? ■

manishbph244@gmail.com

मुस्लिम बाहुल्य सीमांचल के विधानसभा क्षेत्र ओवैसी के सॉफ्ट टारगेट हैं. किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, कटिहार एवं सुपौल में मुस्लिम आबादी के मद्देनज़र ओवैसी की पार्टी एक खास योजना पर काम कर रही है, जिसकी कमान कोचाधामन से राजद के विधायक रहे अख्तरुल ईमान को सौंपी गई है. ओवैसी के अनुसार, दो महीने पहले अख्तरुल ईमान ने उनसे मिलकर सीमांचल की बदहाली और जातीय–सामाजिक परिस्थितियों की चर्चा की, उसके बाद ही किशनगंज में जनसभा करने का निर्णय लिया गया.

विशेष पैकेज में कई झोल हैं

> प्रधानमंत्री ने चुनाव के ऐन पहले पैकेज घोषित कर अपने सबसे प्रखर राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी और सूबे में जनता परिवार महा-गठबंधन के नेता नीतीश कुमार और लालू प्रसाद को राजनीतिक तौर पर बचाव की मुद्रा में ला खड़ा किया है. चुनावी माहौल से विकास जैसे सकारात्मक मुद्दे गायब जैसे हो गए थे और धन-जाति जैसे नकारात्मक तत्व हावी होते जा रहे थे.

सुकांत

बिहार विधानसभा चुनाव की बाजी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी (एनडीए) के पक्ष में सबसे बड़ा दांव खेल गए और उन्होंने विशेष पैकेज जैसा तुरुप का पत्ता चल दिया. उन्होंने आरा में आयोजित सरकारी समारोह (जिसे सार्वजनिक सभा जैसी शक्ल दी गई) में बिहार के लिए शाही दाता के अंदाज़ में एक लाख 65 हज़ार करोड़ रुपये के विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा कर दी है. उन्होंने बताया कि इस पैकेज में एक लाख पच्चीस हज़ार करोड़ रुपये नई सहायता है, जबकि 40,657 करोड़ रुपये राज्य में पहले से जारी, मगर अधूरी योजनाओं के हैं. पैकेज में वे सभी योजनाएं शामिल हैं, जो पुराने एनडीए के साथ-साथ यूपीए सरकारों के दौर से चली आ रही हैं. प्रधानमंत्री द्वारा घोषित पैकेज में आधारभूत संरचना विकसित करने के कार्यक्रमों पर खासा ज़ोर है. केवल सड़क (उच्च पथ के साथ-साथ ग्रामीण सड़क) के विकास एवं विस्तार की योजनाओं के लिए 68,543 करोड़ रुपये से अधिक रकम तय गई है यानी पैकेज की एक तिहाई से अधिक रकम. इसमें 54,713 करोड़ रुपये राजमार्गों के लिए हैं, जबकि 13,620 करोड़ रुपये से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ढाई हज़ार किलोमीटर ग्रामीण सड़कें बनेंगी.

प्रधानमंत्री ने चुनाव के ऐन पहले पैकेज घोषित कर अपने सबसे प्रखर राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी और सूबे में जनता परिवार महा-गठबंधन के नेता नीतीश कुमार और लालू प्रसाद को राजनीतिक तौर पर बचाव की मुद्रा में ला खड़ा किया है. चुनावी माहौल से विकास जैसे सकारात्मक मुद्दे गायब जैसे हो गए थे और धन-जाति जैसे नकारात्मक तत्व हावी होते जा रहे थे. लेकिन, नरेंद्र मोदी द्वारा विशेष पैकेज की घोषणा से विकास इस अविकसित राज्य के विधानसभा चुनाव का केंद्रीय मुद्दा बनता दिख रहा है. महा-गठबंधन एवं उसके नेताओं नीतीश कुमार और लालू प्रसाद को इस घोषणा ने नई चुनौती दी है. हालांकि, नीतीश कुमार एवं और उनके समर्थक कह सकते हैं कि नीतीश बिहार में परिचय के मोहताज नहीं हैं, उनकी छवि विकास-पुरुष की है और उन्हें लोगों ने दस वर्षों से देखा है. पर यह भी सही है कि राज्य में कोई नया पूंजी निवेश नहीं है, रोज़गार के कोई बड़े साधन नहीं हैं. मनरेगा जैसे कार्यक्रमों का धन कम हो जाने से अकुशल मज़दूरों पर बेरोज़गारी की गहरी मार पड़ी है. लेकिन, बिहार की जनता में विकास की चाहत नीतीश कुमार की राजनीति ने जगाई है. हो सकता है कि कुछ तबके नाराज़ हों, पर बिहार को नीतीश से विकासोन्मुखी राजनीति की ही उम्मीद है. यह भी सही है कि नरेंद्र मोदी की इस तुरुप चाल ने लालू-नीतीश की जोड़ी को कुछ हद तक सकते में डाल दिया है. अब उन्हें अपनी राजनीति नए सिरे से विकास की राजनीति से जोड़नी होगी और मतदाताओं को बताना होगा कि नरेंद्र मोदी की घोषणा में नया कुछ भी नहीं है. चुनावी वादे पूरे करने को लेकर भाजपा का रिकॉर्ड बहुत विश्वसनीय नहीं रहा है. यदि लालू-नीतीश की जोड़ी बिहार का चुनाव अभियान नरेंद्र मोदी से हटाकर अपने एजेंडे पर लाना चाहती है, तो उसे यह और ऐसी कई राजनीतिक कसरतें करनी होंगी.

बिहार में चुनावी बढ़त बनाने के लिए नरेंद्र मोदी ने एक दूसरा खेल भी खेला. हालांकि, उसकी घोषणा मुजफ्फरपुर रैली (25 जुलाई) में की गई थी. उस रैली में उन्होंने बिहार में पूंजी निवेश करने वालों को पंद्रह प्रतिशत की कर राहत और उद्योग लगाने वालों को पंद्रह प्रतिशत डिप्रीशिएशन भत्ता देने का वादा किया था. उक्त घोषणाओं को लेकर केंद्र सरकार ने बीते 18 अगस्त को अधिसूचना जारी कर दी है, जिसके मुताबिक, पटना, नालंदा, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, गया, जहानाबाद, औरंगाबाद, नवादा, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, पूर्णिया, कटिहार, अररिया, जमुई, लखीसराय, सुपौल एवं मुजफ्फरपुर को पिछड़ा ज़िला घोषित कर उनमें उक्त कर राहत का लाभ देने का निर्देश दिया गया है. केंद्र सरकार ने तय किया है कि विनिर्माण (मैन्युफैक्चरिंग) इकाई, भवन निर्माण, प्लांट एवं मशीनरीज के निवेशकों को डिप्रीशिएशन पर छूट मिलेगी. आयकर की धाराओं के तहत निवेशकों को यह कर राहत चालू वित्तीय वर्ष (एक अप्रैल 2015) से शुरू हो गई है और इसका लाभ 31 मार्च, 2020 तक मिलेगा. ऐसे लाभ आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना को मिल रहे हैं.

प्रधानमंत्री के इस विशेष आर्थिक पैकेज में कई झोल हैं. इसमें समय जैसा कोई तत्व घोषित नहीं है. राज्य में सड़कें बननी हैं, बनेंगी भी, लेकिन कब? बक्सर में बिजलीघर कितने दिनों में स्थापित हो जाएगा और बिहार को कबसे बिजली मिलने लगेगी? बरौनी तेलशोधक कारखाने में काम कब शुरू होगा? पांच सौ करोड़ रुपये में कैसे व कितने दिनों में विक्रमशिला विश्वविद्यालय बन जाएगा या आईआईएम बोधगया का भवन इतने ही पैसों में तैयार हो जाएगा और ज़मीन के लिए धन कहां से आएगा? पटना में नया हवाई अड्डा बनाने और तीन पुराने एवं महत्वपूर्ण हवाई अड्डों के नवीकरण के लिए 2,700 करोड़ रुपये की रकम क्या पर्याप्त है? पर्यटन विभाग में कौन-कौन सर्किट बनेंगे और उनके लिए अतिरिक्त रकम की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं? यह सब कोई नहीं बता रहा है. ऐसे कई सवाल हैं, जिनके जवाब किसी के पास नहीं हैं. पैकेज में पुरानी परियोजनाओं की भरमार है, जैसे गंगा, कोसी, सोन पर महासेतु की घोषणा. मोकामा में रेल-सड़क सेतु के निर्माण और बोधगया में आईआईएम सेंटर की स्थापना आदि घोषणाएं बजट की हैं. बक्सर विद्युत परियोजना भी पहले की है. पूसा स्थित राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देने पर बिहार और केंद्र सरकार में आठ माह पहले सहमति बन चुकी है. वस्तुत: विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा बाज़ीगरी ज़्यादा है, बिहार को नई सौगात कम. नीतीश कुमार सही कहते हैं कि यह री-पैकेजिंग है. यह चुनाव का दौर है, जिसमें घोषणाओं के ज़रिये वोटों का जुगाड़ किया जाता है. क्या नरेंद्र मोदी यही कर रहे हैं? इतना तो तय है कि वह बिहार के हिस्से की घोषित पुरानी योजनाओं की पैकेजिंग कर रहे हैं.■

feedback@chauthiduniya.com

ओवैसी ने उड़ाई लालू-नीतीश की नींद

नीरज सिंह

आॅल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सीमांचल के मुस्लिम बाहुल्य किशनगंज में एक बड़ी सभा करके बिहार, खासकर महा-गठबंधन की राजनीति में भूचाल ला दिया. राजद, जद (यू) एवं कांग्रेस के नेता सकते में हैं. वैसे तो सामाजिक इंसाफ फ्रंट-बिहार के बैनर तले मुख्य मुद्दा सीमांचल की बदहाली को बनाया गया, लेकिन छिपा एजेंडा अल्पसंख्यकों के

जज्बात उभारना था. ओवैसी ने सीमांचल की बदहाली के लिए नीतीश कुमार, राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस को ज़िम्मेदार बताते हुए भाजपा के ख़िलाफ़ जद (यू), राजद एवं कांग्रेस महा-गठबंधन के समानांतर खुद को खड़ा करने की कोशिश की. चुनाव के ऐन मौक़े पर ओवैसी का दौरा काफी गंभीरता से लिया जा रहा है. मुस्लिम बाहुल्य सीमांचल के विधानसभा क्षेत्र ओवैसी के सॉफ्ट टारगेट हैं. किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, कटिहार एवं सुपौल में मुस्लिम आबादी के मद्देनज़र ओवैसी की पार्टी एक खास योजना पर काम कर रही है, जिसकी कमान कोचाधामन से राजद के विधायक रहे अख्तरुल ईमान को सौंपी गई है. ओवैसी के अनुसार, दो महीने पहले अख्तरुल ईमान ने उनसे मिलकर सीमांचल की बदहाली और जातीय-सामाजिक परिस्थितियों की चर्चा की, उसके बाद ही किशनगंज में जनसभा करने का निर्णय लिया गया. भाषण के दौरान ओवैसी ने विधानसभा चुनाव लड़ने के मुद्दे पर अपने पत्ते नहीं खोले, लेकिन उनके हाव-भाव से साफ़ हो गया कि वह बहुत जल्द चुनावी बिसात पर अपने मोहरे सजाने वाले हैं. स्पष्ट है कि सीमांचल मेंएआईएमआईएम की मौजूदगी से महा-गठबंधन को बड़ा झटका लग सकता है. सूत्र बताते हैं कि ओवैसी बिहार में 25-30 मुस्लिम बाहुल्य विधानसभा क्षेत्रों में अपने प्रत्याशी उतार सकते हैं. ओवैसी का यह प्लान नीतीश और लालू के लिए ख़तरे की घंटी है. ओवैसी साफ़ कहते हैं कि मुसलमान किसी पार्टी के बंधुआ मज़दूर नहीं हैं. अवाम अपने हिसाब से तय कर लेगी कि चुनाव में किसके साथ जाना है.■

feedback@chauthiduniya.com

मेरे एजेंडे में दलित, अति पिछड़े एवं पसमांदा मुसलमान हैं

एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवालों के बेबाक जवाब दिए.

आरोप है कि बिहार विधानसभा चुनाव में आप सेक्युलर ताकतों को कमज़ोर करने वाले हैं...

हम समाज के सबसे पिछड़े दलित, अति पिछड़े एवं अल्पसंख्यकों को साथ लेकर चल रहे हैं. क्या उनकी आवाज़ उठाना सेक्युलर ताकतों को कमज़ोर करना है.

जद (यू) का कहना है कि हम लोग सेक्युलर ताकतों को इकट्ठा कर रहे हैं और सेक्युलरिज्म के नाम पर भाजपा से अलग हुए...

गोधरा में जब ट्रेन जली, तब रेल मंत्री कौन था?

क्या आपके एजेंडे में सिर्फ़ मुसलमान हैं?

मेरे एजेंडे में दलित, अति पिछड़े एवं पसमांदा मुसलमान हैं. मैं इन सबको एक प्लेटफॉर्म पर लाने का काम कर रहा हूं.

आरोप है कि आप सिर्फ़ मुसलमानों को अपनी पार्टी का टिकट देते हैं...

महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मैंने 12 में से छह हिंदू उम्मीदवार उतारे थे, जिनमें चार ओबीसी और दो दलित थे.

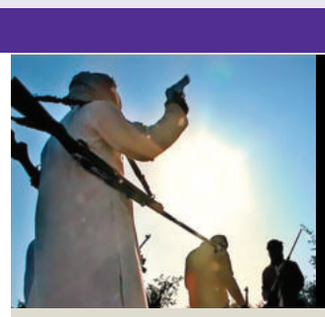

ऐसे हैं आपके वर्तमान विधायक...

चौथी दुनिया ब्यूरो

feedback@chauthiduniya.com

राजनीति का अपराधीकरण बिहार में पिछले कई चुनावों से एक अहम मुद्दा रहा है. एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म (एडीआर) ने बिहार इलेक्शन वाच के साथ मिलकर पिछले विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों और चुनाव जीतकर आने वाले विधायकों की पृष्ठभूमि की समीक्षा तैयार की थी. यहां 2010 में जीतकर आए विधायकों की पृष्ठभूमि का एक खाका प्रस्तुत किया जा रहा है, ताकि मतदाताओं को भी पता चले कि उन्होंने कैसी छवि वाले उम्मीदवारों को अपना वोट दिया था.

एडीआर ने वर्ष 2010 में चुनकर आए 242 विधायकों के हलफनामों का अध्ययन किया. इन 242 विधायकों में से 141 यानी राज्य के 58 प्रतिशत विधायकों के ख़िलाफ़ आपराधिक मामले लंबित हैं. पिछली विधानसभा में यह संख्या 117 यानी 50 प्रतिशत थी. अब एक नज़र 2010 में गंभीर आपराधिक मामलों वाले उम्मीदवारों पर डालते हैं. एडीआर ने हत्या, हत्या का प्रयास, अपहरण, फिरौती, चोरी, ग़ैर इरादतन हत्या आदि को गंभीर मामलों की श्रेणी में रखा है. पिछले विधानसभा चुनाव में 467 उम्मीदवार ऐसे थे, जिनके ख़िलाफ़ गंभीर आपराधिक मामले थे और उनमें से 85 उम्मीदवार चुनाव जीतने में कामयाब रहे. अगर आपराधिक पृष्ठभूमि वाले 141 विधायकों का पार्टीवार ब्यौरा पेश किया जाए, तो जनता दल (यूनाइटेड) के 58, भाजपा के 13, राजद के तीन और लोजपा और कांग्रेस के एक-एक विधायक आपराधिक पृष्ठभूमि के थे. यहां ये आंकड़े भ्रामक हो सकते हैं, क्योंकि ये तो जीते हुए उम्मीदवार हैं. राजनीतिक दल राजनीति का अपराधीकरण ख़त्म करने के प्रति कितने गंभीर हैं, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि तक़रीबन सभी पार्टियों ने एक ही अनुपात में आपराधिक छवि या पृष्ठभूमि वाले लोगों को अपना उम्मीदवार बनाया था. एडीआर ने टॉप-20 शीर्षक से एक ऐसी सूची तैयार की है, जिसमें उन विधायकों को शामिल किया गया है, जिनके ख़िलाफ़ हत्या, हत्या का प्रयास, फिरौती, अपहरण, डकैती जैसे गंभीर मामले हैं.■

क्रम	विधायक का नाम	विधानसभा क्षेत्र	पार्टी	कुल मुक़दमे	आईपीसी की धाराएं
1.	प्रदीप कुमार	वारिसगंज (नवादा)	जद (यू)	18	27
2.	शिवजी राय	मधुबनी (पू. चंपारण)	जद (यू)	08	14
3.	नरेंद्र कुमार पांडेय	तरारी (भोजपुर)	जद (यू)	13	23
4.	नरेंद्र कुमार सिंह	मतिहानी (बेगूसराय)	जद (यू)	15	13
5.	सतीश चंद्र दूबे	नरकटियागंज (प. चंपारण)	भाजपा	07	11
6.	अमरेंद्र कुमार पांडेय	कूचायकोट (गोपालगंज)	जद (यू)	11	07
7.	आनंदी प्रसाद यादव	सिकटी (अररिया)	भाजपा	05	07
8.	मनोरंजन सिंह	एकमा (सारण)	जद (यू)	18	06
9.	मोहम्मद तौसीफ आलम	बहादुरगंज (किशनगंज)	कांग्रेस	06	06
10.	अवनीश कुमार सिंह	चिरैया (पू. चंपारण)	भाजपा	07	05
11.	चितरंजन कुमार	अरवल	भाजपा	05	05
12.	केदार नाथ सिंह	बनियापुर (सारण)	राजद	04	05
13.	विक्रम कुंवर	रघुनाथपुर (सीवान)	भाजपा	04	05
14.	अशोक कुमार यादव	केवोती (दरभंगा)	भाजपा	01	05
15.	सरफराज आलम	जोकीहाट (अररिया)	जद (यू)	08	04
16.	नीरज कुमार सिंह	छातापुर (सुपौल)	जद (यू)	06	04
17.	सुरेंद्र प्रसाद यादव	बेलागंज (गया)	राजद	06	04
18.	अनिल सिंह	हिसुआ (नवादा)	भाजपा	06	04
19.	जनार्दन सिंह सिग्रीवाल	छपरा (सारण)	भाजपा	05	04
20.	राज किशोर*	पूर्णिया	भाजपा	04	04

* एक महिला ने राज किशोर पर बलात्कार का आरोप लगते हुए 2011 में उनकी हत्या कर दी थी.

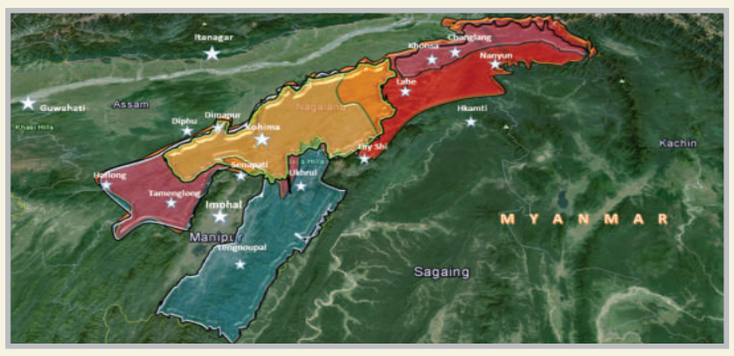

एक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि मुइवा की ग्रेटर नगालैंड की मांग क्या पूरे नगा समुदाय की मांग है? क्या इससे सारे नगा खुश हैं? नगाओं में और भी कई सशस्त्र विद्रोह करने वाले संगठन हैं. मुइवा का प्रमुख विरोधी गुट है, एनएससीएन (के), जिसकी कमान खापलांग के हाथ में है. वह पिछले दिनों मणिपुर में हुए हमले, जिसमें सेना के 18 जवान शहीद हुए थे, का ज़िम्मेदार है. इतना ही नहीं, एमएनपीएफ (मणिपुर नगा पीपुल्स फ्रंट), जिसकी सशस्त्र शाखा एमएनपीए (मणिपुर नगा पीपुल्स आर्मी) है, का मानना है कि इस समझौते के पीछे केंद्र सरकार का उद्देश्य एनएससीएन (आईएम) के दोनों नेताओं इशाक चिसी और टीएच मुइवा की ढलती उम्र का फ़ायदा उठाना भर है.

नगा शांति समझौता

शांति की कोशिश कहीं अशांति न फैला दे

एस. बिजेन सिंह

तीन अगस्त को केंद्र सरकार और नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नगालैंड (एम) के सचिव थुइंगालैंग मुइवा के बीच एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर हुए. इस युद्ध विराम समझौते की नींव वर्ष 1997 में पूर्व प्रधानमंत्री आईके गुजराल के कार्यकाल में पड़ी थी, लेकिन बीते 18 वर्षों में इस संदर्भ में कोई खास प्रगति नहीं हुई, लेकिन अब यह समझौता ज़मीन पर उतरता नज़र आ रहा है. केंद्र सरकार ने इस समझौते को एक ऐतिहासिक क़दम बताया है और मुइवा भी इससे खुश नज़र आ रहे हैं. 15 अगस्त को जब मुइवा दीमापुर में स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में शरीक होने पहुंचे, तो वहां नगाओं ने उनका ज़ोर-शोर से स्वागत किया. लेकिन, सवाल यह है कि क्या केंद्र सरकार नगाओं की मांगें पूरी करके इस क्षेत्र में शांति स्थापित कर पाने में सफल होगी? मुइवा की मांग एक वृहद नगालैंड की है, जिसमें पड़ोसी राज्यों मसलन, मणिपुर के चार ज़िले, अरुणाचल प्रदेश के दो ज़िले और असम के दो पहाड़ी ज़िले भी शामिल हैं. इस मामले को लेकर तीनों राज्यों में विरोध के स्वर शुरू से उठते आ रहे हैं. सबसे ज़्यादा विरोध मणिपुर में हुआ, क्योंकि उसके चार ज़िले इसमें शामिल हैं. ज्ञात हो कि 18 जून, 2011 को मणिपुर में इस मामले को लेकर हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान 18 लोग मारे गए थे.

यह जानना बहुत ज़रूरी है कि इस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट में कौन-कौन से बिंदु शामिल किए गए हैं, जिन पर दोनों पक्षों में सहमति कायम हुई है. लेकिन, यह बात किसी को भी नहीं मालूम. इसके बारे में देश के गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजु तक नहीं बता पा रहे हैं. जब असम, अरुणाचल एवं मणिपुर के मुख्यमंत्रियों से इस बारे में सवाल किए गए, तो वे आश्चर्यचकित रह गए और उनसे कोई जवाब देते नहीं बना. इस समझौते का नगाओं ने तो खूब स्वागत किया, लेकिन अन्य समुदायों के लोगों ने तीनों राज्यों में इसके विरोध में जमकर प्रदर्शन किया और अपने राज्य की सीमा की अखंडता न टूटने देने का नारा लगाया. सवाल यह उठता है

कि आख़िर केंद्र सरकार इस एग्रीमेंट को गुप्त क्यों रखना चाहती है? गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने सिर्फ़ इतना बताया कि इस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट में पड़ोसी राज्यों का पूरा ख्याल रखा गया है.

एक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि मुइवा की ग्रेटर नगालैंड की मांग क्या पूरे नगा समुदाय की मांग है? क्या इससे सारे नगा खुश हैं? नगाओं में और भी कई सशस्त्र विद्रोह करने वाले संगठन हैं. मुइवा का प्रमुख विरोधी गुट है, एनएससीएन (के), जिसकी कमान खापलांग के हाथ में है. वह पिछले दिनों मणिपुर में हुए हमले, जिसमें सेना के 18 जवान शहीद हुए थे, का ज़िम्मेदार है. इतना ही नहीं, एमएनपीएफ (मणिपुर नगा पीपुल्स फ्रंट), जिसकी सशस्त्र शाखा एमएनपीए (मणिपुर नगा पीपुल्स आर्मी) है, का मानना है कि इस समझौते के पीछे केंद्र सरकार का उद्देश्य एनएससीएन (आईएम) के दोनों नेताओं इशाक चिसी और टीएच मुइवा की ढलती उम्र का फ़ायदा उठाना भर है, यह जनता के हित में नहीं है और नगा जनता इन दोनों नेताओं से ऊपर है. एनएससीएन (आईएम) नगाओं का एकमात्र प्रतिनिधि नहीं है. इस संगठन का कहना है कि छह दशकों से चला आ रहा नगाओं का संघर्ष केवल आर्थिक पैकेज या ग्रेटर ऑटोनोमी के लिए नहीं है. इस लंबी समयावधि में बड़ी संख्या में नगाओं ने अपनी जान गंवाई. इसलिए इस समझौते के अंतिम रूप लेने से पहले आईएम के नेताओं को सोचना चाहिए. कैसे माना जा सकता है कि यह समझौता पूरे नगा समुदाय के लिए है? संगठन का यह भी मानना है कि नगाओं की मांग तब पूरी होगी, जब सारे सशस्त्र गुट एकजुट होकर लड़ें.

नगा एक जनजाति समुदाय है, जो पूर्वोत्तर भारत और उत्तर-पश्चिमी बर्मा के इलाकों में बसा हुआ है. पूर्वोत्तर यानी मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश एवं असम कुछ हिस्से. नगाओं की भाषा नगामीज और अंग्रेजी है. अलग-अलग स्थानों पर अलग-अलग उपभाषाएं बोली जाती हैं, जो कि 36 से भी ज़्यादा हैं, लेकिन संपर्क भाषा नगामीज है. वर्ष 2012 तक नगालैंड में आधिकारिक तौर पर 17 नगा जनजातियों को मान्यता दी चुकी है. 99 प्रतिशत नगा ईसाई धर्म मानते हैं और कुछ लोग प्रकृति पूजा (एनीमिज्म) करते हैं. शिकार करना और जानवरों के सिर काटकर एकत्र करना नगाओं की संस्कृति का हिस्सा है. एनएससीएन (आईएम)

नगाओं के सशस्त्र संगठन

एनएससीएन (आईएम) : वर्ष 1980 में स्थापित इस संगठन के पास साढ़े चार हज़ार लड़ाके हैं. इसके नेता हैं इशाक चिसी और टीएच मुइवा. यह संगठन नगाओं के प्रभुत्व और एकीकरण के लिए काम करता है और नए प्रस्तावित राज्य को नगालिम नाम देना चाहता है.

एनएससीएन (के) : इस संगठन का मुखिया खापलांग शिलांग संधि-1975 (नगा नेशनल काउंसिल और भारत सरकार के बीच हुआ समझौता) का विरोध करता था. दरअसल, पहले एनएससीएन नामक एक ही संगठन था, जो 1988 में दो हिस्सों में विभाजित हो गया, एनएससीएन (के) उसका दूसरा हिस्सा है, जिसकी कमान खापलांग के हाथ में है. दोनों गुटों यानी एनएससीएन (आईएम) और एनएससीएन (के) के बीच भी वर्चस्व की लड़ाई है.

एमएनपीएफ : एमएनपीएफ (मणिपुर नगा पीपुल्स फ्रंट) मणिपुर से संचालित होता है. यह मणिपुरी नगाओं का एक उग्रपंथी संगठन है. यह 2013 में बना था, जिसके अध्यक्ष जोहन फ्रांसिस कशुंग हैं. उनका मानना है कि नगाओं की मांग तब पूरी होगी, जब सारे सशस्त्र विरोधी गुट एकजुट होकर लड़ें.

एमएनपीए : एमएनपीए (मणिपुर नगा पीपुल्स आर्मी) एमएनपीएफ की सशस्त्र शाखा है. दोनों संगठन एक-दूसरे के पूरक हैं. दोनों का मकसद और कार्यप्रणाली समान है. एमएनपीए के महासचिव हैं विल्सन टाव.

“हम इस शांति समझौते का स्वागत करते हैं. लेकिन, यदि मणिपुर की सीमा को लेकर कोई ख़तरा पैदा होगा, तो मेरी सरकार केंद्र और एनएससीएन (आईएम) के बीच हो रही इस शांति वार्ता को स्वीकार नहीं करेगी.
–ओक्रम इबोबी सिंह, मुख्यमंत्री, मणिपुर.

“हम नगा मुद्दों को निपटाने के लिए इस समझौते का स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि यह विवाद ख़त्म हो. लेकिन, यदि असम को एक इंच ज़मीन भी नुक़सान होगा, तो उसका विरोध ज़रूर करूंगा. इस समझौते के बिंदुओं को सबसे छिपाया गया.
– तरुण गोगोई, मुख्यमंत्री, असम.

“इस समझौते के बारे में टेलीविजन के माध्यम से पता चला. अगर राज्य सरकार के सुझाव केंद्र को मंजूर हैं, तो यह समझौता स्वीकार करूंगा.
–नबम टूकी, मुख्यमंत्री, अरुणाचल प्रदेश.

और केंद्र सरकार के बीच जारी यह वार्ता तभी शांति वार्ता कहलाएगी, जब पड़ोसी राज्यों का समुचित ख्याल रखा जाएगा, अन्यथा आशंका यह भी जताई जा रही है कि खूनखराबे की स्थिति पैदा हो सकती है. इसलिए केंद्र सरकार को एक ऐसा रास्ता निकालना चाहिए, जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटने पाए. ■

sbijensngh@gmail.com

तस्वीरों में यह सप्ताह

फोटो–प्रभात पाण्डेय

साल भर हम अपने दैनिक कार्य निपटाने में व्यस्त रहते हैं, लेकिन प्रत्येक वर्ष अगस्त के पहले पखवाड़े में हम स्वतंत्रता दिवस के रंगों में सराबोर होने के लिए तैयार हो जाते हैं. हम हर साल आज़ादी का जश्न मनाते हैं, इस साल भी मनाया. बीते 15 अगस्त को आज़ादी की 69वीं वर्षगांठ मनाई गई. इस अवसर पर राष्ट्रपति भवन रंग-बिरंगी रोशनी से जगमगा उठा. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मुख्य झंडारोहण कार्यक्रम में देश के लगभग सभी शीर्षस्थ नेता मौजूद थे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्राचीर से देशवासियों को संबोधित किया. अपने भाषण के बाद वह कार्यक्रम में मौजूद बच्चों से भी मिले. ■

केंद्र की बेरुख़ी के बावजूद हम आगे बढ़ रहे हैं : रावत

नमो लहर में राज्य की सभी पांच सीटें जीतने के बाद मोदी टीम अति उत्साह में आ गई थी. मोदी लहर को बेअसर करते हुए पूरे उत्तराखंड में भाजपा के क़दमों पर मुख्यमंत्री हरीश रावत ने जो ब्रेक लगाया, उससे भाजपाध्यक्ष अमित शाह की रणनीति को भारी धक्का पहुंचा. पेश हैं, हरीश रावत से चौथी दुनिया संवाददाता राजकुमार शर्मा से हुई बातचीत के प्रमुख अंश:

केंद्र सरकार के कोप का शिकार आप हो रहे हैं और तंगहाली जनता को झेलनी पड़ रही है, इस पर आपका क्या कहना है?

जनता से अपने मन की बात कहना और जनता से उसके मन की बात सुनना, दोनों में ज़मीन-आसमान का अंतर है. हम जन-जन से उनका दु:ख-दर्द शेयर करते हैं. झूठ बोलकर जनता को ज़्यादा दिनों तक छला नहीं जा सकता. एक दिन झूठ का मुंह काला हो जाता है. राज्य के लोगों की जागरूकता के कारण संघ परिवार द्वारा प्रायोजित मोदी छल बेअसर रहा. उन्हें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हिमालय से जो हवा बहती है, वह सर्वत्र असर डालती है. जनता है, सब जानती है.

इन दिनों आबकारी घोटाला सुर्खियों में है, क्या कहना चाहेंगे?

केवल ख्याली पुलाव परोस कर जनता का पेट नहीं भरा जा सकता. कांग्रेस का हाथ सदैव ग़रीब-कमज़ोर आदमी के साथ रहा है. आज सत्ता में बैठे लोग झूठ बोलकर चोरी के बाद सीनाजोरी करने पर उतारू हैं. देश की जनता पंद्रह महीनों से अच्छे दिन आने का इंतज़ार कर रही है. अच्छे दिन ज़रूर आए हैं, लेकिन मुट्ठी भर व्यापारिक घरानों के लिए. काले धन पर सरकार कहती कुछ है और करती कुछ है, जिससे दाल में काला होने का संकेत साफ़ नज़र आता है. सरकार की कथनी-करनी में अंतर है. किसानों और सैनिकों के मुद्दों पर जो रोल प्रधानमंत्री मोदी अदा कर रहे हैं, वह लालकिले से उनके भाषण के बाद सबको मालूम हो चुका है. हमारी सरकार बेदाग है और हमारी नीतियां जनहितैषी हैं. भाजपा हमें बदनाम करने की चाहे जितनी कोशिश कर ले, जनता खुद सब देख रही है. आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि विश्व प्रसिद्ध हरिद्वार कुंभ मेले को मिलने वाली मदद से केंद्र सरकार हाथ खींच रही है. राज्य के तीर्थों के मार्ग भारी बारिश के चलते तबाह हो गए हैं, लेकिन राज्य के भाजपा सांसदों ने प्रधानमंत्री का रुख देखते हुए मौन धारण कर रखा है. यह सुशासन है कि कुशासन? जनता ही खुद तय कर देगी.

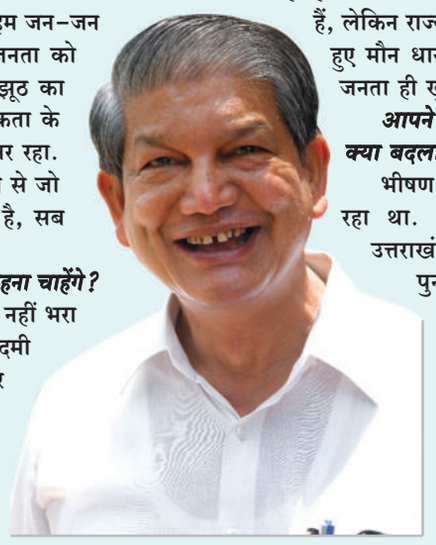

आपने जब उत्तराखंड की सत्ता संभाली, तबसे अब तक क्या बदलाव देख रहे हैं?

भीषण आपदा से त्रस्त राज्य आगे बढ़ने के लिए छटपटा रहा था. आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि उत्तराखंड दिनोंदिन आगे बढ़ रहा है. पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण की प्रक्रिया जारी है, बहुत कुछ अभी किया जाना बाकी है. मुझे विश्वास है कि इसके लिए हमें केंद्र सरकार से आर्थिक सहायता ज़रूर मिलेगी. इस साल अब तक लगभग सात लाख तीर्थ यात्री और तीन करोड़ से अधिक कांवड़िए उत्तराखंड आए. बीते वर्ष बड़ी संख्या में पर्यटक हमारे दूरदराज के पर्यटन स्थलों तक पहुंचे. देवभूमि पर सस्ती थाली योजना शुरू हो गई है. राज्य के लोग एक सुरक्षित उत्तराखंड का संदेश देश-दुनिया को देने में सफल हुए हैं. केंद्र सरकार की बेरुखी से देश की जनता अब धीरे-धीरे परिचित हो रही है. फिर भी हम पर भरोसा करके लोग लगातार आ रहे हैं. यह इस बात का संकेत है कि उत्तराखंड में दम है, का संदेश कायम है. ■

feedback@chauthiduniya.com

कांग्रेसियों पर हुए लाठीचार्ज ने राज्य में मरणासन्न कांग्रेस की खाल में थोड़ी गर्मी पैदा की और दिल्ली में अब तक कांग्रेस के साथ अठखेलियां करती रही समाजवादी पार्टी का असली चेहरा उजागर किया. समाजवादी सरकार की पुलिस ने कांग्रेसी नेताओं को दौड़ा–दौड़ाकर पीटा. पुलिस ने लाठी चलाने में यह ध्यान रखा कि समाजवादी पार्टी से किस कांग्रेसी नेता के अंतरंग रिश्ते हैं और कौन कांग्रेसी नेता समाजवादी पार्टी के नेताओं को नहीं सुहाते. लिहाजा, राज बब्बर, निर्मल खत्री जैसे नेता पुलिस से पिटे, लेकिन प्रमोद तिवारी पुलिस के प्रकोप से बचे रहे. दर्जनों कांग्रेसी जख्मी हुए.

उत्तर प्रदेश

बर्बर लाठीचार्ज से ज़िंदा हो उठी कांग्रेस

प्रभात रंजन दीन

उत्तर प्रदेश सरकार के नाकारेपन, बदहाल क़ानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार और भ्रष्ट मंत्रियों एवं नौकरशाहों को सत्ता से मिल रहे संरक्षण के ख़िलाफ़ राजधानी लखनऊ में प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसियों पर हुए जबरदस्त लाठीचार्ज ने राज्य में मरणासन्न कांग्रेस की खाल में थोड़ी गर्मी पैदा की और दिल्ली में अब तक कांग्रेस के साथ अठखेलियां करती रही समाजवादी पार्टी का असली चेहरा उजागर किया. समाजवादी सरकार की पुलिस ने कांग्रेसी नेताओं को दौड़ा–दौड़ाकर पीटा. पुलिस ने लाठी चलाने में यह ध्यान रखा कि समाजवादी पार्टी से किस कांग्रेसी नेता के अंतरंग रिश्ते हैं और कौन कांग्रेसी नेता समाजवादी पार्टी के नेताओं को नहीं सुहाते. लिहाजा, राज बब्बर, निर्मल खत्री जैसे नेता तो पुलिस से पिटे, लेकिन प्रमोद तिवारी पुलिस के प्रकोप से बचे रहे. दर्जनों कांग्रेसी जख्मी हुए. कुछ पुलिस वालों को भी चोटें आईं. पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य, पूर्व केंद्रीय मंत्री श्रीप्रकाश जायसवाल, कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव मधुसूदन मिस्त्री, प्रदेश अध्यक्ष निर्मल खत्री, सांसद राज बब्बर एवं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रीता बहुगुणा जोशी समेत कई नेताओं की सांकेतिक गिरफ्तारी भी हुई.

विधानसभा का मानसून सत्र बाधित करने के लिए संपूर्ण विपक्ष ने 17 अगस्त को सरकार की घेराबंदी कर दी थी. बहुजन समाज पार्टी एवं भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा के दोनों सदनों के अंदर हंगामा किया और सदन का कामकाज दिन भर बाधित रखा. विधानसभा के बाहर कांग्रेस ने जबरदस्त

कांग्रेस के मुद्दे

- ध्वस्त क़ानून व्यवस्था.
- यादव सिंह के भ्रष्टाचार पर पर्दा डालने की कोशिश.
- बिजली की दरों में भारी बढ़ोत्तरी और आपूर्ति में भीषण कटौती.
- पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक तनाव पर सरकार की लापरवाही.
- सरकारी नौकरियों में हो रही भर्तियों में घोटाले, अल्पसंख्यकों को सिर्फ़ तीन फ़ीसद प्रतिनिधित्व.
- बुनकरों और मदरसों की खस्ता हालत, दलित छात्रों की छात्रवृत्ति.

प्रदर्शन किया और पूरा शहर अस्त–व्यस्त कर दिया. राज्य सरकार की नाकामियों के ख़िलाफ़ कांग्रेस ने विधानसभा घेरने की योजना बनाई थी. कांग्रेसियों ने पहले विधानसभा के बाहर धरना दिया. पुलिस द्वारा खदेड़े जाने के बाद वे लखनऊ स्थित लक्ष्मण मेला मैदान पहुंच गए, जहां कांग्रेसियों का जमावड़ा सभा में तब्दील हो गया. सभा में कांग्रेस ने अपनी 15 सूत्रीय मांगें सामने रखते हुए सरकार विरोधी नारे लगाए. इसके बाद कांग्रेसियों का जत्था दोबारा विधान भवन जाने लगा. पुलिस ने उसे रोकने की कोशिश की और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया. जब कांग्रेसी नहीं रुके, तो पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया. जवाब में कांग्रेसियों ने भी पथराव किया. कांग्रेस ने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश में क़ानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, राज्य सरकार नोएडा के भ्रष्ट चीफ इंजीनियर यादव सिंह समेत कई नौकरशाहों एवं नेताओं के भ्रष्टाचार पर पर्दा डालने में लगी है, दलितों एवं महिलाओं पर अत्याचार बेतहाशा बढ़े हैं, बिजली की दरों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और कटौती भीषण हो रही है. पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक तनाव पर सरकार लापरवाही बरत रही है, सरकारी नौकरियों की भर्तियों में घोटाले हो रहे हैं, बुनकरों एवं मदरसों की हालत खस्ता है, दलित छात्रों की छात्रवृत्ति बंद कर दी गई है, किसानों का करोड़ों रुपये का गन्ना मूल्य बकाया है, लेकिन सरकार उसके भुगतान का कोई उपाय नहीं कर रही है.

कांग्रेसियों ने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का पुतला फूंकने की भी कोशिश की, लेकिन पुलिस ने पुतला छीन लिया और कांग्रेसियों को जमकर पीटा. कांग्रेसियों का गुस्सा और भड़क गया. उन्होंने लाठीचार्ज के ख़िलाफ़ निशातगंज पुल पर भी धरना दिया. कांग्रेस के प्रदर्शन के चलते शहर के मुख्य मार्ग सहित कई स्थानों की यातायात व्यवस्था चरमरा गई. विधानसभा के अंदर बसपा एवं भाजपा के विरोध और विधानसभा के बाहर कांग्रेसियों के प्रदर्शन पर सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी ने तीखी प्रतिक्रिया ज़ाहिर की. सपा प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने कहा कि विधानसभा के अंदर और बाहर विपक्ष ने जो आचरण प्रदर्शित किया, उसे कतई लोकतांत्रिक नहीं ठहराया जा सकता.■

feedback@chauthiduniya.com

मेट्रो के लिए दो सौ करोड़, बुंदेलखंड को सिर्फ़ तीन करोड़

विपक्ष के हंगामे और शोरशराबे के बीच पेश हुए अनुपूरक बजट में लखनऊ मेट्रो परियोजना के लिए 200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. सरकार ने बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र के विकास के लिए महज तीन करोड़ रुपये का प्रावधान किया है. विडंबना यह है कि जो चीनी मिलें किसानों का बकाया देने के लिए तैयार नहीं हैं, उन्हें राज्य सरकार ने 1,529 करोड़ रुपये का राहत पैकेज दिया है. डायल 100 सेवा के लिए सौ करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. अखिलेश सरकार ने आगरा में मुगल म्यूजियम की स्थापना के लिए 15 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है. इटावा में बब्बर शेर प्रजनन केंद्र फेज–2 के लिए सात करोड़ और अयोध्या एवं चित्रकूट में भजन संध्या स्थल के लिए चार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. इसी अनुपूरक बजट की आड़ में मंत्रियों एवं राज्य मंत्रियों को गाड़ियां खरीदने के लिए 40 लाख रुपये आवंटित किए गए हैं. इसी तरह विधायकों के बढ़े वेतन–भत्तों और पूर्व विधायकों के बढ़े हुए भत्तों के लिए 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.

मेरी दोस्त के रूप में नीरा

नीरा राडिया की अंतरंग दुनिया

नीरा और केएलएम के साथ अपने संबंध खराब करने की मेरी कोई मंशा नहीं थी, लेकिन एक वकील अपने क्लाइंट से मिली फीस पर ही ज़िंदा रहता है. 1997–98 में केस कोर्ट में गया, मेरा बिल क़रीब पांच करोड़ रुपये का हो गया था, लेकिन 1998 तक मुझे कुछ नहीं मिला था. नीरा ने तीन दिसंबर को मुझे केएलएम की ओर से उसे प्रेषित एक पत्र दिखाया, जिसे देखकर मैं आश्चर्यचकित रह गया. दरअसल, नीरा मेरी फीस को लेकर केएलएम से सौदेबाजी कर रही थी. उस पत्र के मुताबिक, केएलएम मुझे 55,00,000 यूएस डॉलर देने के लिए सहमत थी. इसके अलावा वह मुझे 6,82,000 पाउंड देती, यदि भारतीय कस्टम से उसका मामला पूर्णतय: सुलट जाता. मेरे स्वीकार करने पर उसने तत्काल 5,50,000 यूएस डॉलर दे दिए.

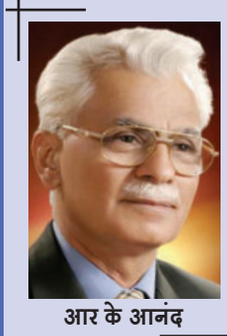

आर के आनंद

वे दोनों क्लाइंट और नीरा राडिया काफी खुश दिख रहे थे. असल में उन सबने मुझे स्टैनफोर्ड आकर इस जीत का जश्न मनाने के लिए आमंत्रित भी किया, जिसे मैंने अस्वीकार कर दिया. मुफ्त विदेशी दौरे का आमंत्रण अस्वीकार करना आसान नहीं था, लेकिन मैंने अपने व्यवसाय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए ऐसा आमंत्रण स्वीकार करना ठीक नहीं समझा. उनके लिए काम करना मेरा कर्तव्य था. मैंने अपनी पूरी ताकत लगा दी, ताकि अपने क्लाइंट्स के विमान भारत से मुक्त कराकर स्टैनफोर्ड भिजवा सकूं. इसके लिए मैंने सरकार में अपने प्रभाव का भी इस्तेमाल किया. इस केस में मिली जीत मेरे लिए बहुत बड़ी थी. भारत की ओर से किसी ने भी विमान मालिकों की दिक्कतें समझने की कोशिश नहीं की. मेरी यह सफलता मेरे आत्मविश्वास को बढ़ाने वाली थी. अब नीरा मेरे साथ काफी सहज हो गई थी. वह मेरी पारिवारिक दोस्त बन गई थी. वह तक़रीबन रोज़ाना मेरे फार्म आवास पर आने लगी थी. वह खुद मेरे घर आती थी, अपने लिए कॉकटेल बनाती थी और घंटों मेरी पत्नी से बातें करती रहती थी. वह अपनी पारिवारिक समस्याओं पर भी मुझसे बातें करती थी.

1996–97 के दौरान मैं अमेरिका से अपनी पत्नी के लिए दवाइयां मंगाता था और उसमें नीरा मेरी काफी मदद करती थी. वह अपने क्लाइंट केएलएम के ज़रिये वहां से दवाइयां सुरक्षित लाने की व्यवस्था कराती थी. नीरा मेरी बहन की तरह बन गई थी और मैं भी उसे उसी तरह मानने लगा था. यह संबंध तब और भी प्रगाढ़ हो गया, जब वह अपना घर बदल कर रसोला आ गई. एक पड़ोसी के नाते वह अक्सर मेरे घर आने लगी थी. हमने क़रीब–क़रीब हर मुद्दे पर बातचीत की. लेकिन, उन सारी बातचीतों का आधार यह होता था कि नीरा राडिया कैसे भारत की एक शक्तिशाली उद्यमी बने. वह अपने उद्देश्य को लेकर काफी स्पष्ट थी. उसमें भारत सरकार, राजनीति, नौकरशाही, नीतियों एवं विदेशी निवेश आदि के बारे में जानकारी रखने की जबरदस्त इच्छा थी. वह ऐसी जानकारियां और आंकड़े आपके सामने रख सकती थी, जो किसी एक्सपर्ट के पास ही होते हैं.

मैं समझ चुका था कि वह किसी बड़े काम के लिए तैयार है. लेकिन, काम क्या होगा, इसका मुझे पता नहीं था. उस वक्त मुझे अंदाज़ा नहीं था कि वह अपना मंसूबा पूरा करने के लिए राजनीतिक

मंच पर भी अपने पंख फैलाने वाली है. एक दिन जब मैं उसके घर पहुंचा, तो मुझे झटका लगा. मैंने देखा कि अपने फार्म हाउस पर नीरा राडिया एनडीए मिनिस्टर अनंत कुमार के साथ पश्चिमी संगीत (वेस्टर्न बॉलरूम म्यूजिक) पर डांस कर रही है.

मेरी फीस की व्यवस्था कैसे हुई

केएलएम के विमान मुक्त होकर अपनी सही जगह तक पहुंच चुके थे. लेकिन, टैक्स (कर) से जुड़ा केस लंबित था, जो अभी भी सरकार के पास जमा किया जाना बाकी था. मेरी अपनी फीस (शुल्क) भी बाकी थी. सतीश मोदी ने केएलएम के ख़िलाफ़ मुक़दमा कर दिया था और केएलएम ने भी मोदी के ख़िलाफ़ आपराधिक मुक़दमा कर दिया था. कोर्ट से मिले निर्देश के मुताबिक, सरकार के आठ करोड़ और फिक्स्ड डिपॉजिट किए हुए 4.5 करोड़ रुपये मेरी कंपनी के खाते में जमा करा दिए गए थे, ताकि वहां से उसे उचित जगह तक पहुंचाया जा सके. इस व्यवस्था

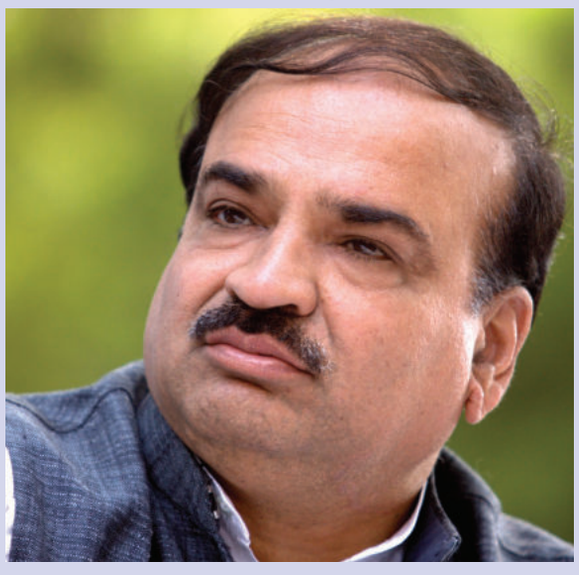

के ज़रिये केएलएम को मेरे खातों के बारे में जानकारी थी. समय–समय पर मैं नीरा को अपनी बकाया फीस के बारे में याद दिलाता रहा. यह सब केएलएम और सतीश मोदी के बीच मुक़दमेबाजी के दौरान चल रहा था. मैंने देखा कि नीरा इस सबसे अनजान बने रहना चाहती थी. इससे मैं चौंका. आख़िरकार, केएलएम के एजेंट के तौर पर उसे समय–समय पर कोर्ट से मिले निर्देशों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ब्रीफ करना चाहिए था. वह इस तरह की व्यवस्था करती भी थी, लेकिन खुद को पीछे रखते हुए. वह हमेशा अपने आपको इस सबके दौरान पृष्ठभूमि में रखती थी और फिर मुझे प्रेस के सवालों का जवाब देना पड़ता था.

उसने मुझे कभी नहीं बताया कि वह केएलएम से कितनी फीस (शुल्क) ले रही है. उसने कभी भी कोर्ट के दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर नहीं किए. वह कभी भी व्यक्तिगत रूप से कोर्ट की सुनवाई में उपस्थित नहीं हुई. मुझे बाद में महसूस हुआ कि मुझे इस सबसे पहले ही सावधान हो जाना चाहिए था. नीरा कभी भी अपना लक्ष्य नहीं भूली थी. उसका लक्ष्य था, भारतीय विमानन क्षेत्र का बादशाह बनना और इसके लिए किसी दिन उसे सतीश मोदी की सलाह और परामर्श की ज़रूरत थी. सतीश मोदी ने केएलएम के ख़िलाफ़ तो केस किया था, लेकिन नीरा के ख़िलाफ़ नहीं.

नीरा और केएलएम के साथ अपने संबंध खराब करने की मेरी कोई मंशा नहीं थी, लेकिन एक वकील अपने क्लाइंट से मिली फीस पर ही ज़िंदा रहता है. 1997–98 में केस कोर्ट में गया, मेरा बिल क़रीब पांच करोड़ रुपये का हो गया था, लेकिन 1998 तक मुझे कुछ नहीं मिला था. नीरा ने तीन दिसंबर को मुझे केएलएम की ओर से उसे प्रेषित एक पत्र दिखाया, जिसे देखकर मैं आश्चर्यचकित रह गया. दरअसल, नीरा मेरी फीस को लेकर केएलएम से सौदेबाजी कर रही थी. उस पत्र के मुताबिक, केएलएम मुझे 55,00,000 यूएस डॉलर देने के लिए सहमत थी. इसके अलावा वह मुझे 6,82,000 पाउंड देती, यदि भारतीय कस्टम से उसका मामला पूर्णतय: सुलट जाता. मेरे स्वीकार करने पर उसने तत्काल 5,50,000 यूएस डॉलर दे दिए. मध्य दिसंबर में केएलएम के कॉरपोरेट वकील ग्राम मार्सी, जॉन डेरबीशायर, नीरा और राव धीरज सिंह से अपने कार्यालय में तीन दिसंबर वाले पत्र के बारे में बातचीत के लिए मिला. मैंने बताया कि भारतीय व्यवस्था में केस सफलतापूर्वक ख़त्म होने के बाद पैसे के भुगतान की बात नहीं है. हम इस पर सहमत हुए कि मेरा पैसा दो चरणों में आएगा. लंबित भुगतान के ख़िलाफ़ तत्काल 5,50,000 यूएस डॉलर और बाकी केस ख़त्म होने पर, बिना यह देखे कि परिणाम क्या आता है.■

जारी...

(मशहूर वकील आर.के. आनंद क्लोज इंकाउंटर्स विद नीरा राडिया के लेखक हैं)

डायन अथवा डाकन का यह अभिशाप केवल झारखंड को नहीं डस रहा है, बल्कि इसकी गिरफ्त में देश का एक बड़ा हिस्सा है. उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, तमिलनाडु, असम, पश्चिम बंगाल एवं राजस्थान के पिछड़े इलाकों से ऐसी ख़बरें आएदिन सुनने को मिलती हैं. बीती 21 जुलाई को असम के सोनितपुर ज़िले के विमाजुली गांव में 63 वर्षीय मोनी ओरांग नामक वृद्धा को दो सौ से ज़्यादा लोगों की भीड़ ने घर से बाहर निकाल कर पहले उसके कपड़े फाड़े, फिर पीटने के बाद धारदार हथियार से उसका सिर कलम कर दिया.

कौन और क्यों बनाता है

21वीं सदी की डायन

केंद्रीय एवं राज्य सरकारों और ग़ैर-सरकारी संगठनों के लाख प्रयासों के बावजूद देश के एक बड़े तबके को अंधविश्वास ने इस कदर जकड़ रखा है कि वह सही-ग़लत की पहचान नहीं कर पाता और जाने-अनजाने अपराध की गिरफ्त में फंसता जा रहा है. यह अंधविश्वास समाज को खोखला कर रहा है और लोगों में भय पैदा कर रहा है. शिक्षा के व्यापक प्रचार-प्रसार के बावजूद ओझाओं, गुनियों एवं तांत्रिकों की पौ बारह है. वे अशिक्षित जनता के खून-पसीने की कमाई लूटकर मालामाल हो रहे हैं और लोग आपस में एक-दूसरे की जान के दुश्मन बने घूम रहे हैं.

महेंद्र अवधेश

अगस्त माह के पहले पखवाड़े में झारखंड एक बार फिर शर्मसार हुआ, जहां डायन होने और जादू-टोना करने के आरोप में सात महिलाओं समेत नौ लोग मौत के घाट उतार दिए गए. बीते 14 अगस्त की रात लोहरदगा ज़िले के हुदु गांव निवासी मना मुंडा एवं बुधराम उरांव नामक वृद्धों को आठ वर्षीय बालक सूरज उरांव का इलाज झाड़-फूंक के ज़रिये कर पाने में नाकाम रहने पर पंचायत ने उन्हें पीट-पीटकर मार डालने की सजा सुनाई. इससे पहले सात अगस्त की रात राजधानी रांची से 37 किलोमीटर दूर मांडर थाना अंतर्गत दक्षिण कंजिया मराय टोली नामक गांव में अंधविश्वासी जनता ने ओझा-गुनी के कहने पर पांच महिलाओं को पहले निर्वस्त्र किया, फिर पत्थरों एवं लाठी-डंडों से पिटाई कर उन्हें मौत के घाट उतार दिया. पलामू एवं गुमला ज़िलों से भी डायन करार देकर दो महिलाओं की हत्या कर देने की ख़बर है. दक्षिण कंजिया मराय टोली की घटना में पुलिस ने 25 लोगों को गिरफ्तार किया है. हुआ यह कि दो अगस्त को गांव के इस्तानिस जलहा खलखो के 13 वर्षीय बेटे विपिन की असामयिक मौत हो गई. ओझा-गुनी ने बताया कि इसके पीछे गांव की एतवारिया खलखो का हाथ है. गांव में पहले हुई कुछ अन्य मौतों के लिए भी ओझा-गुनी मारी गई महिलाओं को दोषी करार दे चुके थे. नतीजतन, पंचायत बुलाकर एतवारिया, जसिंता, तेतरी, रकिया एवं मदनी को यह सजा दी गई. जसिंता एवं मदनी की उम्र क़रीब 60 वर्ष बताई जाती है. राज्य में ऐसी यह पहली घटना नहीं है. बीते 12 मई की रात नक्सल प्रभावित ज़िले सिमडेगा के कोलेबिरा थाना अंतर्गत गांव सरईपानी में दो वृद्धाओं रतनी एवं विमला को डायन बताकर मार दिया गया. रतनी के पति हौड़ा प्रधान के अनुसार, मौक़े पर बड़ी संख्या में तीर-कमान से लैस पुरुष-महिलाएं एवं बच्चे मौजूद थे. रतनी एवं विमला को सबने पहले लात-घूंसों एवं लाठी-डंडों से पीटा और फिर चट्टानों से नीचे फेंक दिया. पुलिस भी दोनों वृद्धाओं के शव बरामद नहीं कर सकी.

डायन अथवा डाकन का यह अभिशाप केवल झारखंड को नहीं डस रहा है, बल्कि इसकी गिरफ्त में देश का एक बड़ा हिस्सा है. उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, तमिलनाडु, असम, पश्चिम बंगाल एवं राजस्थान के पिछड़े इलाकों से ऐसी ख़बरें आएदिन सुनने को मिलती हैं. बीती 21 जुलाई को असम के सोनितपुर ज़िले के विमाजुली गांव में 63 वर्षीय मोनी ओरांग नामक वृद्धा को दो सौ से ज़्यादा लोगों की भीड़ ने घर से बाहर निकाल कर पहले उसके कपड़े फाड़े, फिर पीटने के बाद धारदार हथियार से उसका सिर कलम कर दिया. इससे पहले बीती 11-12 जुलाई को ओडिशा के क्योंझर ज़िले में एक ही परिवार के पांच सदस्यों को अंधविश्वासी लोगों ने कुल्हाड़ी से काट डाला. मरने वालों में तीन बच्चे भी शामिल थे. हत्यारों का मानना था कि उक्त परिवार जादू-टोने में लिप्त था, जिसके चलते इलाके के बच्चे बीमार हो जाते हैं. इसी तरह बीती दो फरवरी को बिहार के बांका ज़िले के बौंसी थाना अंतर्गत सांगा पंचायत के आदिवासी बाहुल्य गांव पथरिया में एक वृद्धा और उसकी 40 वर्षीय बेटी को डायन करार देकर पहले गर्म सलाखों से दागा गया, फिर मल-मूत्र पिलाया गया और अर्द्धनग्न कर पीटा गया. बीते वर्ष 29-30 नवंबर को मध्य प्रदेश के बैतूल ज़िले के गांव रायसेड़ा में एक दलित महिला को जादू-टोने के शक में न सिर्फ़ लाठियों से पीटा गया, बल्कि उसे निर्वस्त्र करके गले में जूतों-चप्पलों की माला पहना कर पूरे इलाके में घुमाया गया. उसे गांव के बाहर स्थित तालाब में तीन घंटे तक खड़ा भी रखा गया.

एक जनवरी, 2011 लेकर मार्च 2014 तक देश भर में कुल 527 महिलाएं इस अंधविश्वास का शिकार बनीं. 2011 में 240, 2012 में 119, 2013 में 160 एवं 2014 के मार्च माह तक आठ महिलाएं डायन होने और जादू-टोने के आरोप में अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठीं. यह कड़वा सच स्वयं केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 25 जुलाई, 2014 को संसद में पेश अपनी रिपोर्ट में उद्घाटित किया. नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के सहारे मंत्रालय ने अपनी रिपोर्ट तो पेश कर दी, लेकिन महिलाओं पर हो रहे इस अत्याचार को रोकने के लिए उसके पास कोई ठोस योजना नहीं है. उसने इसे राज्य के तहत क़ानून व्यवस्था का मामला बताते हुए अपना पल्ला झाड़ लिया. दरअसल, अशिक्षा एवं ग़रीबी के चलते लोग कोई बीमारी होने पर पहले ओझा-गुनी के पास भागते हैं. बाद में हालत बिगड़ने पर डॉक्टर या अस्पताल की शरण लेते हैं. अगर कहीं मरीज की मौत हो जाए, तो ऐसे में ओझा-गुनी जिसकी तरफ़ इशारा कर दे, उसे डायन-टोटकेबाज कहकर सजा देना आम बात है. उसके बाल काटना, मल-मूत्र पिलाना, मुंह काला करके घुमाना, निर्वस्त्र कर पीटना समाज के लोग अपना धर्म-हक़ समझ लेते हैं. कभी-कभी तो सामूहिक दुराचार तक अंजाम दिया जाता है. बीते तीन जून को मध्य प्रदेश के शिवपुरी ज़िले की ग्राम पंचायत ठेवला अंतर्गत मजरा कैमरारा में दबंगों ने एक आदिवासी महिला पर डायन होने का आरोप लगाते हुए उसे उसके घर से खींचकर गांव के बीच स्थित चबूतरे पर लाकर दो दिन सामूहिक बलात्कार किया. दबंग हर रोज़ उसे उसके घर से बाल पकड़ कर चबूतरे तक लाते और फिर उससे सामूहिक दुष्कर्म करते. अफ़सोस की बात यह कि 70 घरों वाले उस गांव के किसी भी शख़्स ने विरोध तक नहीं किया और न पुलिस को सूचना दी.

बिहार के खगड़िया ज़िले में बेलदौर थाना क्षेत्र के गांव भरना में दबंगों ने 65 वर्षीय कौशल्या को लाठी-डंडों से पीटा और उसके आगे एक महिला का शव रखकर उसे ज़िंदा करने के लिए कहा. पीड़िता की पुत्री के मुताबिक, गांव के जंग बहादुर सिंह की बहू काफी दिनों से बीमार थी, जिसकी मौत हो गई. इसके लिए कौशल्या को ज़िम्मेदार ठहराते हुए डायन करार देकर उसकी जमकर पिटाई की गई. खगड़िया में एक महिला पंचायत सदस्य भी ऐसे अंधविश्वासी लोगों का शिकार बन गई. पांच लोगों ने डायन-टोनहिन कहकर पहले उसे जमकर पीटा और फिर उसकी नाक काट ली.

मुजफ्फरपुर के हथौड़ी थाना अंतर्गत गांव सिमरी में 65 वर्षीय सुशीला को उसके पड़ोसियों ने डायन बताते हुए लाठियों से इतना पीटा कि वह अधमरी हो गई. पड़ोसी की 20 वर्षीय बेटी की तबियत खराब होने का खामियाजा सुशीला को भुगतना पड़ा. दुर्भाग्यपूर्ण तथ्य यह कि पुलिस ने सुशीला की पीड़ा सुनने के बजाय उसे दुत्कारते हुए थाने से भगा दिया. झारखंड के रांची के लापुंग इलाके में दो आदिवासी महिलाओं को डायन बताकर मौत के घाट उतार दिया गया. पुलिस ने उनमें से एक महिला की लाश बेलारी नदी के किनारे बरामद की. बंधनी मुंडाइन नामक यह महिला कई दिनों से गायब थी. पश्चिमी सिंहभूम ज़िले के झींकपानी थाना अंतर्गत गांव सोनापासी में निराशो गोप नामक महिला को डायन बताते हुए जान से मारने की कोशिश की गई. उसके भाई को भी लोहे की राड से पीटा गया. राजस्थान के उदयपुर के सलंबूर थाना अंतर्गत गांव कराकली में केशीबाई नामक वृद्धा को उसके भतीजे ने इस कदर पीटा कि अगले दिन उसकी मौत हो गई. इसी उदयपुर के गोगुंदा थाना अंतर्गत गांव सेलू निवासी 65 वर्षीय वृद्धा हगामी पर डायन होने का आरोप लगाकर उसके निकट संबंधियों ने उस पर

- एक जनवरी, 2011 लेकर मार्च, 2014 तक देश भर में कुल 527 महिलाओं की हत्या.
- उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, तमिलनाडु, असम, पश्चिम बंगाल एवं राजस्थान सर्वाधिक प्रभावित राज्य.
- बेसहारा महिलाओं की संपत्ति पर दबंगों की गिद्ध-दृष्टि, भूमि संबंधी विवाद, पुरानी रंजिश एवं आपसी ईर्ष्या-भाव भी एक बड़ी वजह.
- जवान-विधवा औरतों पर कुदृष्टि रखने वाले असरदार लोग डायन करार देने की धमकी देकर उठाते हैं अनुचित लाभ.
- डायन प्रथा प्रतिषेध अधिनियम-1999 बनाने वाला बिहार देश का पहला राज्य, लेकिन राष्ट्रीय स्तर अभी तक कोई क़ानून नहीं.

एक केंद्रीय क़ानून बनाने की ज़रूरत

डायन कहकर महिलाओं के उत्पीड़न, अपमान और जान से मार देने की घटनाओं को देखते हुए 1996 में बिहार की संस्था फ्री लीगल एड कमेटी (फ्लैक) के संस्थापकों में से एक प्रेमचंद प्रेम ने इस संबंध में एक क़ानून की ज़रूरत महसूस की. पटना जाकर उन्होंने तत्कालीन बिहार के प्रत्येक विधायक से संपर्क साधा और डायन प्रथा प्रतिषेध अधिनियम बनवाने के लिए सहायता मांगी. प्रेमचंद जब डायन प्रथा प्रतिषेध अधिनियम बनवाने के लिए प्रयास कर रहे थे, तो कुछ राजनेताओं ने उनके क़दम को आदिवासी संस्कृति पर हमला बताकर विरोध भी किया, लेकिन 1999 में बिहार विधानसभा एवं विधान परिषद ने यह अधिनियम पारित कर मंजूरी के लिए राज्यपाल को भेज दिया. 20 अक्टूबर, 1999 को राज्यपाल ने डायन प्रथा प्रतिषेध अधिनियम को मंजूरी दे दी. यह दिन बिहार में आज भी अंधविश्वास विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है. एकीकृत बिहार देश का ऐसा पहला राज्य बना, जिसके पास इस तरह का क़ानून था. 2000 में जब बिहार का विभाजन हुआ और झारखंड पृथक राज्य बना, तो उसने भी यह क़ानून अपने यहां लागू किया. इस अधिनियम के अंतर्गत आरोपी को तीन महीने की कैद एवं एक हज़ार रुपये जुर्माने और ओझा-गुनी को एक साल की कैद एवं दो हज़ार रुपये जुर्माने का प्रावधान है. 2009 में तत्कालीन केंद्रीय बाल एवं महिला कल्याण मंत्री कृष्णा तीरथ ने डायन प्रथा प्रतिषेध राष्ट्रीय क़ानून बनाने का आश्वासन भी दिया था, लेकिन आज तक उसका कहीं कोई अता-पता नहीं है. बीते 16 अगस्त को दिल्ली के जंतर-मंतर पर राष्ट्रीय दलित महिला आंदोलन ने डायन बताकर महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार के विरोध में प्रदर्शन किया. संगठन की अध्यक्ष रजनी तिलक ने आरोपियों को फांसी देने, डायन शब्द को असंवैधानिक घोषित करने और एक केंद्रीय क़ानून बनाने की मांग की. पिछले दिनों राजस्थान हाईकोर्ट ने भी राज्य सरकार से डायन प्रथा विरोधी क़ानून को लेकर जवाब-तलब किया. नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति अजीत सिंह एवं न्यायमूर्ति एएस ग्रेवाल की खंडपीठ ने बीती 13 जुलाई को आदेश दिए कि जब तक यह क़ानून विधिवत लागू नहीं हो जाता, तब तक पीड़ितों को पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत दो लाख रुपये की क्षतिपूर्ति जारी रखी जाए. याचिका में कहा गया था कि राज्य विधानसभा में डायन प्रथा विरोधी क़ानून पारित तो कर दिया गया, लेकिन उसे लागू नहीं किया गया, जिससे उसका लाभ पीड़ितों को नहीं मिल पा रहा है. राज्य सरकार की ओर से कहा गया है कि अतिशीघ्र यह क़ानून पूरी तरह लागू कर दिया जाएगा. सामाजिक कार्यकर्ताओं का मत है कि देश में मौजूद विभिन्न क़ानूनों के ज़रिये भी दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करके पीड़ित को न्याय दिलाया जा सकता है, लेकिन पुलिस ऐसे मामलों में जान-बूझकर रुचि नहीं लेती. राजस्थान के भीलवाड़ा निवासी बोली देवी विश्नोई का मामला यही बताता है. बोली देवी को डायन बताकर समाज ने इस कदर अपमानित किया कि उनके सरकारी कर्मचारी पति को दबाव और तनाव के चलते नौकरी छोड़नी पड़ी. उनकी बहुओं को भी बेइज्जत किया गया. उनका घर से निकलना और कहीं आना-जाना तक बंद हो गया. ■

पर्दे के पीछे छिपी घिनौनी साजिश

ऐसी घटनाओं के पीछे एक बड़ी वजह बेसहारा महिलाओं की संपत्ति पर दबंगों की गिद्ध-दृष्टि, भूमि संबंधी विवाद, पुरानी रंजिश एवं आपसी ईर्ष्या-भाव भी है. जवान-विधवा औरतों पर कुदृष्टि रखने वाले असरदार लोग भी ओझा-गुनी द्वारा उसे डायन करार देने की धमकी देकर अनुचित लाभ उठाते हैं और नाकाम रहने पर ऐसी औरतें मौत के घाट उतार दी जाती हैं. पीड़ित पक्ष की सबसे बड़ी त्रासदी यह होती है कि गांव या क्षेत्र का कोई भी शख़्स उसकी मदद के लिए आगे नहीं आता. लोग हमलावरों का साथ इसलिए देते हैं, क्योंकि वे संख्या बल में ज़्यादा होते हैं या फिर उन्हें समाज के ख़िलाफ़ जाने में डर लगता है. पीड़ित पक्ष को पुलिस या अस्पताल जाने के लिए साधन तक नहीं मिल पाता. पैसों का प्रबंध करने के लिए उसे खेत, घर या फिर गहने-बर्तन गिरवी रखने पड़ते हैं. इलाकाई साहूकार भी गरज देखकर कर्ज की रकम पर ब्याज दर को लेकर मनमर्जी चलाते हैं. उत्तर प्रदेश के सोनभद्र ज़िले के गांव घघरीटोला निवासी जोधी लाल की कहानी कुछ यही पीड़ा बयां करती है. जोधी लाल को डायन-टोनहिन के आरोप के चलते कुल्हाड़ी के अनगिनत वार सहने वाली अपनी पत्नी मनबसिया को बचाने की ख़ातिर खेत और महुआ के 13 पेड़ महज एक हज़ार रुपये में गिरवी रखने पड़े. जोधी लाल पुलिस के पास भी गया, लेकिन उसे फटकार और भद्दी गालियां मिलीं. जब अदालत ने आदेश किया, तब कहीं जाकर उसका मुक़दमा दर्ज हुआ. बक़ौल जोधी लाल, डायन-चुड़ैल जैसी कोई बात नहीं थी. हमलावरों से पेड़ और ज़मीन को लेकर उसका विवाद चल रहा था. इसी बीच उस परिवार के एक लड़के की मृत्यु हो गई, जिसके लिए मनबसिया को दोषी ठहरा दिया गया. ■

mahendra.awdhesh@gmail.com

www.chauthiduniya.com
चौथी दुनिया

www.kamalmorarka.com

कमल मोरारका

भारत-पाक का मामला है. जब भी किसी वार्ता या समझौते की बात आती है, तो सीमा पर उधर से सेना द्वारा ऐसी कोई हरकत कर दी जाती है, जिससे बातचीत बंद हो जाती है. पाकिस्तान की सेना इस मामले में बिल्कुल साफ़ है. उसका मानना है कि आप चाहे जिससे बात कर लें, हमें मालूम है कि हमारे हित में क्या है. हमें इस जाल में नहीं फंसना चाहिए. दरअसल, मैं व्यक्तिगत तौर पर यह महसूस करता हूं कि बातचीत होनी चाहिए. एक बार अगर बातचीत करने का निर्णय ले लिया, तो उसे स्थगित नहीं करना चाहिए. चाहे ऐसी छिटपुट घटनाएं क्यों न होती रहें. मुख्य बात यह है कि सरकार को अतिरिक्त फंड का आवंटन करना चाहिए. सरकार के लिए अभी अनुकूल परिस्थिति भी है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में कच्चे तेल की क़ीमतें काफी गिर गई हैं. सरकार को सीमा पर मजबूत क़दम उठाने चाहिए.

राजनीतिक बहस का स्तर गिरता जा रहा है

यह देखकर अफ़सोस होता है कि राजनीतिक बहस और राजनीतिक प्रक्रिया का स्तर नीचे गिरता जा रहा है. जैसा कि हम पहले भी कह चुके हैं कि संसद का मानसून सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया. यह भी भारत के विधायी काम का न्यूनतम स्तर था. अब हमारे समक्ष बिहार का चुनाव है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही राज्य के तीन दौरे कर चुके हैं. हो सकता है, आगे भी एक–दो दौरे और करें. लेकिन, उनके चुनावी भाषणों का लहजा और स्वर उस स्तर का नहीं है, जिसकी एक प्रधानमंत्री से अपेक्षा की जाती है. हम समझ सकते हैं कि चुनाव में आप पार्टी के लिए प्रचार करते हैं, जिसमें आपको अपने विरोधियों की आलोचना करनी पड़ती है, लेकिन एक प्रधानमंत्री द्वारा जो भी कहा जाए, उसमें गरिमा होनी चाहिए और उसका एक स्तर होना चाहिए. किसी भी क़ीमत पर इस पर समझौता नहीं होना चाहिए.

इंदिरा गांधी ने यह नियम बना लिया था कि वह मध्यावधि चुनाव में बहुत कम जाती थीं. राज्यों के चुनाव में प्रचार तो करती थीं, लेकिन अपनी बात को मुख्य मुद्दों पर ही केंद्रित रखती थीं. मैं मौजूदा प्रधानमंत्री की चिंता समझ सकता हूं. बिहार बहुत बड़ा राज्य है और अगर वह वहां नहीं जीतते हैं, तो यह पार्टी और खुद उनकी छवि के लिए एक गहरा सदमा होगा. राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और पार्टी के दूसरे नेता कुछ भी कहें, ठीक है, लेकिन मोदी की ज़ुबान से जो भी बात निकले, वह गरिमापूर्ण होनी चाहिए. राज्यों को पहले भी पैकेज दिए जाते रहे हैं. लेकिन, अभी क्या हो रहा है? अभी ऐसा लगता है कि यह वोट के बदले दी जाने वाली एक वस्तु बन गई है. वह पैकेज के बदले वोट मांग रहे हैं. कोई भी उनसे इस बारे में विस्तृत जानकारी नहीं मांग रहा है, यह नहीं पूछ रहा है कि आप क्या और कितने समय के भीतर देंगे? और, अगर आप हार जाते हैं, तब भी यह पैकेज बरकरार रहेगा या नहीं? दरअसल, यह पैसा भाजपा के फंड से नहीं जा रहा है, बल्कि केंद्र सरकार एक राज्य सरकार को दे रही है. इसलिए पार्टियों को बीच में नहीं आना चाहिए.

भारत–पाक का मामला है. जब भी किसी वार्ता या समझौते की बात आती है, तो सीमा पर उधर से सेना द्वारा ऐसी कोई हरकत कर दी जाती है, जिससे बातचीत बंद हो जाती है. पाकिस्तान की सेना इस मामले में बिल्कुल साफ़ है. उसका मानना है कि आप चाहे जिससे बात कर लें, हमें मालूम है कि हमारे हित में क्या है. हमें इस जाल में नहीं फंसना चाहिए. दरअसल, मैं व्यक्तिगत तौर पर यह महसूस करता हूं कि बातचीत होनी चाहिए. एक बार अगर बातचीत करने का निर्णय ले लिया, तो उसे स्थगित नहीं करना चाहिए. चाहे ऐसी छिटपुट घटनाएं क्यों न होती रहें. मुख्य बात यह है कि सरकार को अतिरिक्त फंड का आवंटन करना चाहिए. सरकार के लिए अभी अनुकूल परिस्थिति भी है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में कच्चे तेल की क़ीमतें काफी गिर गई हैं. सरकार को सीमा पर मजबूत क़दम उठाने चाहिए. जब भी सीज फायर का उल्लंघन होता है, तो हम सिर्फ़ विरोध दर्ज कराते हैं. दरअसल, हमें उसका करारा जवाब देना चाहिए. सही नीति तो यह होगी कि हम ऐसा जवाब दें कि वे विरोध दर्ज कराएं. लेकिन, अब तक ऐसा नहीं हुआ है. हम अभी भी शिकायत करते हैं कि पाकिस्तान यह कर रहा है, वह कर रहा है. इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा. हमें इस बारे में एक स्पष्ट जवाबी कार्रवाई की रणनीति बनानी होगी.

भाजपा को खुश करने के लिए बहुत सारे अख़बार लिख रहे हैं कि उसने राजस्थान के निकाय चुनाव में जीत हासिल की है. वे यह भी बता सकते थे कि भाजपा को कांग्रेस के मुक़ाबले वोट प्रतिशत में झटका लगा है. स्थानीय निकाय के चुनाव कभी भी विधानसभा या लोकसभा चुनाव जैसे नहीं होते. यह एक मिश्रित परिणाम है. राजस्थान के 129 निकायों में 71 भाजपा और 44 कांग्रेस के खाते में गए हैं. दिलचस्प रूप से वसुंधरा राजे और दुष्यंत सिंह के क्षेत्रों में कांग्रेस को जीत हासिल हुई है. इससे ज़ाहिर है कि वहां के लोगों ने वसुंधरा राजे और दुष्यंत सिंह पर लगे आरोपों को नोटिस में लिया है. यह सच हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन कुल मिलाकर यह परिणाम ऐसा नहीं है, जिससे भाजपा बहुत खुश हो जाए.

लोकसभा चुनाव के समय भाजपा नेताओं की ओर से ग़ैर–ज़िम्मेदाराना बयान आ रहे थे कि रुपया कमज़ोर हो रहा है और जब हम सत्ता में आएंगे, तो एक डॉलर की क़ीमत 40 रुपये तक ला देंगे. एक सज्जन तो यह भी कह रहे थे कि एक डॉलर एक रुपये के बराबर हो जाएगा. उन्हें अर्थशास्त्र की समझ नहीं है. उन्हें समझना चाहिए कि एक्सचेंज रेट बहुत ही संवेदनशील विषय है. अंतरराष्ट्रीय व्यापार एक्सचेंज रेट पर निर्भर करता है. वह केवल रुपया या डॉलर नहीं, बल्कि अन्य मुद्राओं के हिसाब से भी चलता है. चीन ने अपनी करेंसी का अवमूल्यन किया है, क्योंकि वह एक बहुत बड़ा निर्यातक है. इससे रुपये पर और ज़्यादा दबाव आ गया है. रुपये का अवमूल्यन भारत के हित में है. अगर यह और थोड़ा नीचे जाता है, तो कोई बुराई नहीं है. अभी रुपया एक डॉलर के मुक़ाबले 65 पर है और यह इससे भी नीचे जाता है, तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा. इसका सब्जियों के दाम घटने–बढ़ने से कोई संबंध नहीं है. विशेषज्ञों (एक्सपर्ट्स) को इस मुद्दे पर अपनी राय रखने दीजिए. ज़्यादा घबराने की बात नहीं है. जब रुपया डॉलर के मुक़ाबले 18 पर था, तब हमारी अर्थव्यवस्था की हालत खराब थी. जब मनमोहन सिंह ने भारतीय अर्थव्यवस्था को मुक्त बनाया, तब एक दिन में रुपया 18 से 32 पर चला गया. उस वक्त हम विरोध नहीं कर रहे थे. सब लोग समझ रहे थे कि हम कोई बहुत बड़ा काम कर रहे हैं. एक बार अगर आपने अर्थव्यवस्था को खोल दिया, तो रुपये को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं. इसमें घबराने जैसी कोई बात नहीं है. रुपया अपना स्तर खुद पा लेगा. आरबीआई ज़रूरत पड़ने पर हस्तक्षेप करेगा. लेकिन, अनावश्यक रूप से इसे संकट बनाने की ज़रूरत नहीं है. भाजपा नेताओं को उन विषयों पर बोलना बंद कर देना चाहिए, जिनकी उन्हें जानकारी नहीं है. ऐसा ही एक विषय है, अर्थव्यवस्था.■

feedback@chauthiduniya.com

जब एक स्त्री डाकू बदला लेने पहुंचती है-2

लालाराम-श्रीराम के अपराध की सजा बेहमई ने भुगती

आज पत्रकारिता के मायने बदल गए हैं, बदल रहे हैं अथवा बदल दिए गए हैं, नतीजतन, उन पत्रकारों के सामने भटकाव जैसी स्थिति आ गई है, जो पत्रकारिता को मनसा-वाचा-कर्मणा अपना धर्म-कर्तव्य और कमज़ोर-बेसहारा लोगों की आवाज़ उठाने का माध्यम मानकर इस क्षेत्र में आए और हमेशा मानते रहे. और, वे नवांकुर तो और भी ज़्यादा असमंजस में हैं, जो पत्रकारिता की दुनिया में सोचकर कुछ आए थे और देख कुछ और रहे हैं. ऐसे में, 2005 में प्रकाशित संतोष भारतीय की पुस्तक-पत्रकारिता: नया दौर, नए प्रतिमान हमारा मार्गदर्शन करती और बताती है कि हमारे समक्ष क्या चुनौतियां हैं और हमें उनका सामना किस तरह करना चाहिए. चार दशक से भी ज़्यादा समय हिंदी पत्रकारिता को समर्पित करने वाले संतोष भारतीय देश के उन पत्रकारों में शुमार किए जाते हैं, जो देश और समाज से जुड़े प्रत्येक मुद्दे पर निर्भीक, सटीक, निष्पक्ष टिप्पणी करते हैं.

यमुना नदी के दोनों तरफ़ कानपुर व जालौन ज़िलों में मेव ठाकुरों के कुल 72 गांव हैं. कहते हैं कि ये औरंगजेब के जमाने में मेवाड़ से इस क्षेत्र में आए थे. तब इनके 84 गांव थे. शरीर से खूब तंदुरुस्त मेव ठाकुरों के अनोखे रीति–रिवाज थे. मसलन इनके यहां शादियां आपस में ही होती थीं. फिर समय बदला और कुछ ने अपने को इन रिवाजों से अलग कर लिया. लेकिन अभी भी मेव ठाकुरों के 72 गांवों में यह रिवाज चल रहा है और इनकी आपस में ही रिश्तेदारियां हैं. इन्हें दादी ठाकुर भी कहते हैं. लालाराम व श्रीराम भी, जिनकी तलाश में फूलन बेहमई गई थी, दादी ठाकुर ही हैं और पड़ोस के गांव दमनपुर के रहने वाले हैं. उनकी बेहमई में कई रिश्तेदारियां हैं. क्षेत्र में फैली चर्चा के अनुसार,, बेहमई गांव लालाराम–श्रीराम का मुख्य अड्डा है. इसका कारण गांव में उनकी रिश्तेदारियां और गांव का भौगोलिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होना है.

बेहमई की घटना को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा. इस पूरे अंचल में डकैतों के तीन क्षेत्र हैं. पहला है एटा, मैनपुरी, आगरा व इटावा के इलाके, दूसरा आगरा एवं इटावा के राजस्थान से जुड़े व मध्य प्रदेश से लगे क्षेत्र और तीसरा है कानपुर, जालौन, हमीरपुर एवं इटावा ज़िले. इस पूरे क्षेत्र में चंबल व यमुना के अलावा कुंवारी, पहुंज तथा बेतवा ने भयानक बीहड़ बनाया है, जिसमें डाकुओं को निरापद आश्रय मिलता है. छविराम, पोथी तथा मलखान पहले व दूसरे क्षेत्र के डाकू हैं. छविराम व पोथी यादव हैं तथा मलखान मिर्धा राजपूत. क्षेत्र नंबर तीन में दो साल पहले डाकुओं के गिरोह आपस में बंटे हुए थे, जिन्हें विक्रम मल्लाह ने बाद में आपस में मिला दिया था. विक्रम के जीते जी इस इलाके में मुस्तकीम ही दूसरा बड़ा डाकू था, लेकिन वह भी विक्रम से मिलकर ही अपनी योजनाएं बनाता था. इस समय तक क्षेत्र में कोई बंटवारा नहीं था.

विक्रम को समाप्त करने के लिए कानपुर के पुलिस इंस्पेक्टर श्यामवीर सिंह राठौर ने एक चाल चली. उन्होंने विक्रम के गिरोह में शामिल मेव राजपूत लालाराम व श्रीराम से सजातीय आधार पर संपर्क साधा. दोनों ने पुलिस के समर्थन का आश्वासन पाकर अपनी ससुराल बैरामऊ में सोए हुए विक्रम व उसके साथी बारेलाल को मार दिया तथा फूलन को लेकर भाग गए. साथ में सात आदमी और थे. सभी नौ लोगों ने बाइस दिनों तक फूलन के साथ बलात्कार किया. इसी क्रम में फूलन को बेहमई में भी रखा गया. बेहमई यमुना के किनारे है तथा यमुना के ठीक दूसरी तरफ़ मल्लाहों का गांव है, पालगांव. अपने कैद की तेइसवीं रात में शौच करने गई फूलन यमुना में कूद गई और तैरकर पालगांव जा पहुंची. वहीं से उसने मुस्तकीम से संपर्क किया तथा मुस्तकीम के गिरोह में शामिल हो गई. जब मुस्तकीम को पूरी बात का पता चला, तो वह क्रोध से फुंफकार उठा. एक बार वह लालाराम व श्रीराम का पता लगाने अकेले भी बेहमई गया, लेकिन गांव वालों ने उसे कुछ भी बताया नहीं. मुस्तकीम की मौत अभी हाल में यानी चार मार्च को एक पुलिस मुठभेड़ में हुई. बहरहाल, अब फूलन की ज़िंदगी का लक्ष्य हो गया लालाराम व श्रीराम सहित उसके सातों आदमियों की हत्या कर अपने अपमान का बदला लेना. विक्रम की हत्या का बदला लेना तो केवल उसका एक हिस्सा था. उस रोज़ फूलन ही पहरे पर थी, जब विक्रम की हत्या हुई.

इधर पुलिस इंस्पेक्टर राठौर ने दूसरा खेल खेला. उन्होंने विक्रम को मुठभेड़ में मार डालने का दावा कर दिया. लालाराम व श्रीराम इस धोखे से बौखला उठे. उन्हें डर हो गया कि भेद न खुल जाए, इसलिए पुलिस उन्हें मार देगी. अत: उन्होंने पुलिस से मिलना–जुलना बंद कर दिया. फूलन के भाग जाने पर अब उन्हें जो भी मल्लाह मिलता, उसे वे पुलिस का जासूस समझते तथा मार देते. पालगांव के ही एक मल्लाह को उन्होंने मार दिया, क्योंकि उन्हें शक था कि वह मुखबिरी करता था. खालला गांव के एक गड़रिये को भी उन्होंने इसी उन्माद में मार दिया. फलस्वरूप गड़रियों और मल्लाहों ने फूलन की मदद चाही. इसी बीच लालाराम व श्रीराम ने उरई के प्रसिद्ध वकील गोविंद नारायण तिवारी के लड़के देव नारायण को पकड़ा तथा पचास हज़ार रुपये लेकर छोड़ा. श्री तिवारी ने कभी उन लोगों की मदद की थी, जो फूलन के साथ थे. लालाराम व श्रीराम जिसे भी पकड़ते थे, उसे बेहमई में ले जाकर ही छोड़ते थे. इससे फूलन को अंदाज़ हो गया कि बेहमई के लोग लालाराम व श्रीराम से मिले हुए हैं.

> विक्रम को समाप्त करने के लिए कानपुर के पुलिस इंस्पेक्टर श्यामवीर सिंह राठौर ने एक चाल चली. उन्होंने विक्रम के गिरोह में शामिल मेव राजपूत लालाराम व श्रीराम से सजातीय आधार पर संपर्क साधा. दोनों ने पुलिस के समर्थन का आश्वासन पाकर अपनी ससुराल बैरामऊ में सोए हुए विक्रम व उसके साथी बारेलाल को मार दिया तथा फूलन को लेकर भाग गए.

उस रोज़ फूलन बेहमई में लालाराम–श्रीराम को ढूंढने ही आई थी. चर्चा है कि बीस लोगों की हत्या करने के बाद भी वह माइक पर अट्टहास कर रही थी. इससे उसके भीतर धधक रहे जातीय द्वेष का अंदाज़ा लगाया जा सकता है. इस संदर्भ में यह बात बेमानी हो जाती है कि वह पहले से योजना बनाकर ठाकुरों की सामूहिक हत्या करने आई थी या किन्हीं परिस्थितियोंवश उसने अचानक ऐसा कर डाला. हालांकि, जिस तरीके से एक–एक करके उसने लोगों को बटोरा और उन्हें गांव से बाहर लिवा ले गई, उससे यह नरसंहार हड़बड़ी में की गई कार्रवाई नहीं लगता. प्राप्त जानकारी के अनुसार, डाकू जब नाव से यमुना पार करके उस पार उतरे, तो एक व्यक्ति उधर से गुज़र रहा था. डाकुओं में से एक ने उसे बुलाया. तभी पीछे से एक ने अपने साथी से जल्दी चलने को कहकर उसे छुड़वा दिया. यानी वे जल्दी से जल्दी गांव पहुंच कर अधिक से अधिक आदमियों को अपने कब्जे में कर लेना चाहते थे. गांव में जिस लापरवाही से उन्होंने लूटपाट की, उससे भी यही लगता है कि उनका मुख्य लक्ष्य लूटपाट करना नहीं था. यह नाटक संभवत: इसलिए किया गया, ताकि यह लगे कि वे इसीलिए आए हैं. एक घायल का कहना था कि यदि वे लोग जरा भी सतर्क हो जाते और आपा–धापी में ही भाग लेते, तो आधे से अधिक बच जाते, क्योंकि चौतरफ़ा ऊंचे–नीचे बीहड़ से घिरे इस गांव का भूगोल ही ऐसा है.

जारी...

feedback@chauthiduniya.com

संतोष भारतीय

जब तोप मुक़ाबिल हो

आचार्य बालकृष्ण आयुर्वेद के महान योद्धा हैं

> आचार्य बालकृष्ण ने बाबा रामदेव के साथ मिलकर सबसे बड़ा काम यह किया कि पूरे विश्व में योगा को योग बना दिया. पहले योगा के नाम से पूरी दुनिया में हिंदुस्तान से विद्वान जाते थे और इसे उन्होंने अभिजात्य वर्ग की चीज बना रखा था. लेकिन, बाबा रामदेव और आचार्य बालकृण की जोड़ी ने इसे सामान्य जन की वस्तु बना दिया. आचार्य बालकृष्ण ने योग के ऊपर भी खोज जारी रखी और उसे शोध (रिसर्च) का विषय बना दिया. आज पतंजलि योग पीठ में आयुर्वेद का एक बहुत बड़ा अस्पताल है, जो सारी दुनिया में बाबा रामदेव के अस्पताल के नाम से जाना जाता है.

पत्रकारिता में अक्सर ऐसा होता है कि हम कुछ सुबूतों के आधार पर एक रिपोर्ट करते हैं, पर जब उसकी सच्चाई में जाते हैं, तो वहां कुछ ऐसे तथ्य सामने आते हैं, जिनकी तुलना में पहले मिले सुबूत बहुत हल्के लगते हैं. और, हम जिसके बारे में रिपोर्ट करते हैं, देखते हैं कि वह इतना ज़्यादा काम कर रहा है और इतने कमाल का काम कर रहा है, तब लगता है कि अपनी ग़लती सुधारनी चाहिए.

मैं अभी–अभी पतंजलि योग पीठ से आया हूं. पतंजलि योग पीठ बाबा रामदेव का आश्रम है. बल्कि कहें कि यह बाबा रामदेव का केंद्रीय आश्रम है. बाबा रामदेव देश भर में लोकसभा चुनाव से तीन साल पहले शहर–शहर, कस्बे–कस्बे लोगों का संगठन बना रहे थे और उन्हें व्यवस्था परिवर्तन के लिए तैयार कर रहे थे, पर उनका सारा ज़ोर कांग्रेस द्वारा भ्रष्टाचार के सवाल पर अपनाए जाने वाले रुख़ के ख़िलाफ़ था. उन्होंने देश में जो जन–जागरण पैदा किया, वैसा ही जन–जागरण अन्ना हजारे ने भी पैदा किया और इस जन–जागरण ने भारतीय जनता पार्टी को अद्भुत मदद की. उसी दौरान बाबा रामदेव के आश्रम में क्या हो रहा था, क्या नहीं हो रहा था, इसे लेकर बहुत सारी कथाएं बाहर आईं, पर आज हमारा विषय बाबा रामदेव नहीं, आचार्य बालकृष्ण हैं.

आचार्य बालकृष्ण बाबा रामदेव के बहुत क़रीबी अनुयायी हैं. बाबा रामदेव की संघर्ष यात्रा में आचार्य बालकृष्ण प्रारंभ से लक्ष्मण की तरह जुड़े रहे हैं. आचार्य बालकृष्ण का बाबा रामदेव से कोई खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन शायद खून से भी बड़ा रिश्ता है और पूरे देश में यह माना जाता है कि बाबा रामदेव के सारे क्रियाकलापों के पीछे, उनकी सारी कोशिशों के पीछे अगर कोई संगठनात्मक दिमाग है, तो वह आचार्य बालकृष्ण का है. लेकिन, सच्चाई यह भी नहीं है. सच्चाई कुछ और है.

आचार्य बालकृष्ण पतंजलि योग पीठ में जो काम कर रहे हैं, वह अद्भुत है. आयुर्वेद के क्षेत्र में आचार्य बालकृष्ण विश्व के अकेले व्यक्ति हैं, जो न केवल आधिकारिक जानकारी रखते हैं, बल्कि आधिकारिक सलाह भी दे सकते हैं. आयुर्वेद की दवाइयां पौधों से बनती हैं. आचार्य बालकृष्ण ने हज़ारों तरह की औषधियों की वनस्पतियां तलाशी हैं और उन्हें अपने आश्रम में उगाया भी है. इन दिनों वनस्पतियों के ऊपर आचार्य बालकृष्ण काम कर रहे हैं और संस्कृत में सिर्फ़ 1,000 वनस्पतियों के आधिकारिक नाम हैं. लगभग पांच से छह हज़ार वनस्पतियों के ऐसे नाम हैं, जो आधिकारिक नहीं हैं. आचार्य बालकृष्ण लगभग सवा लाख प्रजातियों को तलाशने और उनका नाम रखने का काम कर रहे हैं. टेलीविजन पर आने वाले आयुर्वेद को लेकर उनके कार्यक्रम विश्व में बहुत ही रुचि से देखे–सुने जाते हैं. आचार्य बालकृष्ण एलोपैथी के मुक़ाबले आयुर्वेद को स्थापित करने वाले महान योद्धा कहे जा सकते हैं.

आचार्य बालकृष्ण पुरानी पांडुलिपियां तलाश–तलाश कर, जिनके जीवनावशेष जहां भी मिलते हैं, वहां से वह मंगाते हैं और पुरानी पांडुलिपियों को नए कलेवर में सहेजने का काम कर रहे हैं. उन पांडुलिपियों को पढ़ने वाले लोग अब हिंदुस्तान में नहीं हैं, विश्व में होने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता. कौन उन पांडुलिपियों को पढ़ सकता है, ऐसे लोगों को तलाशने का काम आचार्य बालकृष्ण ने किया है. उनकी टीम में ऐसे–ऐसे विद्वान हैं, जिनकी उम्र तो ज़्यादा है, लेकिन वे अद्भुत विद्वान हैं.

जब आचार्य बालकृष्ण को लगा कि अधिक उम्र के विद्वानों के बाद, जो कि मुश्किल से खोज के बाद उन्हें मिले, आगे यह काम कैसे होगा? तो उन्होंने अपने छात्रों को छांटकर उन्हें इसकी शिक्षा दी और अब वे छात्र आचार्य बालकृष्ण के लिए पांडुलिपियां पढ़ने, सहेजने और उन्हें सरल भाषा में लोगों तक पहुंचाने की तैयारी कर रहे हैं. आचार्य बालकृष्ण ने इसके ऊपर काफी पुस्तकें छपवा ली हैं.

आचार्य बालकृष्ण ने बाबा रामदेव के साथ मिलकर सबसे बड़ा काम यह किया कि पूरे विश्व में योगा को योग बना दिया. पहले योगा के नाम से पूरी दुनिया में हिंदुस्तान से विद्वान जाते थे और इसे उन्होंने अभिजात्य वर्ग की चीज बना रखा था. लेकिन, बाबा रामदेव और आचार्य बालकृण की जोड़ी ने इसे सामान्य जन की वस्तु बना दिया. आचार्य बालकृष्ण ने योग के ऊपर भी खोज जारी रखी और उसे शोध (रिसर्च) का विषय बना दिया. आज पतंजलि योग पीठ में आयुर्वेद का एक बहुत बड़ा अस्पताल है, जो सारी दुनिया में बाबा रामदेव के अस्पताल के नाम से जाना जाता है. आचार्य बालकृष्ण असाध्य रोगों को ठीक करने के काम में आयुर्वेद और योग के सम्मिश्रण से बनी उपचार विधि का इस्तेमाल कर रहे हैं और इसके द्वारा लोगों को निरोग कर रहे हैं. ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जो हताश–निराश हो चुके हैं, वे उस अस्पताल में जाते हैं. बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं, जो मानते हैं कि जब तक आचार्य बालकृष्ण उन्हें देख नहीं लेते, उनकी बीमारी नहीं समझ लेते, तब तक उनका रोग ठीक होने वाला नहीं है. ऐसी कई घटनाओं का मैं भी गवाह हूं. ऐसे कई सारे लोग पत्रकार होने के नाते मेरे संपर्क में आते हैं. और, जब मैं उन्हें आचार्य बालकृष्ण के पास भेजता हूं, तो वे लौटकर बताते हैं कि अब उनका रोग ठीक हो जाएगा.

इसके अलावा आचार्य बालकृष्ण उन सारी चीजों को देखते हैं, जो बाबा रामदेव के आश्रम से देश के बाज़ारों में जा रही है. वे शुद्ध हैं, त्रुटिहीन हैं, फ़ायदा कर सकती हैं या नहीं, यह सारी ज़िम्मेदारी आचार्य बालकृष्ण के कंधों पर है. मैं जब उनसे मिला, तो मुझे पता चला कि वह एक–एक चीज को हाथ में लेते हैं और उसका सही विश्लेषण लोगों के सामने रखते हैं. इन दिनों वह मसालों के ऊपर काम कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात से चिंता हुई कि बाज़ार में बिकने वाले मसालों की पैकिंग पर लिखी गई अधिकांश सामग्रियां (इनग्रेडियंट) उनमें शामिल ही नहीं होंती. देखने में तो लगता है कि यह मसाला उन्हीं सामग्रियों से बना है, लेकिन जब उसका विश्लेषण करते हैं, तो उसमें साठ प्रतिशत चीजें ग़लत होती हैं. वह मिश्रण होता ही नहीं है, जो मसालों की पैकिंग पर इनग्रेडियंट के रूप में लिखा रहता है. बाबा रामदेव के उत्पादों पर लोगों का विश्वास इतना बढ़ गया है कि जो भी शख्स उनके उत्पाद लेना शुरू करता है, उसका मुरीद हो जाता है. यहीं पर आचार्य बालकृष्ण का रोल सामने आता है, जो इस बढ़ती हुई साख के पीछे का नाम है.

आचार्य बालकृष्ण बहुत बड़े पैमाने पर देश में जैविक (ऑर्गेनिक) खेती को बढ़ावा देने का काम भी कर रहे हैं. उनके अधिकांश उत्पाद (प्रोडक्ट) जैविक यानी ऑर्गेनिक हैं. जो सबसे महत्वपूर्ण बात मुझे दिखाई दी, वह यह कि आचार्य बालकृष्ण प्रचार से कोसों दूर रहना चाहते हैं. उनका कहना है, बाबा रामदेव देश के लिए काम कर रहे हैं और मैं देश की सेहत के लिए काम कर रहा हूं. इसलिए नाम उसका होना चाहिए, जो देश के लिए काम कर रहा हो. मैं तो उनका अनुयायी हूं.

भारत सरकार ने आयुष मंत्रालय खोला है. यह आयुष मंत्रालय सरकारी अधिकारियों के लिए एक नई चीज है. उन्हें नहीं पता कि आयुष मंत्रालय कैसे चलाना है, क्या शोध (रिसर्च) करना है, किस चीज को प्राथमिकता देनी है और किसे नहीं देनी. बल्कि वास्तविकता में देखें, तो उन्हें बहुत–सी चीजों के नाम भी नहीं मालूम. वे सब इन दिनों आचार्य बालकृष्ण के संपर्क में हैं और उनसे बुनियादी जानकारी ले रहे हैं. पतंजलि योग पीठ में देश भर के किसानों की भी ट्रेनिंग होती है. पतंजलि योग पीठ में जैविक खेती कैसे करें, इसके बारे में भी जानकारी दी जाती है. देश भर से लोगों को आमंत्रित किया जाता है कि वे आएं और देखें कि आयुर्वेद एवं योग पर आधारित जीवनशैली स्वस्थ जीवन और स्वस्थ विचार के लिए कितनी आवश्यक है.

आचार्य बालकृष्ण पर मुक़दमे भी चल रहे हैं. वह सीबीआई जांच के दायरे में भी हैं. एक समय में बहुत सारे अख़बारों ने उनके ख़िलाफ़ रिपोर्टें भी छापीं, पर वे मुद्दे ऐसे हैं, जिनमें किसी ने आचार्य बालकृष्ण का पक्ष जानने की कोशिश ही नहीं की, उनसे कोई मिला ही नहीं कि सच्चाई क्या है. यह हमारी पत्रकारिता का एक नया दुर्गुण है. अगर हम सौ प्रतिशत किसी रिपोर्ट को लेकर संतुष्ट हैं, तो हम बिना किसी का पक्ष जाने भी रिपोर्ट कर सकते हैं. लेकिन, जब यह पता चले कि हमने जिसे सौ प्रतिशत सच माना था, वह सिर्फ़ बीस प्रतिशत सच है और 80 प्रतिशत झूठ, तो भी हम उस व्यक्ति का पक्ष न छापें, यह पत्रकारिता का धर्म नहीं है. आचार्य बालकृष्ण इस राय के हैं कि देश में, विशेषकर पत्रकारिता के क्षेत्र में नकारात्मक रिपोर्टों की भरमार है. कहीं पर भी सकारात्मक चीजें देखने में नहीं आतीं. वह खुद से मिलने आने वाले लिखने–पढ़ने वाले लोगों से आग्रह करते हैं कि सकारात्मक चीजों और सकारात्मक रिपोर्टों के लिए भी अख़बार या टेलीविजन चैनल में जगह होनी चाहिए.

आचार्य बालकृष्ण देश में घूमना पसंद नहीं करते. जहां बहुत ज़रूरी होता है, वह जाते हैं. वह पतंजलि योग पीठ में ही रहना चाहते हैं और वे सारे काम करना चाहते हैं, जिनसे पुरानी पांडुलिपियां, वनस्पतियां, योग और आयुर्वेद हमारे देश में सामान्य जन की पहुंच में आ जाएं तथा उनके जीवन को सुधारें.

मेरा मानना है कि बाबा रामदेव की ताकत के पीछे आचार्य बालकृष्ण का योगदान देश के सामने कम आया है. आचार्य बालकृष्ण बहुत से लोगों की ईर्ष्या के भी पात्र हैं, जिसकी वजह से उन्हें कई परेशानियों का भी सामना करना पड़ा. लेकिन, उन्होंने मुझसे हंसकर कहा, हर अच्छे काम में विघ्न आता ही है. यह प्राचीन काल से चला आया है और गोस्वामी तुलसी दास ने तो इसे रामायण में ही लिख दिया है. तुलसी दास जी कहते हैं कि किसी भी काम से पहले, जो खल–दुष्ट होते हैं, उनकी पूजा ज़रूर करनी चाहिए. और, जो पहले दुष्टों की पूजा नहीं करता, उसके काम में विघ्न या खलल आता ही है. मैं आचार्य बालकृष्ण द्वारा किए जा रहे कामों को देखकर अचंभित हूं और मैं उन सभी से अनुरोध करता हूं कि वे पतंजलि जाएं, जिन्हें योग, आयुर्वेद, प्राचीन पांडुलिपियों एवं वनस्पतियों में रुचि है. विश्वकोश बनाने का काम आचार्य बालकृष्ण कर रहे हैं. जिस दिन सवा लाख वनस्पतियों के नामकरण का काम पूरा हो जाएगा, वह शब्दकोश विश्व के लिए अद्भुत धरोहर हो जाएगा. हालांकि, आचार्य बालकृष्ण इतना काम कर चुके हैं, जिसके परिणामस्वरूप वह ऐसे व्यक्तियों की श्रेणी में शामिल हो गए हैं कि उन्हें पतंजलि योग पीठ के साथ–साथ देश की संपत्ति भी माना जा सकता है. ■

editor@chauthiduniya.com

बिना संसद के शासन

मेघनाद देसाई

संसद का मानसून सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया. इस बार मोदीगेट के साथ वसुंधरा राजे और शिवराज सिंह चौहान बहाना बने. बहरहाल, इससे पहले जो सत्र हंगामे के भेंट चढ़े थे, उनके कुछ और कारण थे. संसद स्वायत्त ज़रूर है, लेकिन उस पर आम लोगों की सेवा की ज़िम्मेदारी भी है. अगर व्यापारी वर्ग संसद में कामकाज ठप होने की वजह से चिंतित है, तो उसकी चिंताओं पर विचार किया जाना चाहिए. व्यापार में उन्नति के साथ ही नौकरी और रोज़गार के अवसरों को सुरक्षित किया जा सकता है. सांसदों के असंसदीय व्यवहार के कारण अगर चीज़ें आगे नहीं बढ़ती हैं, तो उसका खामियाज़ा सांसदों के बजाय आम लोगों को भुगतना पड़ता है. अब सबसे ख़राब परिस्थिति की कल्पना करते हैं. मान लीजिए कि जब तक भाजपा (एनडीए) को दोनों सदनों में बहुमत नहीं मिल जाता है, तब तक सदन नहीं चलने दिया जाता है, क्योंकि दोनों सदनों के चुनाव एक साथ नहीं होते और दोनों सदनों के सदस्यों की कार्यावधि भी अलग–अलग है. लिहाज़ा सरकार को दोनों सदनों में बहुमत के लिए वर्ष 2019 तक इंतज़ार करना पड़ेगा. इस दौरान सरकार को यह रणनीति बनानी चाहिए कि कोई महत्वपूर्ण क़ानून बनाए बगैर कैसे शासन चलाया जाए. यह कोई बहुत चिंता की बात नहीं है, क्योंकि हमें लोकपाल और तेलंगाना बिल पारित करने के लिए संसद के कई सत्रों तक इंतज़ार करना पड़ा था. दूसरे शब्दों में, देश एक अप्रभावी संसद (लगभग जवाहर लाल नेहरू के बाद) झेल लेने में सक्षम था. इंदिरा गांधी ने खुद के सिवाय किसी को कोई तवज्जो नहीं दी. राजीव गांधी को भारी बहुमत हासिल था, इसलिए संसद उनके लिए भी अप्रासंगिक थी. राष्ट्रीय मुद्दों पर बहस और रचनात्मक विधि निर्माण के एक मंच के तौर पर संसद में नेहरू दौर की स्वस्थ परंपरा का वापस आना अब नामुमकिन लगता है.

भारत में कार्यपालिका बहुत शक्तिशाली है. एक निर्णायक प्रधानमंत्री और एक कारगर नौकरशाही की मदद से सुशासन के लिए बहुत कुछ किया जा सकता है. यह बैंकिंग, बीमा और सब्सिडी जैसी कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन में दिखने भी लगा है. डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया जैसे कार्यक्रम शुरू किए जा चुके हैं. रक्षा क्षेत्र में एफडीआई की रुकावटें हटाई जा चुकी हैं. व्यापार में आसानी और नागरिकों को कागज़ी कार्यवाही की उलझन से मुक्ति दिलाना बाकी है. सरकारी काम को और बेहतर बनाने के क़ानून का कार्यान्वयन किया जाना है. जीएसटी बिल और भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 में संशोधन पारित न करने के मौजूदा नुक़सान से यह ज़ाहिर होता है कि सभी पारित विधेयक अर्थव्यवस्था के लिए उपयोगी नहीं होते. याद कीजिए, वर्ष 1998 और 2009 के दरम्यान बिना जीएसटी और भूमि अधिग्रहण बिल के भी अर्थव्यवस्था में 8.5 प्रतिशत का विकास दर्ज किया गया था. बहरहाल, अगर ये बिल पास हो जाते हैं, तो अवश्य मददगार साबित होंगे और अगर कांग्रेस सहयोग नहीं भी करती है, तो भी सरकार अच्छा प्रदर्शन कर सकती है. इसके लिए जितना कम हो सके, उतने क़ानून बनाने की रणनीति बनानी चाहिए, ताकि दो बजट (रेल और आम) के अलावा कोई बिल सदन में रखा ही न जाए. फ़िलहाल अर्थव्यवस्था सात प्रतिशत की दर से विकास कर रही है और महंगाई दर में भी गिरावट दर्ज की जा रही है. मौजूदा निवेश से अधिक से अधिक लाभ हासिल करने की गुंजाइश है.

> भारत में कार्यपालिका बहुत शक्तिशाली है. एक निर्णायक प्रधानमंत्री और एक कारगर नौकरशाही की मदद से सुशासन के लिए बहुत कुछ किया जा सकता है. यह बैंकिंग, बीमा और सब्सिडी जैसी कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन में दिखने भी लगा है.

यूपीए–2 ने मौजूदा सरकार के लिए कई परियोजनाएं छोड़ी हैं. बैंकों की अनर्जक परिसंपत्तियों का बोझ है. प्रधानमंत्री एक प्राइवेटाइजर नहीं हैं. वह चाहते हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम बेहतर प्रदर्शन करें. यह भी एक प्रशासनिक कार्य है, जिसमें क़ानून बनाने की ज़रूरत नहीं है. गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी को विधायिका की अधिक ज़रूरत नहीं थी. इस लिहाज़ से देखा जाए, तो राज्यों में मुख्यमंत्री राष्ट्रपति की तरह काम करते हैं. कांग्रेस ने उन्हें एक सुनहरा मौक़ा दे दिया है कि संसद के बिना ही शासन चलाया जाए. केवल संसद का सत्र बुलाना और प्रतिदिन स्थगित करना बहुत आसान है तथा इससे विपक्ष भी उपकृत महसूस करेगा. सरकार अपना काम करती रहेगी और दोनों सदन निष्क्रिय रहेंगे. अभी सरकार के पास चार साल बचे हैं. देश में बदलाव लाने के लिए यह समय पर्याप्त है.■

feedback@chauthiduniya.com

इस अंक से पतंजलि योग पीठ, हरिद्वार के आचार्य बालकृष्ण जी चौथी दुनिया के पाठकों के लिए विभिन्न आयुर्वेदिक जड़ी–बूटियों के महत्व और इस्तेमाल के बारे में जानकारी देंगे. पहले अंक में आचार्य बालकृष्ण जी अकरकरा, एक भारतीय पौधा, के बारे में बता रहे हैं.

चिकित्सकीय गुणों से भरपूर है अकरकरा

आचार्य बालकृष्ण

अकरकरा का पौधा मूल–रूप से अरब का निवासी कहा जाता है इसलिए इसको मोरक्को अकरकरा कहते हैं. भारत के कुछ हिस्सों में इसकी खेती की जाती है. वर्षाऋतु की प्रथम फुहार पड़ते ही इसके छोटे–छोटे पौधे निकलना शुरू हो जाते हैं. इसकी जड़ का स्वाद **चरपरा** होता है तथा इसको चबाने से गर्मी महसूस होती है व जीभ जलने लगती है. आयुर्वेदीय गुण–कर्म एवं प्रभाव में अरब से आयातित औषधि अधिक वीर्यवान मानी जाती है. आयुर्वेद में इसका प्रयोग लगभग 400 वर्षों से किया जा रहा है. यद्यपि चरक, सुश्रुत आदि प्राचीन ग्रन्थों में इसका उल्लेख नहीं होता है, तथापि यह नहीं माना जा सकता कि यह बूटी भारतवर्ष में पहले नहीं होती थी. भारतवर्ष में पाई जाने वाली यह औषधि प्राय: तीन प्रकार की होती है.

1–आकारकरभ

इसके छोटे–छोटे क्षुप वर्षा–ऋतु के आरम्भ काल में उत्पन्न हो जाते हैं. शाखाएं, पत्र और पुष्प सफेद बाबूना के समान होते हैं, किन्तु इनके डण्ठल कुछ पोले होते हैं. तना और शाखाएं रूएदार होती हैं. ये शाखाएं एक तने या डाली में से निकल कर कई भागों में विभक्त हो जाती हैं. इसकी जड़ में एक प्रकार की सुगन्ध होती है. इसकी जड़ 2.5–10 सेमी लंबी और 5–20 सेमी मोटी तथा वजनदार होती है. मूल छाल मोटी, भूरी तथा झुर्रीदार होती है. अन्य वनस्पतियों का गुण–धर्म तो एक वर्ष में नष्ट हो जाता है, परन्तु इस असली अकरकरा मूल का गुण धर्म 7 वर्षों तक प्राय: जैसे का तैसा रहता है. इसको मुख में चबा लेने से अन्य कटु, तिक्त रस वाली औषधियों का स्वाद मालूम नहीं होता. महाराष्ट्र में इसकी डंडी का अचार और शाक बनाकर खाया जाता है.

2–भारतीय अकरकरा

यह 30–60 सेमी ऊंचा, वर्षायु, शाकीय पौधा है. इसका काण्ड सीधा अथवा आरोही, अत्यधिक पुष्ट एवं मांसल, रोमश, आधार उच्चाग्र भूशायी अत्यधिक अथवा अल्प रोमश होता है. इसके पत्र साधारणत: विपरीत, अंडाकार–भालाकार, त्रिकोणाकार–अण्डाकार होते हैं. इसके पुष्प पीले अथवा रक्ताभ भूरे वर्ण के अण्डाकार अथवा दीर्घायत अंतस्थ पुष्पगुच्छों में होते हैं. इसके फल चपटे, पृष्ठ भाग पर सम्पीडित, अधोमुख अण्डाकार से त्रिकोणीय, कृष्ण वर्ण के होते हैं.

अकरकरा की उपरोक्त उल्लेखित प्रजातियों के अतिरिक्त नामक एक प्रजाति और पाई जाती है, जिसका प्रयोग चिकित्सा के लिए किया जाता है, परन्तु यह अल्प गुण युक्त होती हैं.

3–दीर्घवृन्त अकरकरा

यह शाखा प्रशाखायुक्त, चिकना, सीधा अथवा आरोही लगभग 30 सेमी लम्बा शाकीय पौधा होता है. इसके पत्ते वृंतयुक्त, अण्डाकार या भलाकार 2–4 सेमी लम्बे, 1–2.5 सेमी चौड़े तथा शीर्ष पर नुकीले होते हैं. इसके पुष्प दीर्घवृन्त युक्त पीतवर्ण के होते हैं. इसके पुष्पों का प्रयोग चिकित्सा के लिए किया जाता है. इसके फूलों की मिलावट अकरकरा के पुष्पों से की जाती है तथा कई स्थान पर अकरकरा के स्थान पर इसका प्रयोग किया जाता है. इसके पुष्पों का क्वाथ बनाकर गरारा करने से दंतशूल तथा कण्ठशूल का शमन होता है. इसके पुष्पों का चूर्ण बनाकर दांतों पर रगड़ने से दंतशूल का शमन होता है.

रासायनिक संघटन

इसके मूल में ऐनासाईक्लिन, पाईरेथ्रीन, पेलीटोरिन, एनेट्रीन, हाइड्रोकेरोलिन, टैनिन, डिहाइड्रो ऐनासाइक्लिन, ऐल्कामाइड्स, इन्युलिन, वाष्पशील तैल एवं सीसेमिन पाया जाता है.

आयुर्वेदीय गुण–कर्म एवं प्रभाव

आकारकरभ

–यह बलकारक, कटु, लालास्रावजनक, प्रदाहकारक, नाड़ी को बल देने वाला, कामोद्दीपक, वेदनास्थापक तथा प्रतिश्याय और शोथ को नष्ट करता है.

–इसकी मूल हृदयोत्तेजक, रक्तिमाकारक तथा बलकारक होती है.

–यह सुक्ष्मजीवाणुरोधी कीटनाशक, कृमिदंत, दंतशूल, ग्रसनीशोथ, तुण्डीकेरी शोथ, पक्षाघात, अर्धांगघात, जीर्ण नेत्ररोग, शिरशूल, अपस्मार, विसूचिका, आमवात तथा टाइफस ज्वरनाशक होता है.

–इसके बीज में अल्प गर्भस्रावक प्रभाव दृष्टिगत होता है.

भारतीय अकरकरा

–यह रस में कटु, उष्ण, रूक्ष तथा वातपित्तकारक होती है.

–यह लालास्रावववर्धक, उत्तेजक, दीपन, कफिन सारक, स्वेदक, पाचक, उदरशूल तथा ज्वरनाशक होती है.

–इसका पुष्प कटु, तापजनक, कफनिस्सारक, वेदनाहर, स्वेदजनन एवं ज्वरहर होता है.

औषधीय प्रयोग मात्रा एवं विधि

शिरो रोग

1–मस्तक पीड़ा(शिर:शूल) अकरकरा की जड़ या फूल को पीसकर, हल्का गर्म करके ललाट(मस्तक) पर लेप करने से मस्तक की पीड़ा का शमन होता है.

2–अकरकरा के फूल को दांतों के बीच में रखकर चबाने से जुकाम के कारण होने वाला सिर दर्द मिटता है. इसको चबाने से दाढ़ की पीड़ा मिट जाती है. एक बार के प्रयोग के लिए एक फूल या थोड़ा कम पर्याप्त होता है.

नेत्र रोग

जीर्ण चक्षुरोग–2–4 बूंद अकरकरा मूल स्वरस को नाक में डालने से पुराने नेत्ररोग तथा सिर के दर्द में लाभ होता है.

नासा रोग

पीनस–2–4 बूंद अकरकरा स्वरस को नाक में डालने से पीनस तथा जुकाम, आधासीसी व अन्य ऊर्ध्वजत्रुगत रोगों में लाभ होता है. यह तीक्ष्ण है, बच्चों व सुकुमार लोगों को थोड़ा पानी मिलाकर इसका प्रयोग करना चाहिए.(अकरकरा स्वरस के लिए ताजी जड़ का प्रयोग करें इससे जीर्ण प्रतिश्याय में भी अत्यंत लाभ होता है)

मुख रोग

दंतशूल–अकरकरा मूल या पुष्प और उसका दसवांभाग कपूर लेकर थोड़ा–सा सेंधानमक मिलाकर, पीसकर मंजन करने से सब प्रकार की दंत पीड़ा का शमन होता है.

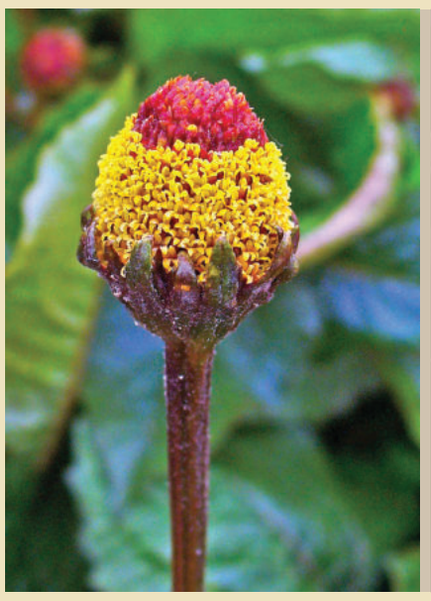

2–मुख दुर्गन्ध–अकरकरा, माजुफुल, नागरमोथा, भुनी हुई फिटकरी, काली मिर्च तथा सेंधानमक सबको बराबर मिलाकर बारीक पीस लें, इस मिश्रण से प्रतिदिन मंजन करने से दांत और मसूड़ों के सभी विकारों में लाभ होता है तथा मुख की दुर्गन्ध मिट जाती है.

3–दंतशूल–अकरकरा के पुष्पों को चबाने से दांत के दर्द में लाभ होता है व मुख की दुर्गन्ध मिटती है.

4–अकरकरा के पुष्पों का प्रयोग हनुशोथ व दांत में कीड़ा लगने या दांतों की पीड़ा, मसूड़ों की सूजन आदि में भी अत्यंत लाभकारी होती है.

5–अकरकरा मूल या पुष्प, हल्दी तथा सेंधानामक को पीसकर उसमें थोड़ा सरसों का तेल मिलाकर दांतों पर मलने से दांत के दर्द का शमन होता है, साथ ही मुख दुर्गन्ध व मसूढ़ों की समस्या भी दूर होती है. यह एक चमत्कारिक प्रयोग है.

6–दंतरोग–अकरकरा की मूल को चबाने से तथा काढ़े का कवल एवं गण्डूष धारण करने से दंतकृमि (दांत में कीड़ा लगना), दांत दर्द आदि दंत रोगों तथा वातजन्य मुख रोगों में लाभ होता है.

कण्ठ रोग

1–कंठ्य–अकरकरा चूर्ण को 250–500 मिग्रा की मात्रा में सेवन करने से बच्चों और गायकों का कंठ स्वर सुरीला हो जाता है. अकरकरा मूल या अकरकरा फूल को मुंह में रखकर चूस भी सकते हैं यह कण्ठ के लिए बहुत लाभकारी है.

2–कण्ठरोग–तालु, दांत और गले के रोगों में अकरकरा के काढ़े से कुल्ला करने पर बहुत लाभ होता है.

वक्ष रोग

1–हिचकी– आने पर आधा से एक ग्राम अकरकरा मूल चूर्ण को शहद के साथ चटाएं. हिचकी पर यह चमत्कारिक असर दिखता है.

2–श्वास–अकरकरा के कपड़छान चूर्ण को सूंघने से श्वास में लाभ होता है.

3–खासी–अकरकरा (2 ग्राम) एवं सोंठ (1 ग्राम) का काढ़ा बनाकर 10–20 मिली मात्रा में सुबह–शाम पीने से पुरानी खांसी मिटती है.

4–अकरकरा चूर्ण को 1–2 ग्राम की मात्रा में सेवन करने से कफज विकारों में लाभ होता है.

हृदय रोग

1–दो भाग अर्जुन की छाल और एक भाग अकरकरा मूल चूर्ण, दोनों को मिलाकर, पीसकर दिन में दो बार आधा–आधा चम्मच की मात्रा में खाने से घबराहट, पीड़ा, कम्पन और कमजोरी आदि हृद् विकारों में लाभ होता है.

2–कुलंजन, सोंठ और अकरकरा की 2–5 ग्राम मात्रा को 100 मिली पानी में उबालें, जब चतुर्थांश काढ़ा शेष रह जाए तो इस काढ़े को नियमित रूप से पिलाने से घबराहट, नाड़ीक्षीणता, हृदय कार्य शिथिलिता आधि हृद् विकारों में अत्यंत लाभ होता है.

उदर रोग

1–उदर रोग–अकरकरा मूल चूर्ण और छोटी पिप्पली चूर्ण को समभाग लेकर उसमें थोड़ी भुनी हुई सौंफ मिलाकर, आधा चम्मच सुबह शाम भोजनोपरांत खाने से उदररोगों में लाभ होता है.

2–मंदाग्नि(अफारा)– शुंठी चूर्ण और अकरकरा दोनों को 1–1 ग्राम की मात्रा में लेकर सेवन करने से मंदाग्नि और अफारा में लाभ होता है.

प्रजनन संस्थान रोग

1–मासविकार–अकरकरा मूल काढ़ा बनाकर 10 मिली काढ़े में चुटकी भर हींग डालकर कुछ माह सुबह–शाम पीने से मासिकधर्म ठीक होता है. इससे मासिकधर्म के दिनों में होने वाली पीड़ा का शासन शमन होता है.

2–इन्द्रिय शिथिलिता –20 ग्राम अकरकरा मूल को लेकर उसका चतुर्थांश क्वाथ बना लें, अब इस क्वाथ के साथ 10 अकरकरा मूल को पीसकर पुरुष जननेंद्रिय(शिश्न) लेप करने से इन्द्रिय शैथिल्यता का शमन होता है. लेप कुछ घण्टों तक लगा रहने दें, लेप लगाते समय शिश्न के ऊपरी भाग(मणी) को छोड़कर लगाएं.

अस्थि संधि रोग

1–गृध्रसी–अकरकरा के मूल चूर्ण को अखरोट के तेल में मिलाकर मालिश करने से गृध्रसी में लाभ होता है.

2–वातरोग–अकरकरा के मूल कल्क तथा काढ़े का लेप, सेंकाई, धावन आदि रूपों में बाह्य–प्रयोग करने से आमवात(एक प्रकार का गठिया), लकवा तथा नसों की कमजोरी में लाभ होता है.

त्वचा रोग

1–पामा–भारतीय अकरकरा के 5 से 7 ग्राम पंचांग का क्वाथ बनाकर प्रभावित स्थान को धोने से खुजली तथा छाजन में लाभ होता है.

2–व्रण–अकरकरा के मूलार्क को घावों में या मूल को पाउडर कर घाव के ऊपर लगाने से घाव जल्दी भरता है व संक्रमण होने की सम्भावना भी नहीं रहती है.

3–कण्डू– अकरकरा के ताजे पत्र व फूल को पीसकर लगाने से दाद, खाज तथा खुजली में लाभ होता है.

मानस रोग

1–अपस्मार–अकरकरा के फूल या जड़ को सिरके में पीसकर मधु मिलाकर 5–10 मिली की मात्रा में चाटने से मिर्गी का वेग रुकता है.

2–ब्राह्मी के साथ अकरकरा की जड़ का काढ़ा बनाकर पिलाने से मिर्गी में लाभ होता है. मिर्गी में मोरक्को वाली अकरकरा ज्यादा कार्य करती है.

3–मंदबुद्धि–अकरकरा मूल और ब्राह्मी को समान मात्रा में लेकर चूर्ण बनाएं, इसको आधा चम्मच या लगभग 1–2 ग्राम लेकर शहद के साथ मिलाकर नियमित सेवन करने से बुद्धि तीव्र होती है.

4–हकलाना– 2 भाग अकरकरा मूल चूर्ण, 1 भाग काली मिर्च व 3 भाग बहेड़ा छिलका लेकर पीसकर रखें, उसे 1–2 ग्राम की मात्रा में दिन में दो से तीन बार शहद के साथ बच्चों को चटाने से टॉन्सिल में लाभ होता है. जिह्वा पर मलने से जीभ का सूखापन और जड़ता दूर होकर हकलाना या तोतलापन कम होता है. 4–6 हफ्ते या कुछ माह तक प्रयोग करें.

5–पक्षाघात–अकरकरा मूल को बारीक पीसकर महुए के तेल या न मिलने पर तिल के तैल में मिलाकर प्रतिदिन मालिश करने से पक्षाघात(लकवा) में लाभ होता है.

6–अकरकरा मबल चूर्ण(500 मिग्रा–1ग्राम) को मधु के साथ प्रात: सायं चाटने से पक्षाघात(लकवा) में लाभ होता है.

7–अर्दित–उशवे के साथ अकरकरा का 10–20 मिली क्वाथ करके पिलाने से अर्दित(मुंह का लकवा) में लाभ होता है.

8–अकरकरा चूर्ण और राई के चूर्ण को बारीक पीसकर, मिलाकर प्रतिदिन मालिश करने से अर्धांगवात में लाभ होता है. यदि शरीर में शुष्कता ज्यादा हो या बाल झड़ते हों, तब थोड़ा राईं का तैल भी मिलाकर मालिश करें. यह अनुभूत व अत्यंत लाभकारी प्रयोग है.

9–अकरकरा मूल को धीरे–धीरे चबाने से अर्दित में लाभ होता है. 1 से 2 ग्राम सूक्ष्म चूर्ण को शहद में मिलाकर या गर्म पानी में सुबह–शाम लेने से अर्दित में लाभ होता है.

10–अपस्मार–अकरकरा के मूल चूर्ण को प्रतिदिन दो बार मधु के साथ सेवन करने से मिर्गी में लाभ होता है.

सर्वशरीर रोग

1–ज्वर–अकरकरा की जड़ के चूर्ण को जैतून के तैल में पकाकर मालिश करने से पसीना आकर बुखार उतर जाता है. आवश्यकता के अनुसार यह प्रयोग कई दिन तक किया जा सकता है.

2–अकरकरा के 500 मिग्रा चूर्ण में 4–6 बूंद चिरायता अर्क मिलाकर सेवन करने से बुखार में अत्यंत लाभ होता है.

3– 1 ग्राम अकरकरा मूल, 5 ग्राम गिलोय तथा 3–5 पत्र तुलसी को मिलाकर काढ़ा बनाकर दिन में 2–3 बार देने से जीर्ण ज्वर, बार–बार होने वाले बुखार व सर्दी लगकर आने वाले बुखार में अत्यंत लाभ होता है.

4–अकरकरा से निर्मित ज्वरघ्नी गुटिका का सेवन करने से ज्वर में लाभ होता है.

रसायन वाजीकरण

1–वाजीकरण–अश्वगंधा, सफेद मसूली तथा अकरकरा मूल को समान भाग लेकर महीन पीसें. नित्य प्रात: व सायंकाल एक–एक चम्मच एक कप दूध के साथ लेने से इसका प्रभाव वाजीकारक होता है.

2–1 ग्राम आकारकरभादि चूर्ण में मधु मिलाकर सेवन करने से यह शुक्र का स्तम्भन करता है.

प्रयोज्यांग: पुष्प, पंचांग एवं मूल

मात्रा : स्वरस 5–10 मिली, पुष्प 1–2 ग्राम.

प्रशस्त(उत्तम) अकरकरा के लक्षण–प्रशस्त अकरकरा भारी (वजनदार) और तोड़ने पर भीतर से सफेद होती है. यह स्वाद में अत्यंत तीक्ष्ण होती है. इसको चबाने से मुख और जीभ में बहुत तेज और एक विचित्र ढ़ंग की सनसनाहट होने लगती है तथा मुंह का शोधन हो जाता है. जो अकरकरा वजन में हल्की, तोड़ने पर अन्दर कुछ पीला या भूरापन लिए होती है तथा इसकी झनझनाहट कम और थोड़ी–देर तक होती है, वह अकरकरा औषधि कार्य हेतु अप्रशस्त होती है.■

आचार्य बालकृष्ण

आज उमोजा गांव में सिर्फ वही महिलाएं रहती हैं,जो बाल विवाह, खतना प्रथा, घरेलू हिंसा और बलात्कार जैसी यातनाओं के चलते घर छोड़ देती हैं. इस गांव में दूर–दूर तक ज्यादा लोग नहीं दिखेंगे. इस गांव में सिर्फ 200 बच्चे हैं, जिनके पढ़ने के लिये अलग से स्कूल भी खोला गया है. यह स्कूल महिलाओं की तरफ से ही खोला गया है. यहां पर रहने वाली नाराकोचोम का कहना है कि हर रोज वो उठती हैं और खुद के लिए मुस्कुराती हैं. यहां के लोग अपनी आजीविका के लिए कुटीर उद्योगों पर निर्भर रहते हैं.

अख़बारों की नज़र में मोदी का यूएई दौरा

वसीम अहमद

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का यूएई दौरा काफ़ी दिनों तक लोगों में चर्चा का विषय रहेगा. 34 वर्ष के लंबे अंतराल के बाद भारत का कोई प्रधानमंत्री यूएई गया था. दौरे के दौरान भारत सरकार और यूएई की सरकार में कई बिंदुओं पर समझौते हुए. यूएई दुनिया भर के अमीरों का एक ट्रेड यूनियन है. मोदी ने यूएई के इस महत्व को समझा. यही कारण है कि मोदी ने अपने दौरे में इस बात की भरपूर कोशिश की कि यूएई भारत में अधिक से अधिक निवेश करे. अबुधाबी अथॉरिटी के पास निवेश के लिए 800 बिलियन डॉलर और दुबई निवेश प्राधिकरण के पास 500 बिलियन डॉलर का फंड निवेश के लिए आवंटित है. काफी हद तक मोदी की कोशिशें सफल हुईं और यूएई के निवेशकों ने भारत में 4.50 लाख करोड़ रुपये निवेश करने पर दिलचस्पी दिखाई है.

भारत–यूएई संबंध

यूएई आर्थिक दृष्टि से भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है. यह देश कुछ वर्ष पहले तक भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक सहयोगी था, लेकिन अब अमेरिका और चीन के बाद तीसरे पायदान पर है. दोनों देशों के बीच 2013 में 73 बिलियन डॉलर का व्यापार था, जो घटकर अब केवल 60 बिलियन डॉलर रह गया है. इसके अलावा दुबई हमारे देश को तेल देने वाला छठा बड़ा सप्लायर है, जिसके तहत देश के कुल तेल की खपत का 9 प्रतिशत हम इससे तेल लेते हैं. 25 लाख से अधिक भारतीय वहां पर नौकरी कर रहे हैं, जो प्रत्येक वर्ष अपने देश को लगभग 12 अरब डॉलर भेजते हैं. इन अर्थों में देखा जाये तो यह देश हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है.

इंदिरा के बाद मोदी गए यूएई

1981 में इंदिरा गांधी के बाद पिछले 34 वर्षों में भारत के किसी प्रधानमंत्री ने यूएई का दौरा नहीं किया. 2013 में मनमोहन सिंह ने वहां जाने की पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन अंतिम क्षणों में यह दौरा रद्द कर दिया गया. ज़ाहिर है, भारत सरकार की ओर से यह एक बड़ी कोताही थी. नरेन्द्र मोदी ने दो दिवसीय दौरा करके इस कोताही को सुधारने की कोशिश की है. इन्होंने दुबई के मरहबा क्रिकेट स्टेडियम में 50 हज़ार भारतीयों के सामने यह बताया कि

यूएई हमारा एक मित्र देश है और हमदोनों में काफी नज़दीकी है. इसके बावजूद प्रधानमंत्री को यहां आने में 34 वर्ष लग गये, लेकिन आगे ऐसी कोई कोताही नहीं होगी.

यूएई के अख़बारों में मोदी का दौरा

यह कुछ मूल तथ्य हैं, जिसके कारण प्रधानमंत्री के इस दौरे को दोनों देशों के मीडिया में काफ़ी महत्व दिया गया. यूएई से प्रकाशित होने वाला अख़बार अलबयान लिखता है कि भारतीय प्रधानमंत्री का यह दौरा दोनों देशों के बीच विकास के नये रास्ते खोलेगा. अख़बार लिखता है कि यूएई के संस्थापक शेख़ ज़ायद बिन सुल्तान निहयान ने भारत और यूएई के बीच दोस्ती, आपसी सहयोग की जो नींव रखी थी, मोदी के दौरे से वह नींव और मज़बूत होगी. एक दूसरा अख़बार अलख़लीज लिखता है कि मोदी के यूएई दौरे के बाद निवेशकों में मेक इंडिया के तहत विभिन्न क्षेत्रों में निवेश करने का साहस बढ़ा है और जनता में बहुत से लोग, जो भारत में निवेश की संभावनाओं से परिचित नहीं थे, इनके इस दौरे के बाद उन्हें महसूस होने लगा है कि एशिया में भारत एक ऐसा देश है, जहां व्यापार के बेहतर भविष्य को तलाशा जा सकता है. एक और अख़बार अलअमारात अलयौम लिखता है कि इस दौरे ने यूएई के लोगों में भारत के प्रति नज़दीकी बढ़ाया है. अब दोनों देशों के बीच सुरक्षा, आर्थिक विकास और आपसी विश्वास में ज़बरदस्त बढ़ोत्तरी होगी. एक इलेक्ट्रॉनिक अख़बार शुऊन खलीजिया लिखता है कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का यह दौरा 34 वर्षों के दौरान दोनों देशों के बीच रिश्तों में जो ज़ंग लग गया था, उसे दूर करेगा. कई अख़बारों ने प्रधानमंत्री के इस दौरे को महत्व देते हुए इसे प्रथम पृष्ठपर प्रकाशित किया है. कुछ अख़बारों ने तो इस दौरे की ख़बर को दो दिनों पहले से ही प्रकाशित करना शुरू कर दिया था. इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यूएई के स्थानीय अख़बारों में इस दौरे को काफ़ी महत्व दिया गया और इसको सकारात्मक दृष्टि से देखा गया.

भारतीय अख़बारों में दौरे का महत्व

भारतीय उर्दू मीडिया ने जहां इस दौरे को सकारात्मक और मेक इंडिया की ओर बढ़ता हुआ क़दम बताया, वहीं यह भी कहा कि मोदी का यह दौरा पूर्व के दौरों की तरह ख़ुशफहमियों पर आधारित होगा. मोदी अब तक बहुत सारे देशों में गये, वहां के निवेशकों को भारत आने की दावत दी, लेकिन इसका कोई सकारात्मक परिणाम सामने नहीं आया. वह दुबई से 4.50 लाख करोड़ रुपये के निवेश की बात करते हैं, लेकिन क्या यह व्यावहारिक रूप से हो सकेगा, यह निश्चित नहीं है. एक उर्दू अख़बार लिखता है कि मोदी के यूएई दौरे की जितनी चर्चा की जा रही है, उतनी चर्चा किसी और दौरे की नहीं हुई. अबुधाबी में मंदिर के लिए यूएई सरकार द्वारा ज़मीन आवंटित करने की ख़बर को भी एक अखबार ने प्रकाशित की है. मोदी के यूएई में मस्जिद में जाने की घटना को एक अख़बार ने राजनीतिक रंग देने के बजाए प्रोटोकॉल का हिस्सा बताया है. बहरहाल, दोनों देशों की अख़बारों में संयुक्त रूप से यूएई दौरे को सकारात्मक दृष्टि से देखा जा रहा है और उम्मीद की जा रही है कि यह दौरा अर्थव्यवस्था को स्थिर करने की राह में एक मज़बूत क़दम साबित होगा. इस दौरे में भारत और यूएई के बीच कई अन्य महत्वपूर्ण समझौते हुए, जिनमें सैन्य प्रशिक्षण, आपसी रणनीतिक सहयोग, धार्मिक हिंसा और आतंकवाद को रोकने पर सहमति हुई. मोदी के दौरों में यह अब तक का सबसे पहला ऐसा दौरा है, जिसको दोनों देशों के मीडिया में ख़ूब कवरेज दिया गया.■

एक समय की बात है...

टाइटेनिक एक अद्भुत एहसास

चौथी दुनिया ब्यूरो

प्यार एक ऐसा एहसास है, जो बयां तो आंखों से होता है, लेकिन घर दिल में बना लेता है. यूं तो प्यार पर न जाने कितनी फिल्में बनी हैं, लेकिन प्यार का जीवंत एहसास दिखा फिल्म टाइटेनिक में. यह फिल्म उस जहाज के समुद्र में डूब जाने की घटना पर बनी थी, जो 1912 में डूबा था. 4 सितबंर, 1985 को इस आलीशान जहाज टाइटेनिक की तस्वीरें जनता के सामनेआई थीं. टाइटेनिक उस समय का सबसे भव्य पानी में चलने वाला यात्री जहाज था, जो अटलांटिक समुद्र में एक बड़े हिमखंड से टकराने की वजह से डूबा, हिमखंड से इसे काफी नुकसान पहुंचा था, जिसके कारण ये डूबा. टाइटेनिक जिस समय डूबा, उस वक्त वो 2,223 यात्रियों को लेकर साउथम्पटन जा रहा था. लेकिन होनी को कुछ और मंजूर थी. 10 अप्रैल, 1912 को टाइटेनिक ने अपनी पहली और आखिरी यात्रा की. इस हादसे में 1517 यात्रियों को भव्य टाइटेनिक जहाज सहित अपनी जान गंवानी पड़ी. लगभग दो साल टाइटेनिक जहाज को बनाने में लगे थे. जहाज के पहले तल पर एक खूबसूरत रेस्तरां भी बनाया गया था, जिसमें बनाये लजीज़ व्यंजन यात्रियों को परोसे जाते थे. दूसरे तल पर लाइब्रेरी और हेयर सैलून भी बनाये गये थे, जबकि थर्ड क्लास में सब सुविधाएं नहीं थीं. थर्ड क्लास के कमरों की चौखट–दरवाजे और फर्नीचर पाइन लकड़ी के तख्तों से बनाये गये थे. टाइटेनिक एक ब्रिटिश कंपनी हरलैंड ऐंड वोल्फ शिपयार्ड में तैयार किया गया था. पानी में खड़ा टाइटेनिक यूं लगता था, जैसे कोई राजमहल तैर रहा हो. इस हादसे को लेकर जो टाइटेनिक फिल्म बनी थी, उसमें फिल्म के निर्देशक कैमरून ने उस समय के हादसे के गवाह कुछ लोगों से भी इस फिल्म में एक्टिंग करवाई थी. यही कारण था कि फिल्म इतनी जीवंत बनी कि 1912 के हादसे की यादें एक बार फिर से दुनियावालों की नजरों में ताजा हो गई. एक बड़ी बात यह थी कि इस जहाज के बारे में कहा जाता था कि यह कभी नहीं डूबने वाला जहाज है, लेकिन प्रकृति को तो कुछ और ही मंजूर था, इसलिए यह जहाज ही नहीं डूबा, बल्कि इसने कई लोगों की जीवन लीला ही समाप्त कर दी. ■

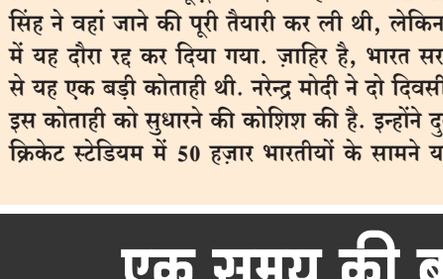

अपराधों का सरगना अल कपोन

एल्फोंसे गेब्रिएल कपोन का जन्म न्यूयॉर्क में हुआ था. गेब्रिएल अल कपोन एक अमेरिकी गैंगस्टर था, जो कपोंस नाम से जाने जाने वाले एक आपराधिक सिंडिकेट का मुखिया था. 14 वर्ष की आयु में कपोन को स्कूल से निकाल दिया गया था. उसके बाद उसने एक कैंडी स्टोर सहित कई छोटी–मोटी नौकरियां कीं. उस दौरान कपोन गैंगस्टर जॉनी टोरियो से प्रभावित था और बाद में उन्हें अपना गुरु मानने लगा. कपोन 1920 से 1931 के बीच तस्करी तथा शराब की अवैध बिक्री एवं अन्य गैर क़ानूनी गतिविधियों में संलिप्त था. उसके बिजनेस कार्ड में कथित तौर पर पुराने फर्नीचरों का एक डीलर बताया गया था. कपोन अपनी पत्नी और बेटे को छोड़कर न्यूयॉर्क से शिकागो चला गया. कपोन गैंगस्टर की ताकत का यह शक्तिशाली उदाहरण था. शिकागो अंडरवर्ल्ड के बड़े हिस्से पर नियंत्रण के कारण कपोन का काफी दबदबा था. एक अनुमान के अनुसार, उसके संगठन की सालाना आय 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर थी. यह धन वेश्यावृत्ति और जुआ जैसे सभी प्रकार के अवैध तरीकों से जुटाया जाता था. हालांकि सबसे अधिक धन उसको शराब की अवैध बिक्री से मिलता था. अपने संगठित अपराध तथा भ्रष्टाचार के बल पर कपोन का गिरोह बिना किसी क़ानूनी अड़चन के स्वतंत्र रूप से काम करता था. वह पूरे शिकागो में कैसीनो तथा शराबखाने चलाता था. 1929 और 1931 में कपोन को आयकर चोरी तथा वोल्सटीड एक्ट के कई उल्लंघनों का दोषी पाया गया. एक लंबे मुक़दमे के बाद आखिरकार उसे आयकर चोरी के कुछ मामलों में दोषी पाया गया. जज ने उसे भारी जुर्माने के साथ ग्यारह वर्षों की सजा सुनाई. 21 जनवरी, 1947 को कपोन को दिल का दौरा आया. 25 जनवरी को कपोन की मौत हो गई. 20 वीं सदी के सबसे कुख्यात अमेरिकी अपराधियों में से एक कपोन कई लेखों, पुस्तकों तथा फिल्मों का विषय भी रहा. ■

अंतरराष्ट्रीय अपराधी

संक्षिप्त खबरें

महात्मा गांधी से प्रेरित था ओसामा बिन लादेन

अलकायदा का पूर्व चीफ ओसामा बिन लादेन महात्मा गांधी से इंस्पायर्ड था. लादेन का 1993 में रिकॉर्ड किया गया एक ऑडियो टेप सामने आया है. इस टेप के मुताबिक, ओसामा अपने समर्थकों से महात्मा गांधी के ब्रिटिश रुलर्स के खिलाफ उठाए गए कदमों से सीख लेने की सलाह देता सुना गया है. ओसामा अपने समर्थकों से कहता है कि उन्हें अमेरिका में बनी चीजों का बहिष्कार करना चाहिए. 2001 में अफगानिस्तान में शुरू किए गए अमेरिकी मिलिट्री ऑपरेशन के चलते ओसामा को मजबूरी में कंधार छोड़ना पड़ा, जहां वो 1997 से डेरा डाले हुए था.

यहीं एक बिल्डिंग से करीब 1500 ऑडियो और वीडियो कैसेट्स मिले थे. एक विदेशी चैनल के मुताबिक, ये कैसट्स मैसाचुसेट्स में विलियम्स कॉलेज के अफगान मीडिया प्रोजेक्ट के पास पहुंचे थे, जिसने कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में अरबी लैंग्वेज के एक्सपर्ट प्लैग मिलर से इनकी डिटेल्स मांगी थी. टेप में ओसामा कहता है कि ब्रिटेन का मामला देखिए, इस देश का कभी सूर्यास्त नहीं होता. ब्रिटेन को भारत से हटना पड़ा, जब गांधी ने उनकी चीजों के बॉयकाट की घोषणा की. हमें आज अमेरिका के साथ भी ऐसा ही करना चाहिए.■

इस गांव में पुरुषों के आने पर पाबंदी है

एक ऐसा गांव, जहां पर पुरुषों के आने पर पाबंदी है. दूर–दूर तक यहां एक भी पुरुष नहीं दिखेगा. केन्या के उमोजा गांव में कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिलता है. उमोजा वह गांव है, जिसको वर्ष 1990 में उन महिलाओं ने बसाया था, जिनका ब्रिटिश सेना के जवानों ने बलात्कार किया था. आज उमोजा गांव में सिर्फ वही महिलाएं रहती हैं, जो बाल विवाह, खतना प्रथा, घरेलू हिंसा और बलात्कार जैसी यातनाओं के चलते घर छोड़ देती हैं. इन्हीं महिलाओं से यहां की आबादी है. इस गांव में दूर–दूर तक ज्यादा इंसान नहीं दिखेंगे. इस गांव में सिर्फ 200 बच्चे हैं, जिनके पढ़ने के लिये अलग से स्कूल भी खोला गया है. यह स्कूल महिलाओं की तरफ से ही खोला गया है. यहां पर रहने वाली नाराकोचोम का कहना है कि हर रोज वो उठती हैं और खुद के लिए मुस्कुराती हैं. यहां के लोग अपनी आजीविका के लिए कुटीर उद्योगों पर निर्भर रहते हैं. खुश रहने के लिए उमोजा गांव की महिलाएं खुद ही उत्सव मनाती हैं और आपस में खुशियां बांटती हैं. ■

हर व्यक्ति ईश्वरता से जुड़ा तो है ही, पर वह अपने अंदर उस ईश्वरीय सत्ता को पूर्ण रूप से अनुभव नहीं कर पाता. वह मन के कारण ईश्वर के माया रूप को–जो कि जगत के रूप में दिखलाई देता है, उसका अनुभव करता है और उसी में लिप्त रहता है. जब वह अपने को मन से निकाल कर अपनी आत्मा में अवस्थान करेगा, तभी वह अपनी ईश्वरता को समझ पाएगा. इसको ही आत्म–साक्षात्कार कहते हैं.

साई वंदना

बाबा की आकर्षण शक्ति

सद्गुरु के संस्पर्श, संसर्ग या संपर्क में चाहे किसी भी रूप से आने वाली प्रत्येक आत्मा को वे अपनी आकर्षण शक्ति से खींच सकते हैं. सद्गुरु लोगों को, जीवों को पिछले जीवन के ऋण–बंधन या उनके आध्यात्मिक स्तर के अनुसार अपने पास खींचते हैं. उस समय वह जीव समझता है कि वह अपनी भक्ति से गुरु के पास आ रहा है, पर वास्तव में सद्गुरु उसके भीतर अपने प्रेम–भाव को जगाते हैं, जिसको भक्त अपनी भक्ति समझता है.

डॉ. चन्द्रभानु सतपथी

श्री साई सच्चरित्र में बार–बार आत्म–साक्षात्कार शब्द का उल्लेख हुआ है. आत्म–साक्षात्कार किसे कहते हैं?

ईश्वर जगत–व्यापी है और जगत से परे भी है. यही चेतना शक्ति समस्त प्राणियों में सक्रिय है. इसीलिए हर प्राणी की आत्मा उस परमात्मा का अंश होने के कारण परमेश्वर से जुड़ी है. हर व्यक्ति ईश्वरता से जुड़ा तो है ही, पर वह अपने अंदर उस ईश्वरीय सत्ता को पूर्ण रूप से अनुभव नहीं कर पाता. वह मन के कारण ईश्वर के माया रूप का, जो कि जगत के रूप में दिखलाई देता है, अनुभव करता है और उसी में लिप्त रहता है. जब वह अपने को मन से निकाल कर अपनी आत्मा में अवस्थान करेगा, तभी वह अपनी ईश्वरता को समझ पाएगा. इसको ही आत्म–साक्षात्कार कहते हैं.

बाबा द्वारा उपदेश क्यों नहीं?

बाबा अपने भक्तों को प्राय: उपदेश क्यों नहीं देते?

बाबा भक्ति की अवस्था के अनुसार उपदेश दिया करते थे. बाबा बहुत ही सरल उपाय से सब कहते और समझाते थे, इतने सरल रूप में कि लोग उन बातों को सहजता से ग्रहण कर सकें. वे भली–भांति जानते थे कि लोग अभी समझने के लिए तैयार नहीं हैं. इसलिए जो जिस स्तर का था, उसको उन्होंने उसी के अनुरूप समझाने का प्रयत्न किया. बाबा जानते थे कि जिसको करना या पाना है, वह उनके कुछ कहे बिना भी गुरु–शरण में रहकर बहुत कुछ स्वत: समझ लेगा. जैसे म्हालसापति, काका साहेब दीक्षित सदा चुपचाप रहकर बाबा जो कुछ भी सांकेतिक रूप से समझना चाहते थे, उस पर अमल करते थे.

बाबा की आकर्षण–शक्ति

बाबा ने श्री साई सच्चरित्र में कहा है कि वे अपने भक्तों को कहीं से भी धागे में बंधी चिड़िया की तरह खींच लाते हैं. क्या सद्गुरु किसी भी व्यक्ति को खींचकर अपने पास ला सकते हैं? यह कैसे होता है?

श्री साई सच्चरित्र में देखने को मिलता है कि बाबा अपने भक्तों को प्रमाणिक रूप से काका साहेब दीक्षित, नाना चांदोरकर, श्री उपासनी लाए. सद्गुरु जो कि प्रत्येक जीव के पिछले सभी जन्मों का इतिहास जानते हैं, अपनी महत् ईश्वरीय इच्छा शक्ति द्वारा सबको आकर्षित कर लेते हैं. आदमी माया या अज्ञान से भ्रमित होकर अपनी सीमित इच्छा शक्ति द्वारा इस महान इच्छा शक्ति को रोकने का प्रयास करता है, अंततोगत्वा उसको खिंचकर सद्गुरु के पास आना ही पड़ता है. चाहे इसमें कुछ समय क्यों न लग जाए. सद्गुरु भी उस समय उसको पास खींचते हैं, जब उपयुक्त समय आता है.

साथी–आखिरकार

बाबा ने कहा था कि मैं अपने भक्तों की मृत्यु के समय उनकी आत्मा को दूर से खींच लाता हूं. क्या यह सत्य है?

सद्गुरु के संस्पर्श, संसर्ग या संपर्क में चाहे किसी भी रूप से आने वाली प्रत्येक आत्मा को वे अपनी आकर्षण शक्ति से खींच सकते हैं. सद्गुरु लोगों को, जीवों को पिछले जीवन के ऋण–बंधन या उनके आध्यात्मिक स्तर के अनुसार अपने पास खींचते हैं. उस समय वह जीव समझता है कि वह अपनी भक्ति से गुरु के पास आ रहा है. पर वास्तव में सद्गुरु के उसके भीतर अपने प्रेम–भाव को जगाते हैं, जिसको भक्त अपनी भक्ति समझता है. वह कहीं भी हो सद्गुरु उसके बारे में समस्त खबर एक सूक्ष्म प्रक्रिया से जान लेते हैं. मृत्यु के समय जब वह जीव मृत्यु–मूर्च्छा की स्थिति में आ जाता है, अर्थात अचेतन अवस्था आ जाता है, तो उसका स्थूल शरीर से संबंधित समस्त परिवार जनों से या जान–पहचान के लोगों से संपर्क कट जाता है. उसकी आत्मा मृत्यु के संधि–क्षण में एक महा–अंधकार की स्थिति में व्याकुल होकर इधर–उधर भटकती है. उस समय सद्गुरु अपने ज्योतिर्मय रूप में उसकी आत्मा के समक्ष आकर उसको शरीर के दशम द्वार से यानि ब्रह्म–द्वारा से अकर्षित करके अपने पास ले आते हैं. चूंकि उस समय और कोई साथी मृत्यु की उस आखिरी अवस्था में नहीं होता और केवल सद्गुरु ही साथ चलते हैं, इसीलिए उन्हें साथी–आखिरकार कहते हैं.■

feedback@chauthiduniya.com

धर्म

आस्था का केंद्र है गोलू देवता का मंदिर

ऐसा कहा जाता है कि यहां आने वाले लोगों को यह विश्वास होता है कि अगर आप निराश हैं या फिर आपके साथ अन्याय हुआ है तो गोलू देवता की शरण में जाने से उन्हें लाभ होगा. जिन लोगों की इसमें आस्था है, उनका कहना है कि अदालत का खर्च वहन नहीं कर पाने वाले तथा अन्याय, व विपदा से घिरे लोग इस मंदिर में अपनी चिट्ठियों से अर्जी लगाते हैं और अपने सामर्थ्य के अनुसार घंटिया चढ़ाते हैं.

कविता राना

उत्तराखण्ड की पावन धरती देवभूमि कही जाती है. कई सारे तीर्थ स्थलों और अनेक मंदिरों की वजह से इस राज्य को देवभूमि की संज्ञा दी गई है. इन्हीं मंदिरों में से एक है गोलू देवता का मंदिर. यह मंदिर न्याय दिलाने और इच्छा पूरी

करने के लिए एक अटूट आस्था का केंद्र है. गोलू देवता का मंदिर अल्मोड़ा से छह किलोमीटर दूर पिथौरागढ़ मोटर मार्ग के समीप है. मंदिर के अंदर घोड़े पर सवार, पगड़ी पहने और धनुष धारण किये गोलू देवता की प्रतिमा है. ऐसा कहा जाता है कि यहां आने वाले लोगों को यह विश्वास होता है कि अगर आप निराश हैं या फिर आपके अन्याय हुआ है तो गोलू देवता की शरण में जाने से लाभ होगा. जिन लोगों की इसमें आस्था है, उनका कहना है कि अदालत का खर्च वहन नहीं कर पाने वाले तथा अन्याय, क्लेश व विपदा से घिरे लोग इस मंदिर में अपनी चिट्ठियों से अर्जी लगाते हैं और अपने सामर्थ्य के अनुसार घंटिया चढ़ाते हैं. गोलू देवता को गोयल देवता और कुल देवता के नाम से भी जाना जाता है. लोग अपनी अटूट आस्था के अनुसार गोलू देवता को घी, दही, हलवा–पूरी और दूध चढ़ाते हैं.

यह मंदिर अल्मोड़ा से 8 किमी दूर है. यह जागेश्वर धाम रोड पर पड़ता है. यह मंदिर काठगोदाम रेलवे स्टेशन से 94 किलोमीटर दूर है. यहां से बस से मंदिर तक पहुंचा जा सकता है.■

feedback@chauthiduniya.com

अरुणाचल प्रदेश के जिरो में दुनिया का सबसे लंबा शिवलिंग

इस शिवलिंग को जिरो के स्थानीय लोगों ने पहली बार देखा था. जिसके बाद से स्थानीय लोग इसके दर्शन के लिए आने लगे और इसकी ख्याति बढ़ने लगी.

आदित्य पाण्डेय

पूर्वोत्तर भारत के अरुणाचल प्रदेश की जिरो नामक स्थान पर दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग प्रकट हुआ है जो 25 फिट लंबा है और अभी भी बढ़ रहा है और इसके ठीक बगल में पार्वती और गणेश की प्रतिमा भी है. इस शिवलिंग को जिरो के स्थानीय लोगों ने पहली बार देखा था. जिसके बाद से स्थानीय लोग इसके दर्शन के लिए आने लगे और इसकी ख्याति बढ़ने लगी. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) ने भी यहां का दौरा किया और इस शिवलिंग का अवलोकन किया.

हालांकि इस जगह को अभी भी भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा तीर्थ स्थान घोषित नहीं किया गया है. पर इसकी ख्याति राज्य और देश में बढ़ती ही जा रही है और यहां श्रद्धालुओं की भीड़ हमेशा देखी जा सकती है.■

feedback@chauthiduniya.com

साई भक्तों!

आप भी चौथी दुनिया को साई से जुड़ा लेख या संस्मरण भेज सकते हैं. मसलन, साई से आप कब और कैसे जुड़े. साई की कृपा आपको कब से मिलनी शुरू हुई. आप साई को क्यों पूजते हैं. कैसे बने आप साई भक्त. साई बाबा का जीवन और चरित्र आपको किस तरह से प्रेरित करता है? साई बाबा के बारे में अनेक किंवदंतियां हैं, क्या आपके पास भी कुछ कहने के लिए है? अगर हां, तो केवल 500 शब्दों में अपनी बात कहने की कोशिश करें और नीचे दिए गए पते पर भेजें.

चौथी दुनिया
एफ–2, सेक्टर–11, नोएडा (गौतमबुद्ध नगर), उत्तर प्रदेश, पिन–201301
ई–मेल feedback@ chauthiduniya.com

पाठकों की दुनिया

सबका साथ सबका विकास

भारत जैसे बहुभाषी, बहुधर्मी, बहुजातीय समाज में जहां सामाजिक और सांस्कृतिक एकता हमेशा संवेदनशील रही है. ऋगवेद से लेकर उत्तर वैदिक काल वाल्मीकि रामायण, महाभारत और कौटिल्य अशोक तक राजनीति का अर्थ लोकमंगल ही है. राजनीति को फिर से जनकल्याण का उपकरण बनना होगा. विरोध का उद्देश्य भी राष्ट्रहित ही होना चाहिए. संसद और सभी राजनीतिक पार्टियों पर राजनीति का वास्तविक अर्थ बहाल करने की जिम्मेदारी है. बिहार चुनाव के मुहाने पर खड़ा है और कुछ पार्टियां एक बार फिर से जाति का राग अलापने लगी हैं. भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह कहते हैं कि भाजपा ने देश को पहला ओबीसी प्रधानमंत्री दिया है. भाजपा भूल रही है कि एक वर्ष पहले 2014 लोकसभा चुनाव में उसने देश को जाति–धर्म के संकीर्ण खांचों से ऊपर उठकर सबका साथ सबका विकास के वादे के साथ केन्द्र में सरकार बनाई थी. इधर क्षेत्रीय पार्टियां सामाजिक, आर्थिक जनगणना और जातियों की बात करके मुद्दे को गर्माना चाहती हैं. अगर देखें, तो 21वीं सदी में भारतीय राजनीति बहुत मुश्किल से जाति–धर्म के जुमलों से ऊपर उठकर विकास के मुहावरे तक पहुंची है. लोगों ने ज्यादा राज्यों की मौजूदा सरकारों को भी विकास के मुहावरे से ही चुना है. हमारी नई पीढ़ी जाति धर्म के संकीर्ण के खांचे में नहीं फंसने वाली. सर्वजन का हित विचारने वाली राजनीति को उसकी नई राह पर चलने देने की जरूरत है. हर राज्य को देश को राजनीति को फिर से जाति धर्म के खाचों में कैद करने की कोशिश में लगे यथा स्थिति वाद की राजनीति करने वाले को आवाम एवं युवा वर्ग किनारे रख देगा. समाज को भड़काने का काम करने वाले बाज आएं.

–गौरव निर्मोही, *दरभंगा, बिहार.*

डॉक्टर दस साल सरकारी नौकरी करें

एक खबर पढ़ी कि मरीजों की बढ़ती भीड़ और डॉक्टरों की कमी का परिणाम यह है कि यदि आप पीजीआई में अपना इलाज़ करना चाहते हैं, तो आपका नंबर आठ महीने बाद आएगा. इसकी वजह यह है कि पांच साल तक जिस एक मेडिकल ग्रेजुएट की पढ़ाई पर सरकार लाखों रुपये खर्च करती है. वह प्रैक्टिस कर अपना नर्सिंग होम खड़ा करना चाहता है. इसलिए सरकार कानून बनाए कि प्रत्येक मेडिकल की पढ़ाई करने के बाद अनिवार्य रूप से दस साल सरकारी अस्पताल में नौकरी करनी होगी और विदेश जाने की स्थिति में उसे पूरा खर्च सरकार को वापस करना होगा.

–राजकिशोर पांडेय, *लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश.*

संसद बनी कलह मंच

भारत की संसद लोकतंत्र का पावन मंदिर है तथा देश की अभिलाषा, स्वप्न और संवाद का शीर्ष मंच है, लेकिन आज कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दलों ने उसे राजनीतिक झगड़ों का मंच बनाकर रख दिया है, सामान्यत: विपक्ष चर्चा पर बल देता है, तो सत्ता पक्ष कतराता है, लेकिन मानसून सत्र में जब सरकार बहस को तैयार थी, तो विपक्षी दल मुद्दा आधारित चर्चा से भाग रहा था, जिससे लगातार संसद की कार्यवाही बाधित रही. ऐसे में आम जनता की गाढ़ी कमाई, जो कर के रूप में जनता की जेब से आती है, संसदीय हंगामे की भेंट चढ़ रही है, अत: अब संसदीय अनुशासन को सांसद की अर्हता से जोड़ना आवश्यक है, ताकि अनुशासनहीन सासंदों पर कार्रवाई की जा सके.

–सत्यप्रकाश शिक्षक , *लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश.*

सावधानी जरूरी है

कवर स्टोरी–प्रधानमंत्री जी घोटाला होने वाला है(17 अगस्त–23 अगस्त 2015) पढ़ा. बेहद प्रभावित किया. मैं मनीष कुमार से बिल्कुल सहमत हूं कि सत्ता परिवर्तन हो जाए, प्रधानमंत्री बदल जाएं, रक्षा मंत्री बदल जाएं, लेकिन हमारे देश में कुछ चीजें ऐसी हैं, जो कभी नहीं बदल सकतीं. यह बहुत चौंकाने वाली बात है कि रक्षा सौदों में दलालों का ही राज चलता है. मोदी सरकार को बहुत सर्तकता के साथ हथियार को खरीदना चाहिए और हथियार दलालों से बचना होगा. मोदी सरकार को याद रखना चाहिए कि राजीव गांधी की सरकार पर हथियार खरीदारी में ही घोटाले का आरोप लगा था, जो बोफोर्स घोटाला के नाम से प्रचलित है. आज तक कांग्रेस पार्टी के ऊपर यह बड़ा दाग है, जिसने राजीव गांधी की छवि धूमिल कर कर रख दिया. इसलिए मोदी जी आपको हथियार खरीदने में सावधानी बरतनी चाहिए और बिचौलियों से बचना चाहिए, जिससे आपकी और आपकी सरकार की साख बची रहे.

– रवि रंजन कुमार, *लखनऊ, उत्तर प्रदेश.*

सर्वश्रेष्ठ समाचार पत्र

चौथी दुनिया समाचार पत्र का नियमत पाठक हूं. चौथी दुनिया समाचर पत्र हमेशा तथ्यों पर आधारित खबरें प्रकाशित करता है. इस समाचार पत्र में हमें पूरे सप्ताह की सभी खबरें एक साथ पढ़ने को मिल जाती हैं और ऐसे समाचार जो किसी भी समाचार पत्र में पढ़ने को नहीं मिलती. चौथी दुनिया समाचार पत्र में प्रकाशित सभी खबरें प्रभावित करने वाली होती हैं. इसमें विशेषकर संपादकीय और कवर स्टोरी पढ़कर बहुत खुशी होती है कि यह समाचार पत्र जनता की आवाज बनकर उसके हितों की आवाज उठाता है. चौथी दुनिया समाचार पत्र एक ऐसा समाचार पत्र है जो हमेशा भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों पर चोट करता है. चौथी दुनिया समाचार पत्र में पिछले कुछ दिनों में कई ऐसी खबरें प्रकाशित हुई हैं जो जनता और सरकार दोनों के हित में हैं. चौथी दुनिया समाचार पत्र निर्भीक और एक सर्वश्रेष्ठ समाचार पत्र है.■

–रितेश ओझा, *बक्सर, बिहार.*

यथार्थ से मुठभेड़ की परख

अनंत विजय

दैनिक प्रभात खबर के प्रधान संपादक हरिवंश जी राज्यसभा के सदस्य बने. उन्होंने अपने सांसद बनने के बाद के अपने व्यक्तिगत अनुभवों पर एक लंबा लेख लिखा. भारतीय राजनीति के बारे में रुचि रखनेवाले सभी लोगों को उस लेख को पढ़ना चाहिए. अपने उसी लेख में हरिवंश जी ने जॉन इलियट की किताब इंप्लोजन की चर्चा की है. हालांकि जॉन इलियट की यह किताब इंप्लोजन दो हजार चौदह में छपी थी और उसी साल उसको एशियन पब्लिशिंग अवॉर्ड भी मिला था. किताब चर्चित भी हुई थी.लेखक जॉन इलिएट ने लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत के बाद इस किताब को फौरन अपडेट किया और नई भूमिका और नरेन्द्र मोदी पर एक चैप्टर लिख डाला.

इसके बाद इस साल इस किताब का परिवर्धित और परिमार्जित संस्करण प्रकाशित हुआ. लगभग पांच सौ पृष्ठों की यह किताब आजादी के बाद के भारतीय राजनीति के विकासक्रम को समझने का बेहतर आधार प्रदान करती है. इस किताब को पढ़ते हुए एक बार फिर से दिमाग में वही बात कौंधी कि क्यों हिंदी में इस तरह के लेखन नहीं हो पाता है. क्यों हिंदी में राजनीति और समाज पर गंभीर लेखन की कमी है. इसके बहुत कारण हैं, लेकिन हिंदी के लिए यह स्थिति अप्रिय है, हिंदी वालों के लिए शर्मनाक. खैर यह एक अवांतर प्रसंग है जो विस्तार से चर्चा की मांग करता है.

भारत को जब आजादी मिली थी तब जवाहरलाल नेहरू जी ने आधी रात को अपने ऐतिहासिक भाषण में ट्रायस्ट विद डेस्टिनी का जुमला इस्तेमाल किया था, जॉन इलियट ने अपनी किताब का नाम उससे ही प्रेरित होकर इंप्लोजन, ट्रायस्ट ऑफ रियलिटी यानि यथार्थ से मुठभेड़ करार दिया है. अपनी इस किताब को जॉन इलियट ने साथ अध्याय में बांट कर भारतीय राजनीति को देखा है. दरअसल जॉन इलिएट लंबे समय से भारत की राजनीति को बेहद करीब से देख रहे हैं. उनकी इस किताब को लिखने की भी बेहद दिलचस्प कहानी है. जॉन इलिएट ने लिखा है कि अस्सी के दशक में जब लंदन के एक अखबार की दिल्ली की उनकी पोस्टिंग खत्म हुई तब से ही वो भारत के बारे में, यहां की बदलती राजनीति के बारे में लेख लिखना चाहते थे. उनकी ये योजना दो हजार सात तक परवान नहीं चढ़ पा रही थी. दो हजार सात में उन्होंने राइडिंग द एलिफेंट के नाम से एक ब्लॉग लिखना शुरू किया. उनका दावा है कि इस ब्लॉग को लिखने के क्रम में ही उनको इस किताब को लिखने के लिए जरूरी जमीन मिली. इंप्लोजन का मतलब होता है – भीतर ही भीतर फूटना या अंत: विस्फोट.

अब अगर हम भारतीय राजनीति के नजरिए से देखें तो यह किताब उसको भीतर ही भीतर खोखला होते जाने की कहानी भी कहती है. इस किताब की एक खास बात और है कि ज्यादातर रेफरेंस उनके व्यक्तिगत

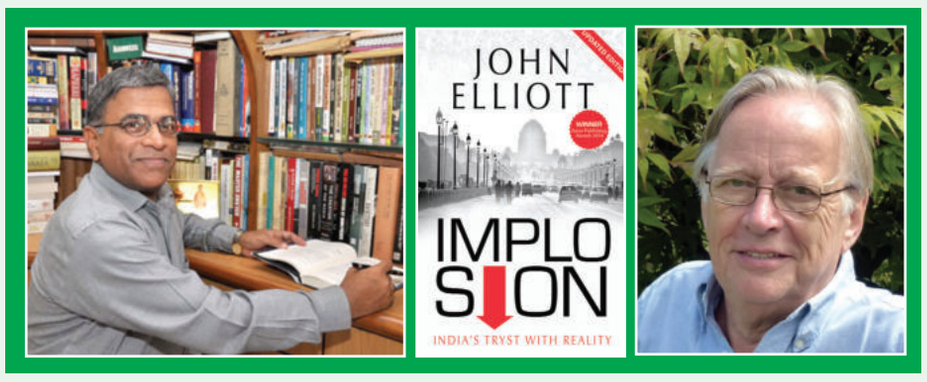

साक्षात्कार से तो हैं ही भारतीय मीडिया में छप रहे लेखों को भी इलियट ने बहुलता से अपनी किताब में सुविधानुसार उपयोग किया है. इन संदर्भों की वजह से इस किताब की उपयोगिता थोड़ी बढ़ जाती है. लगभग ढाई दशक से ज्यादा वक्त भारत में गुजारनेवाले जॉन इलिएट ने अपनी इस किताब में भारतीय राजनीति और समाज में जारी जुगाड़ और चलता है की मानसिकता को उजागर किया है. इसके अलावा इलियट ने अपने तर्कों के समर्थन में योजना आयोग से लेकर कंपनियों की रिपोर्ट तक को उद्धृत किया है.

इस पूरी किताब के केंद्र में या यों कहें कि पूरी किताब में जो एक अंतर्धारा चलती है वो यह है कि भारत की राजनीतिक व्यवस्था में नेताओं और अफसरों कॉरपोरेट के गठजोड़ ने देश का बेड़ा गर्क कर दिया. इस गठजोड़ ने ना केवल देश को लूटा बल्कि देश की प्राकृतिक संपदा भी डाका डाला और गरीबों को उनके अधिकारों से सालों तक वंचित रखा और इस वक्त भी उनको उनके हक से दूर रखने में ये गठजोड़ बहुत हद तक कामयाब रहा है. अपनी इस किताब में इलियट भारतीय राजनीति में वंशवाद की लहलहाती फसल की तरफ भी इशारा करते हैं और यह बताते चलते हैं कि किस तरह से प्रजातंत्र में राजनीतिक वंशवाद चल रहा है और अपनी विरासत अपने उत्तराधिकारी को सौंपने के लिए चालें चली जाती हैं.

जॉन इलियट इस बात का भी विश्लेषण करते हैं कि प्राकृतिक और मानवीय संपदा से भरपूर होने के बावजूद किस तरह से इस देश में अपेक्षा के मुताबिक काम करना मुश्किल है. लोगों की आकांक्षाएं जरूर हिलोरें लेती हैं लेकिन जल्दी ही उनका मोहभंग हो जाता है. जॉन इलियट इस बात का संकेत करते हैं लेकिन विस्तार में नहीं जाते हैं कि किस तरह से भारतीय राजनीति में जनता की इसी आकांक्षा को भुनाकर आजादी के बाद कई बार राजनीतिक दलों ने सत्ता पर कब्जा जमाया. इस देश में ज्यातार चुनाव और राजनीतिक जंग परसेप्शन के आधार पर लड़े और जीते जाते रहे हैं. नारों और जुमलों ने कई सरकारें बनवाई और गिरवाईं. बस नारे के क्लिक करने की जरूरत होती है. ज्यादा पीछे नहीं जाते हुए अगर हम देखें तो इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ के नारे पर कई चुनाव जीते, राजा नहीं फकीर है के जुमले पर वीपी सिंह देश के पीएम बने. सुशासन बाबू का तमगा लगाकर नीतीश लगातार चुनाव जीतते रहे हैं. मजबूत शासन देने के दावे और वादे पर नरेन्द्र मोदी पहली बार बीजेपी को केंद्र में बहुमत दिलवाया. नरेन्द्र मोदी ने जिस तरह की जुमलेबाजी पिछले लोकसभा चुनाव में की और सफलता हासिल की वो राजनीति शास्त्र के छात्रों के लिए शोध का विषय हो सकता है. उसी तरह से दिल्ली विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग का एलान कर सत्ता पर ऐतिहासिक बहुमत से काबिज हुए.

द इंसाइक्लोपीडिया ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस (1978–83) के पच्चीसवें खंड में इंदिरा गांधी ने कहा था कि – कांग्रेस अपने डायनमिक प्रोग्राम्स और आम जनता से जुड़ी नीतियों की बदौलत ही अपने आपको बचा सकती है. हम कांग्रेस के सरवाइवल के लिए तो लड़ ही रहे हैं, लेकिन भारत की जनता की लड़ाई भी लड़ रहे हैं. अब यहां भी यह साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से इंदिरा गांधी ने बेहद चतुराई के साथ अपनी लड़ाई को जनता की लड़ाई बताई. नतीजा यह हुआ कि इमरजेंसी के बाद सतहत्तर के चुनाव में बुरी तरह से मात खानेवाली कांग्रेस अस्सी में बहुमत से सरकार में आई. तो भारतीय राजनीति में, खासकर चुनाव में बहुत कुछ भावनात्मक स्तर पर होता है. भावना के इस निर्माण के कई कारक होते हैं जिसपर इस किताब इंप्लोजन में इसके लेखक ने प्रकाश डाला है.

राजनीति के अलावा इस किताब में भारत के आर्थिक इतिहास का विश्लेषण भी किया गया है. 1991 में जब भारतीय अर्थव्यवस्था खुल रही थी या ये कहें कि जब भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार शुरू हुए थे तो लेखक उसका गवाह रहा. इस किताब के दूसरे अध्याय ओपनिंग अप की शुरुआत बेहद दिलचस्प तरीके से होती हैं. 21 जून 1991 में जब नरसिम्हा राव ने अपनी सरकार बनाई तो अपने एक उच्चाधिकारी से उन्होंने छूटते ही कहा था – हमें इस मकड़जाल से बाहर निकलना हैं. उन्होंने मनमोहन सिंह से कहा था कि आप अपने दफ्तर जाएं और इसके बारे में कार्ययोजना बनाएं. नरसिम्हा राव की यही बात या कहें कि प्रधानमंत्री का यही आदेश भारत में आर्थिक सुधार की बुनियाद बना. उस वक्त राव के दफ्तर में काम करनेवालों को ये एहसास नहीं था कि वो देश पर कितनी बड़ी छाप छोड़ने जा रहे हैं. जब नरसिम्हा राव ने देश की बागडोर संभाली थी तो देश की अर्थव्यवस्था बदहाल थी. विदेशी मुद्रा भंडार आश्चर्यजनकर रूप से कम था. विदेशी निवेश के नाम पर लगभग शून्य की स्थिति थी. इस अध्याय में इलियट ने विस्तार से इसके शुरू होने की ऐतिहासिक वजहों पर लिखा है. उस दौर को जानने के लिए यह अध्याय एक जरूरी दस्तावेज की तरह हैं. आर्थिक सुधार के दौर से लेकर यह यूपीए 2 के शासन काल तक की आर्थिक गतिविधियों को परखते हैं और सोनिया गांधी और उनके पुत्र राहुल गांधी की छाप को इन नीतियों पर रेखांकित करते चलते हैं.

किताब का एक और महत्वपूर्ण चैप्टर सोशल चेंज है जिसमें लेखक दिल्ली में 2012 में हुए निर्भया कांड के खिलाफ उठे जनज्वार से शुरूआत करता है और फिर लोकतंत्र में विरोध के अधिकार पर विस्तार से बात करता है. चूंकि लेखक लंबे समय तक रिपोर्टर रहा है लिहाजा जब वो आंखों देखी कहता है तो उसमें खबर के साथ साथ सामाजिक बदलाव को भी पकड़ता है. घटनाओं के मार्फत चीजों को देखने का नजरिया इस अध्याय को प्रामाणिक बना देता है. जैसा कि उपर संकेत किया गया है कि इलियट ने राजनीतिक वंशवाद पर विस्तार से लिखा है. डायनेस्टी के नाम से लिखे अध्याय में मुख्यत वो गांधी नेहरू परिवार पर ही अपना फोकस रखते हैं. सोनिया के काल को परखते हुए राहुल के आगमन की आहट को भांपने की कोशिश करते हैं. सोनिया पर इलियट लिखते हैं कि उन्होंने अपने इर्द गिर्द एक ऐसा घेरा बना लिया है कि कोई भी उनपर व्यक्तिगत हमले करने से बचता हैं. 2004 से लेकर करीब करीब 2010 तक तो सोनिया की यही स्थिति थी. इस बात के लिए सोनिया गांधी को दाद तो देनी ही होगी कि जब कांग्रेस अपने पतन काल में थी तो उन्होंने आगे बढ़कर संभाला और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे कद्दावर नेता के रहते भारतीय राजनीति में ना केवल अपनी जगह बनाई बल्कि अपनी पार्टी को सत्तारूढ़ भी करवाया. फिर अगले दस साल तक कांग्रेस केंद्र की सत्ता पर काबिज रही.

जॉन इलियट की किताब इस लिहाज से अहम है कि इसमें उस दौर की सारी घटनाएं जीवंत हो जाती है. इस किताब के अंत में लेखक ने अपने निष्कर्ष दिए हैं जिसमें वो भारतीय लोकतंत्र की सफलता को तो स्वीकार करते हैं लेकिन लोकतंत्र की कमियों को भी उजागर करते हुए अपने तर्कों के आधार पर उसको साबित करते चलते हैं. कुल मिलाकर देखें तो यह किताब एक शोध की तरह है लेकिन बोझिल नहीं.

(लेखक IBN7 से जुड़े हैं)

anant.ibn@gmail.com

साहित्यकार

चार्ल्स डिकेंस विक्टोरियाई युग के चर्चित साहित्यकार थे. उनकी प्रसिद्ध रचनाओं में ग्रेट एक्सपेक्टेशन्स, पिकविक पेपर्स और ओलिवर ट्विस्ट हैं. उनकी लोकप्रियता का आलम यह था कि उस समय ब्रिटेन में लोग उनके उपन्यास का परिवार के सामने पाठ करते थे.

नई किताब

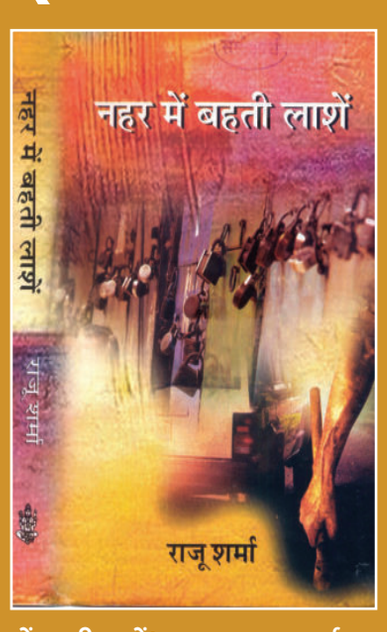

'नहर में बहती लाशें' कथाकार राजू शर्मा का नया कहानी–संग्रह है. अपनी कहानियों से राजू शर्मा ने जो ख्याति अर्जित की है, उसे कई अर्थों में खास कहा जा सकता है.

पुस्तक–समीक्षा

अध्यात्म से समाजशास्त्र और राजनीति तक की यात्रा कराता है ब्रह्मास्त्र

डॉ. अनिल सुलभ

आशीष भारती एक ऐसे लेखक हैं, जिनपर सांख्य–योग के प्रवर्त्तक महर्षि कपिल का गंभीर प्रभाव है. विद्वानों ने माना है कि सांख्य–दर्शन मानव–मस्तिष्क की क्षमता का अब तक का श्रेष्ठतम उपयोग का फ़लित है. इसमें मानवीय बौद्धिक–क्षमता की अद्भुत शक्ति को देखा और समझा जा सकता है. लेखक की मान्यता है कि सांख्य–दर्शन अंतिम दर्शन है. इसके आगे कोई विचार हो नहीं सकता.

इस संबंध में सांख्य–दर्शन की ठीक–ठीक समझ रखने वाले विद्वान, जो अन्य दर्शनों के प्रखर अध्येता और चिंतक हों, वे ही इस संबंध में स्थिर मत दे सकते हैं. किंतु मेरी दृष्टि में, किसी भी संबंध में, किसी भी बात को अंतिम मान लेना, आगे की संभावनाओं को सदा–सदा के लिये समाप्त कर देना है. अस्तु विचारों में नयापन का होना, काल की गति की सापेक्ष–दृष्टि का परिचायक है, और वांछित भी.

नोवेल्टी एण्ड कम्पनी से से प्रकाशित पुस्तक ब्रह्मास्त्र में, लेखक ने अपनी बौद्धिक–क्षमता का प्रयोग, अपने संचित ज्ञान और भारत के विगत एक हज़ार वर्षों के इतिहास के अध्ययन के आधार पर, एक निराले ही अंदाज में करते हुए, भारत की वर्तमान समस्या को समझने की कोशिश की है. समस्याओं के निदान के प्रसंग में कुछ स्पष्ट मार्ग देने के प्रयास में लेखक अवश्य सफ़ल नही दिखते हैं, किंतु अपनी सीमाओं में, उन्होंने समस्याओं की पड़ताल करने का प्रयास अवश्य किया है.

लेखक की मान्यता है कि भारतीय संस्कृति की मूल–शक्ति, उसका वैदिक–ज्ञान है. इसी ज्ञान को महर्षि कपिल ने सांख्य–दर्शन के रूप में और परिस्कृत रूप में रखा, किंतु इस दर्शन के गूढ़ार्थ को समझने में बाद का मनुष्य असफल रहा, अथवा इस दर्शन के संबंध में अपेक्षित रुचि नहीं दिखाई गयी. भारतीय संस्कृति की उदारता के कारण अन्य अनेक विचार और दर्शन भी भारत में, अंकुरित, पल्लवित और पुष्पित हीं नहीं फलित भी हुए. कई विचार विभिन्न मानव–जाति के भारत में प्रवेश के कारण भी आये और इन विचारों ने भी भारतीय संस्कृति में अपना स्थान बनाने में सफ़लता प्राप्त की. यह भारतीय संस्कृति की विशेषता है कि इसने अपना स्वरूप सामासिक रखा और अन्यविचारों के प्रति सहिष्णु भी रही. भारत की इसी विशालता ने संसार के सभी विचारों को अपने में समेट लिया और सबके मेल से इसकी विशाल सामासिक संस्कृति और अधिक परिस्कृत हुई.

किंतु लेखक का मत है कि, भारत की इसी उदार दृष्टि ने, अनेक ऐसे विचारों को भी भारत में प्रवेश का मार्ग प्रदान कर दिया, जिससे इस राष्ट्र की बड़ी क्षति हुई और आज भी हो रही है. लेखक का यह विचार संकीर्णतापूर्ण परिलक्षित होता है. लेखक के इन विचारों से पूरी तरह सहमत नहीं हुआ जा सकता, किंतु वर्णित परिस्थिति में उनका तर्क कुछ सीमा तक इस पर विचार करने का आग्रह अवश्य रखता है.

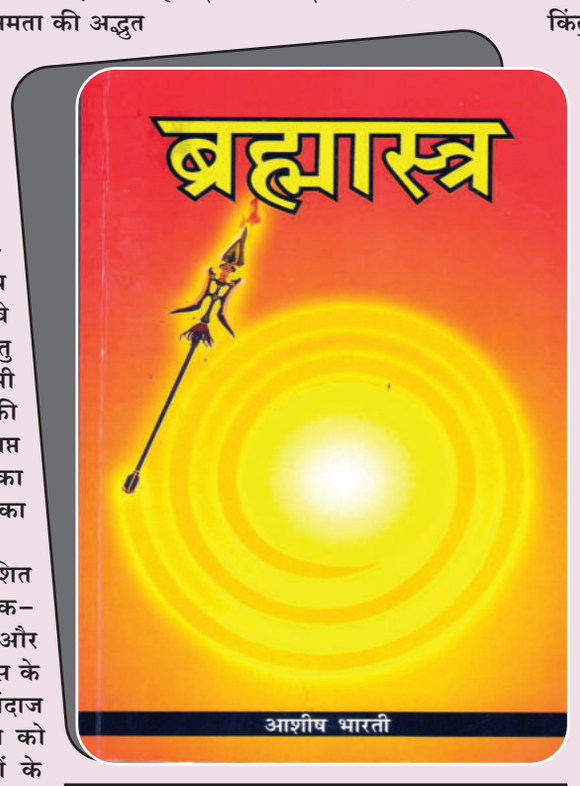

पुस्तक का नाम : ब्रह्मास्त्र
लेखक : आशीष भारती
प्रकाशक : नोवेल्टी एण्ड कम्पनी, पटना

अत्यंत बौद्धिक–चिंतन का संदर्भ और तदनुरूप भाषा का प्रयोग पुस्तक के अनुकूल कहा जा सकता है, किंतु अनेक–स्थलों पर वर्ण–संयोजन की भूल भी मिलती है. किसी विद्वान से वर्ण–संयोजन की त्रुटियां दूर कर इसका प्रकाशन किया गया होता तो सुधी पाठकों को पुस्तक और आकर्षक लगती. लेखक के निराले ढंग का प्रभाव भी इस पुस्तक के कलेवर और तेवर में दिखाई देता है. कुल 288 पृष्ठों की पुस्तक एक मात्र अध्याय में पूर्ण की गयी है. मूल शीर्षक के अतिरिक्त न तो इस पुस्तक में कोई एक भी उपशीर्षक है और न ही खण्ड–विराम. यही कारण है कि, कई प्रसंगों में पुनरावृत्ति भी मिलती है.

कुल मिलाकर यह पुस्तक, भारत की आध्यात्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनैतिक संदर्भों के साथ इसकी अनमोल चिंतन–धारा को समझने में सहायक है और प्रबुद्ध पाठकों के लिये प्रचूर सामग्री भी प्रदान करती है. इस दृष्टि से इस पुस्तक को मूल्यवान और लाभकारी माना जा सकता है.■

feedback@chauthiduniya.com

ग़ज़ल...

है अजीब सा तेरा शहर भी,
नहीं जानता तेरा नाम है.

मेरा क्या बनेगा ऐ आशना,
मेरा कुछ दिनों का क़याम है.

तुझे सोच लूं या कहूं ग़ज़ल,
नहीं फर्क दोनों ही बात में.

तू रदीफ़ है–तू ही क़ाफ़िया,
तू ही ज़िंदगी का कलाम है.

कहां मुझसे अब कोई राबता,
ना मुहब्बतें ना अदावतें.

हां मगर, ये फिर भी जान लो,
मेरा इस गली में मकान है.

कहां चांद ओ सूरज से मेरा,
कोई सिलसिला कोई वास्ता.

तेरी जुल्फ़ कांधे पे हो तो दिन,
तेरी ज़ुल्फ चेहरे पे, शाम है.

ये शरीफ़ सोहबतें छोड़ दो,
गर चाहिए तुम्हे रास्ता.

या जहां खड़े हो खड़े रहो,
यही इस शहर का निज़ाम है.

कभी हम्द उनका अज़ीज़ था,
कभी कुर्बतों का उसूल था.

मगर आज उनको ख़बर नहीं,
ये मज़ार किसकी मज़ार है.

जमशेद क़मर सिद्दीकी पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं. वे रेडियो सिटी के लिए भी काम कर रहे हैं.

feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया की हर खबर अब आपके Android फोन पर भी उपलब्ध,
Play Store से Download करें | CHAUTHI DUNIYA APP

फोर्ड फिगो एस्पायर की शुरुआती कीमत महज 4,89,990 रुपये तय की गई है. कंपनी ने इस कार में सभी आधुनिक फीचर्स और तकनीक को शामिल किया है, जो एक मिड लेवल सिडान को बेहतर बनाते हैं. कंपनी ने अपनी इसी कार को 4 ट्रीम वैरिएंट को 3 अलग–अलग इंजन ऑप्शंस के साथ बाजार में उतारा है. यानी कि ग्राहकों के पास इस कार को चुनने के ज्यादा विकल्प मौजूद हैं. कंपनी ने फोर्ड फिगो एस्पायर में कई शानदार फीचर्स दिए हैं : हैंडी स्टोरेज स्पेश क्वालिटी और डिजाइन, डीजल वर्जन दमदार, बेहतरीन इंटीरियर, रूमी केबिन और एसी, स्टैंडर्ड ड्राइवर और पैसेंजर एयरबैग, टॉप वैरिएंट में 6 एयरबैग.

सैर-सपाटा

सहयाद्रि की गोद में बसा है...

फूलों का स्वर्ग

अक्सर लोग घूमने के लिए किसी शांत जगह या फिर कोई ऐसी जगह की तलाश करते हैं, जो खूबसूरत और अनोखी हो. आज हम आपको एक ऐसी जगह लेकर चलते हैं, जो महाराष्ट्र में स्थित है. कास पठार महाराष्ट्र में एक छोटा गांव है, जो सहयाद्रि पहाड़ियों की गोद में बसा है और फूलों की खूबसूरती के लिए प्रसिद्ध है. अगर आप प्राकृतिक सौंदर्य के कायल

हैं तो कास पठार आपके लिए ही है. यहां पर आप फूलों की 850 प्रकार की प्रजातियां देख सकते हैं, जो आपका मन मोह लेंगी. कास पठार के दृश्य आपको कभी न भूलने वाली एक याद देगी. यहां पर आने के बाद आपको एक अलग ही प्रकार की शांति की अनुभूति होती है. अगर आपको पुराने हिन्दी फिल्मों की तरह फूलों के खेत में भागकर पार्टनर के गले लगने का शौक है तो सहयाद्रि के पहाड़ियों में बसा कास पठार इसके लिए परफेक्ट जगह है. यह महाराष्ट्र के सतारा सिटी से 22 किलोमीटर की दूरी पर है. कास पठार को 2012 में यूनेस्को द्वारा जैव विविधता स्थल घोषित किया जा चुका है, जिसके बाद यहां पर्यटकों कि संख्या में इजाफा हुआ है. अब यहां भी पर्यटक प्रकृति की सुंदरता और फूलों से ढंकी वादियों को देखने आने लगे हैं. प्रकृति प्रेमियों और फोटोग्राफर के लिए कास पठार की यात्रा स्वर्ग के समान है. यहां पर आवास और खान–पान की कोई विशेष सुविधा नहीं है, लेकिन स्थानीय निवासियों से आपको रहने और खान–पान की छोटी–मोटी जरूरतें आप पूरी कर सकते हैं. महाराष्ट्र पर्यटन के अधिकारी से जब यहां रहने और खाने–पीने की व्यवस्था के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि कास पठार में सरकार द्वारा कोई व्यवस्था तो नहीं है, लेकिन यहां से 22 किलोमीटर की दूरी पर सतारा में आप सारी सुविधाओं का आनंद उठा सकते हैं.

कब जाएं : कास पठार जाने के लिए अगस्त और सितंबर का महीना सबसे उपयुक्त है. बरसात के बाद यहां पर फूलों के ढेर सारी विविधताएं पाई जाती हैं.

कैसे जाएं : मुंबई से सतारा के लिए मुंबई–पुणे एक्सप्रेसवे जाती है, जिससे आप सतारा तक जा सकते हैं. फिर सतारा से एनएच–4 के रास्ते आप कास पठार तक पहुंच सकते हैं, जो कि सतारा से 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है. ■

मुकाम

थिएटर को बनायें करियर

अगर आपकी अभिनय में रुचि और रचनात्मक अभिव्यक्ति से दूसरों को आकर्षित करने का हुनर है तो आप बना सकते हैं थिएटर में करियर. थिएटर या रंगमंच एक कला के रूप में भारत में सदियों से मौजूद है, लेकिन थिएटर को कुछ समय पहले तक केवल शौक के लिए की जाने वाली एक्टिविटी के तौर पर देखा जाता था, करियर के तौर पर नहीं, लेकिन पुरानी बातें, सोच–विचार बदले हैं और आज थिएटर को करियर के तौर पर अच्छा ऑप्शन माना जाने लगा है. कुछ साल पहले थिएटर को फुल टाइम प्रफेशन के तौर पर सोचना भी मुश्किल था, लेकिन अब थिएटर में कई मौके उपलब्ध होने के कारण यह मेनस्ट्रीम करियर बन चुका है. रंगमंच पर युवाओं की बढ़ती भागीदारी और रुचि ने इस फील्ड को काफी पॉपुलर बना दिया है. दुनियाभर में थिएटर की कई वैरायटी हैं. जैसे चिल्ड्रन थिएटर, फिजिकल थिएटर, कम्युनिटी थिएटर आदि. जिसमें आप आगे बढ़ सकते हैं. थिएटर का मतलब सिर्फ एक्टिंग ही नहीं है. थिएटर लवर्स के लिए एक्टिंग के अलावा थिएटर की कई स्ट्रीम में भी कई ऑप्शंस हैं. जैसे स्क्रिप्ट राइटिंग, लाइटिंग, थिएटर मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट, मेक–अप, स्टेज डिजाइन, साउंड डिजाइन, कॉस्ट्यूम्स, जिनमें करियर बनाया जा सकता है. ■

यहां से करें थिएटर कला की पढ़ाई

- नेशनल स्कूल ऑफ़ ड्रामा –दिल्ली
- श्रीराम भारतीय कला केंद्र – दिल्ली
- संगीत नाटक अकादमी – दिल्ली
- भारतेन्दु नाट्य अकादमी – लखनऊ
- ललित कला केंद्र – पुणे
- अकादमी ऑफ़ फाइन आर्ट्स – कोलकाता

खाना पीना

सिलाव की मिठाई खाजा

बिहारी व्यंजन केवल देख भर लेने से ही लोगों के मुंह से पानी आने लगता है, लेकिन इन व्यंजनों में स्वाद के अलावा वर्षों से चली आ रही रस्मों–रिवाज़ की भी झलक दिखती हैं. कुछ मिठाइयां तो इतनी आकर्षक होती हैं कि उन्हें देखते ही खुद–ब–खुद चखने को जी मचलने लगता है. ऐसी ही एक स्वादिष्ट और प्रसिद्ध मिठाई है सिलाव का खाजा, जो न सिर्फ बिहार में, बल्कि पूरे देश केलोगों द्वारा पसंद किया जाता है. सिलाव राज–गीर के रास्ते में एक छोटा कस्बा है, जो अपने खाजा के लिए प्रसिद्ध है. खाजा यानी जमकर खा और जा. खाजा एक ऐसी मिठाई है, जिसके बिना बिहार में कोई भी शादी पूरी नहीं होती. शादी के बाद नई–नवेली दुल्हन के पांव जब ससुराल में पड़ते हैं तो वह कई झंपोली खाजा अपने साथ लाती है और ये खाजा गांव–मुहल्ले में

कई दिनों तक बांटा जाता है. खाजा बहुत पुरानी मिठाई है. तभी तो सैकड़ों साल पहले ये कहावत बनी थी–अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सेर भाजी टके सेर खाजा. सिलाव में बने खाजे की तो बात ही निराली है. सिलाव जैसा स्वाद कहीं और के खाजे में नहीं आ पाता. यहां के खाजे के बेहतरीन होने की अपनी पहचान है. पारखी इसे अलग–अलग तरीके से पहचानते हैं. अब सिलाव के खाजे का स्वाद दिल्ली के प्रगति मैदान तक पहुंच चुका है. सिलाव के मुख्य बाजार में ही खाजे की कई दुकानें हैं. खाजा खाएं और साथ में पैक करा कर भी ले जाएं, क्योंकि ये हफ्तों रखा जा सकता है. बाकी मिठाइयों की तुलना में खाजा अभी भी सस्ता है. सिलाव में खाजा का भाव 80 रुपये किलो से लेकर 100 रुपये किलो तक है. हल्का होने के कारण एक किलो खाजा ढेर सारी जगह घेरता है. एक बार आपने खाजा खरीदा तो कई दिनों तक खा सकते हैं.

सामग्री : मैदा 1 कप
बादाम : आधा कप
पिस्ता : आधा कटोरी
घी : आधा कटोरी
मलाई : 2 कटोरी
शक्कर : आधा कटोरी
इलायची : 1–2 चुटकी
नमक : स्वादानुसार
घी : तलने के लिए

बनाने कि विधि :– मैदे को छानें. उसमें गर्म घी और नमक मिलाकर मलाई से पूरे आटे को गूंथें. 15–20 मिनट तक ढंककर रख दें. शक्कर डूबने भर पानी डालकर डेढ़ तार की चाशनी तैयार करें. अब कड़ाही में घी गर्म करें. छोटी–छोटी लोइया बनाकर पेड़े की आकृति दें. बीच में थोड़ा–सा दबाकर खस्ता तल लें. फिर मंद आंच पर तलें और तैयार चाशनी में इन्हें डुबोकर निकाल लें ऊपर से बादाम, पिस्ता, छिड़क दें फिर चांदी के वर्क से सजाकर रखें. ■

feedback@chauthiduniya.com

फैशन दुनिया

फैशन सिर्फ रैंप की ही चीज नहीं रह गई है. यह महिलाओं में आत्मविश्वास की भी कहानी बयां करती है, जो मेट्रो और छोटे शहरों की महिलाओं के परिधानों में साफ झलकता है. भोपाल स्टाइल वीक के दौरान भोपाल में रैंप पर जलवा बिखेरती मॉडल्स.

कूड़ेदान में डालो कूड़ा, पाओ मुफ्त वाईफाई कोड

मुंबई के प्रतीक और उनके पार्टनर राज देसाई ने वाई–फाई ट्रैशबिन नाम से एक नई टेकनोलोजी डेवलप की है. प्रतीक अग्रवाल ने बताया कि ट्रैशबिन में कूड़ा डालते ही कोड मिलता है, जिसकी मदद से मुफ्त में इंटरनेट की सेवा का आनंद उठाया जा सकता है। उन्होंने बताया की डेनमार्क, फिनलैंड जैसे देशों में यह कॉनसेपट बहुत पुराना पर भारत में नया है.. बेंगलूरू, कोलकाता तथा दिल्ली में सप्ताहंत के विभिन्न महोत्सवों में यह सफल रहा थिंकस्क्रीन द्वारा पोस्ट किए एक विडियो के मुताबिक डिवाइस को एमटीएस के साथ मिलकर तैयार किया गया है. इसमें रॉडस, आईआर सेंसर आदि के जरिए वाई–फाई जोन क्रिएट किया जाएगा, जिससे कूड़ा फेंकते ही सिस्टम सक्रिय हो जाएगा और यूजर्स मुफ्त इंटरनेट का आनंद ले सकेंगा. पूरी प्रक्रिया को अभी विकसित किया जाना बाकी है. ■

एलआईसी की नई एंडोमेंट प्लस योजना का शुभारंभ

एलआईसी की नई एंडोमेंट योजना की शुरुआत 18 अगस्त, 2015 को एलआईसी (उत्तर) के जोनल प्रबंधक टीटी काबुई के द्वारा की गई. इस मौके पर काबुई ने कहा कि नई एंडोमेंट प्लस योजना एलआईसी की एकमात्र यूलिप योजना है, जो फरवरी में जारी किए गए नए उत्पाद नियमों के बाद शुरू की गई. यह एक यूनिट–लिंक्ड बीमा योजना है, जो धारक को निवेश और बीमा का दोहरा लाभ देती है. यह दोहरी जोखिम को कवर करने के लाभों और निवेश बाजार को लाभ प्रदान करता है.

पॉलिसीधारक के पास उसकी पंसद सुविधा के मुताबिक बांड कोष, सुरक्षित कोष, बैलेंस कोष और विकास कोष में से किसी एक का चयन करने का विकल्प होगा. इस पॉलिसी के दौरान धारक बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के चार बार अपने विकल्प बदल सकता है.

सभी संरक्षित कोष के एनएवी (नेट एसेट वैल्यू) की गणना निवेश की स्थिति और फंड प्रबंधन शुल्क के आधार पर रोज़ाना की जायेगी. यह योजना 90 दिनों से 50 वर्ष के उम्र के लोगों के लिए होगी. ■

बाज़ार में नया

फोर्ड ने लॉन्च की फिगो एस्पायर

अमेरिकन कार निर्माता कंपनी फोर्ड ने अपनी सबसे शानदार मिड लेवल फोर्ड फिगो एस्पायर को भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया है. फोर्ड फिगो एस्पायर की शुरुआती कीमत महज 4,89,990 रुपये तय की गई है. कंपनी ने इस कार में सभी आधुनिक फीचर्स और तकनीक को शामिल किया है, जो एक मिड लेवल सिडान को बेहतर बनाते हैं. कंपनी ने अपनी इसी कार को 4 ट्रीम वैरिएंट को 3 अलग–अलग इंजन ऑप्शंस के साथ बाजार में उतारा है. यानी कि ग्राहकों के पास इस कार को चुनने के ज्यादा विकल्प मौजूद हैं. कंपनी ने फोर्ड फिगो एस्पायर में कई शानदार फीचर्स दिए हैं : हैंडी स्टोरेज स्पेश क्वालिटी और डिजाइन, डीजल वर्जन दमदार, बेहतरीन इंटीरियर, रूमी केबिन और एसी, स्टैंडर्ड ड्राइवर और पैसेंजर एयरबैग, टॉप वैरिएंट में 6 एयरबैग. स्पेश के मामले में भी ये कार काफी शानदार है. कंपनी ने ज्यादा बूट स्पेश प्रदान किया है, ताकि आप सफर के दौरान ज्यादा लगेज कार में रख सकें. यह कार अपने बेहतरीन आधुनिक फीचर्स और कम कीमत के चलते काफी प्रभावित करती है. ■

चौथी दुनिया ब्यूरो feedback@chauthiduniya.com

बैडमिंटन

हार कर भी जीतीं साइना

साइना नेहवाल को वर्ल्ड चैंपियनशिप के फाइनल में स्पेन की कैरोलिना मैरिन से हार का सामना करना पड़ा. स्पेनिश स्टार ने साइना को लगातार सेटों में 21–16 और 21–19 से हराया. लेकिन उन्होंने सिल्वर मेडल जीतकर इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करा लिया. इस हार के साथ ही साइना को सिल्वर से संतोष करना पड़ा. ऐसा पहली बार हुआ है, जब किसी इंडियन शटलर ने वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल पर कब्जा किया.

पहले गेम में वर्ल्ड नंबर वन कैरोलिना से हार का सामना करना पड़ा, लेकिन शुरुआत में पिछड़ने के बाद साइना ने जोरदार वापसी जरूर की, लेकिन स्पेनिश शटलर से 16–21 से हार गईं. इससे पहले साइना को मारिन से ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप के फाइनल में शिकस्त मिली थी.

साइना भले ही यह मुकाबला हार गई हों, लेकिन उन्होंने एक नया रिकॉर्ड जरूर कायम किया है. इससे पहले किसी भारतीय खिलाड़ी ने इस प्रतियोगिता में ब्रॉन्ज मेडल से ज्यादा नहीं जीत था. इससे पहले तक वर्ल्ड चैंपियनशिप के इतिहास में भारत के नाम चार ब्रॉन्ज मेडल थे. प्रकाश पादुकोण ने 1983 में, ज्वाला गुट्टा और अश्विनी पोनप्पा की महिला जोड़ी ने 2011 में तथा पीवी सिंधू ने 2013–14 में ब्रॉन्ज मेडल जीते थे.■

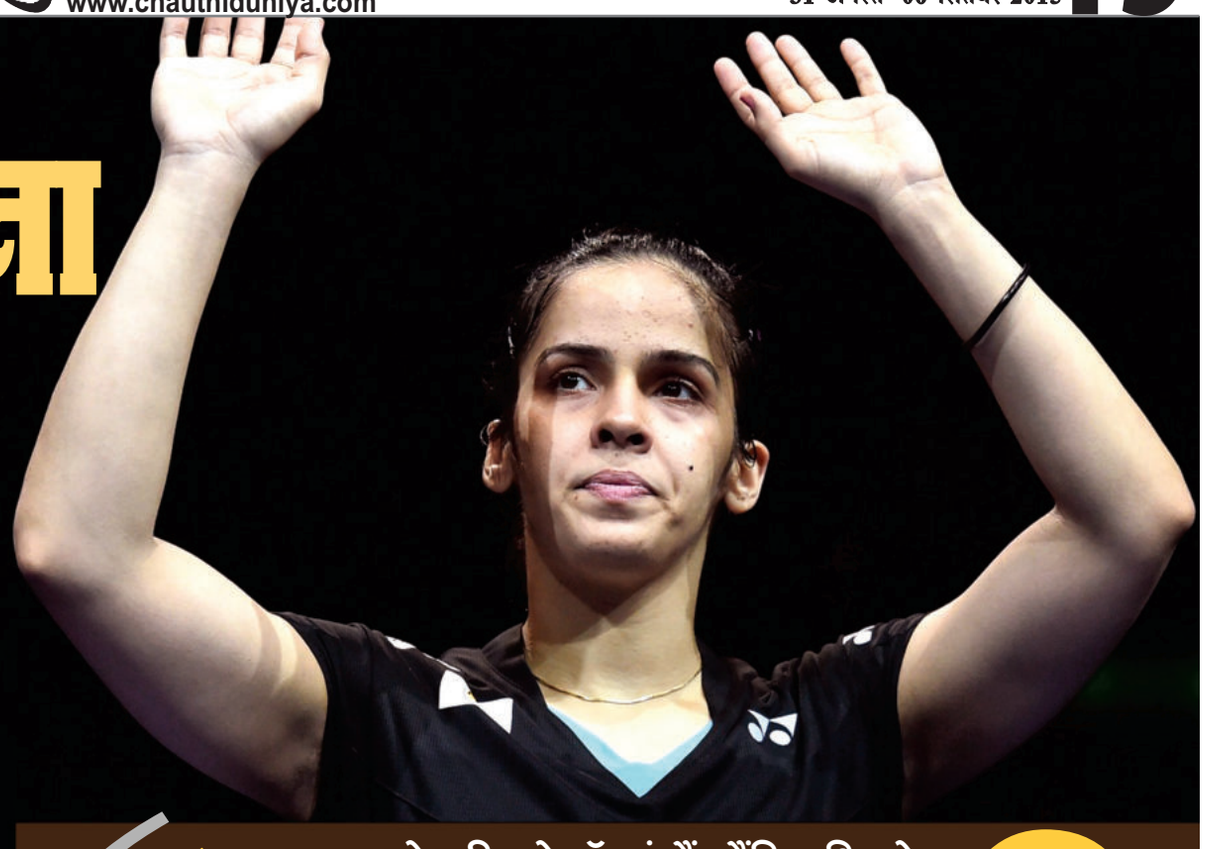

> साइना को मारिन से ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप के फाइनल में हार मिली थी. साइना भले ही यह मुकाबला हार गई हों, लेकिन उन्होंने एक नया रिकॉर्ड जरूर कायम किया है. इससे पहले किसी भारतीय खिलाड़ी ने इस प्रतियोगिता में ब्रॉन्ज मेडल से ज्यादा नहीं जीता था.

क्रिकेट

आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में अश्विन टॉप 10 में

श्रीलंका से पहले टेस्ट में मिली हार के बाद भारतीय खिलाड़ी आर अश्विन की रैंकिंग में उछाल आया है. मैच में दस विकेट लेने वाले रविचंद्रन अश्विन आईसीसी की बॉलर्स की टेस्ट रैंकिंग में टॉप 10 में जगह बनाने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं.

श्रीलंका के साथ टेस्ट मैच की पहली पारी में 6 और दूसरी पारी में 4 विकेट लेने वाले अश्विन 12वें स्थान से अब तीन स्थान उछाल के साथ नौंवें स्थान पर पहुंच गये हैं.■

कीर्तिमान

टॉप 10 टेस्ट गेंदबाज

रैंक	खिलाड़ी	देश	रेटिंग
1	डेल स्टेन	साउथ अफ्रीका	905
2	स्टुअर्ट ब्रॉड	इंग्लैंड	852
3	जेम्स एंडरसन	इंग्लैंड	815
4	ट्रेंट बोल्ट	न्यूजीलैंड	814
5	यासिर शाह	पाकिस्तान	810
6	रंगना हेराथ	श्रीलंका	771
7	वेरनॉन फिलेंडर	साउथ अफ्रीका	770
8	मिचेल जॉनसन	ऑस्ट्रेलिया	765
9	आर. अश्विन	भारत	734
10	टिम साउदी	न्यूजीलैंड	713

टेनिस

स्विस सनसनी
बेनसिच ने सेरेना को हराया

शोरी बेलिंडा बेनसिच ने डब्ल्यूटीए रोजर्स कप टेनिस टूर्नामेंट में कड़े मुकाबले में विश्व की नंबर एक खिलाड़ी सेरेना विलियम्स को हराकर फाइनल में अपनी जगह पक्की की.

यह मुकाबला टूर्नामेंट में खेल रही सबसे उम्रदराज और सबसे युवा खिलाड़ी के बीच था, जिसमें 18-वर्षीय बेनसिच ने जीत हासिल की. उन्होंने 21 बार की ग्रैंडस्लैम विजेता सेरेना को मैच में 3-6, 7-5, 6-4 से हराया.

सेरेना ने 1999 में जब अपना पहला ग्रैंडस्लैम खिताब जीता था, तब बेनसिच केवल दो साल की थीं. इस जीत से उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था. बेनसिच ने बाद में कहा कि यह अद्भुत एहसास है. इसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है.■

गोल्फ

गोल्फ खिलाड़ी अनिर्बान ने रचा इतिहास

भारतीय स्टार गोल्फर अनिर्बान लाहिड़ी ने अमेरिकी पीजीए गोल्फ चैंपियनशिप में संयुक्त पांचवां स्थान हासिल कर नया इतिहास रच दिया है. लाहिड़ी ने अमेरिकी पीजीए गोल्फ़ चैंपियनशिप में के चारों राउंड में बेहतरीन प्रदर्शन किया. उन्होंने कुल 13 अंडर पार 275 का स्कोर बनाया. इस स्कोर के साथ वे ब्रूक्स कोएपका के साथ संयुक्त तौर पर दूसरे स्थान पर रहे. अगर आखिरी होल से पहले लाहिड़ी से बॉगी की गलती नहीं हुई होती तो अनिर्बान लाहिड़ी पांचवें पायदान से भी ऊपर चढ़ सकते थे. इस कामयाबी को बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है और माना जा रहा है कि लाहिड़ी का प्रदर्शन मेजर गोल्फ चैंपियनशिप में और भी बेहतर होगा.

मलेशिया ओपन और हीरो इंडियन ओपन खिताब जीतने वाले लाहिड़ी नई रैंकिंग में शीर्ष 50 में पहुंच जायेंगे. लाहिड़ी ने कहा कि इससे मेरा आत्मविश्वास काफी बढ़ा है. मैं दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों का सामना कर सकता हूं और उनके करीब पहुंचने के लिये भविष्य में थोड़ी और मेहनत करनी होगी.■

चौथी दुनिया ब्यूरो

feedback@chauthiduniya.com

भुला न पाएंगे...

जिमी जॉर्ज

भारत में अगर खेलों पर नजर डालें तो क्रिकेट के अलावा अब तक किसी और खेल को क्रिकेट के बराबर प्रोत्साहन नहीं दिया गया है, लेकिन कई बार ऐसे खिलाड़ी हमारे सामने आते हैं, जो अपने प्रदर्शन से अपना और साथ में देश का नाम भी रोशन करते हैं. जिमी जॉर्ज भारत के वॉलीबॉल प्लेयर थे. वे 1970 में जिमी विश्वविद्यालय, कालीकट की वॉलीबॉल टीम के सदस्य बने. 1973 में जिमी सेंट थॉमस कॉलेज, पाला में शामिल हो गए. 1973 से 1976 तक जिमी ने केरल विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व किया.

उन्होंने पेशेवर तरीके से वॉलीबॉल खेलना शुरू किया और क्लब वॉलीबॉल में भाग लेने इटली भी गए थे. जिमी ने इटली में 6 सीज़न्स तक वॉलीबॉल खेला, जहां उनके प्रदर्शन की वजह से उनके बहुत सारे फैंस बने. दर्शक यह देख कर हैरान रह जाते थे कि जिमी कैसे दूसरों से ऊपर उछल कर बॉल मार देते थे. जिमी भारतीय वॉलीबॉल टीम के सदस्य थे और उन्होंने तेहरान (1974), बैंकॉक (1978) और सीओल (1986) एशियाई खेलों में टीम का नेतृत्व भी किया था. उनके प्रदर्शन की वजह से 1986 एशियाई खेलों में भारत ने वॉलीबॉल में कांस्य पदक जीता. इसके अलावा 1986 में हैदराबाद में हुए इंडिया गोल्ड कप इंटरनेशनल वॉलीबॉल टूर्नामेंट में उन्होंने भारत को स्वर्ण पदक भी दिलाया. सच में जिमी, हम आपको भुला न पायेंगे.■

एक खेल ऐसा भी...

आइस हॉकी

आइस हॉकी या बर्फ हॉकी, बर्फ पर खेला जाने वाला खेल है. जो हॉकी जैसे खेल का ही एक रूप है. इसमें प्रतिद्वंद्वी स्केटरों की मदद से छड़ी द्वारा गोल करने की कोशिश करते हैं. मुख्यतः ये खेल कनाडा एवं संयुक्त राज्य अमेरिका में खेला जाता है. आइस हॉकी सबसे पहले 19वीं सदी में कनाडा में खेला गया. इस खेल में 6 खिलाड़ियों के साथ खेला जाता है. पांच (5) स्केटरों और एक (1) गोलटेंडर.

हॉकी खेलने के लिए खिलाड़ियों को माउथ गार्ड, कंधे के लिए पैड, कोहनी पैड, हॉकी दस्ताने, हॉकी पैंट, एथलेटिक समर्थक (जॉक), शिन पैड, जुराब, जर्सी, हेलमेट की आवश्यकता होती है और साथ में हॉकी स्टिक की जरूरत होती है. सबसे पहले यह 1920 में ओलंपिक खेलों में खेला गया था. अंतर्राष्ट्रीय आइस हॉकी महासंघ बर्फ हॉकी से संबंधित कार्यक्रमों की देखरेख एवं आयोजन करता है.■

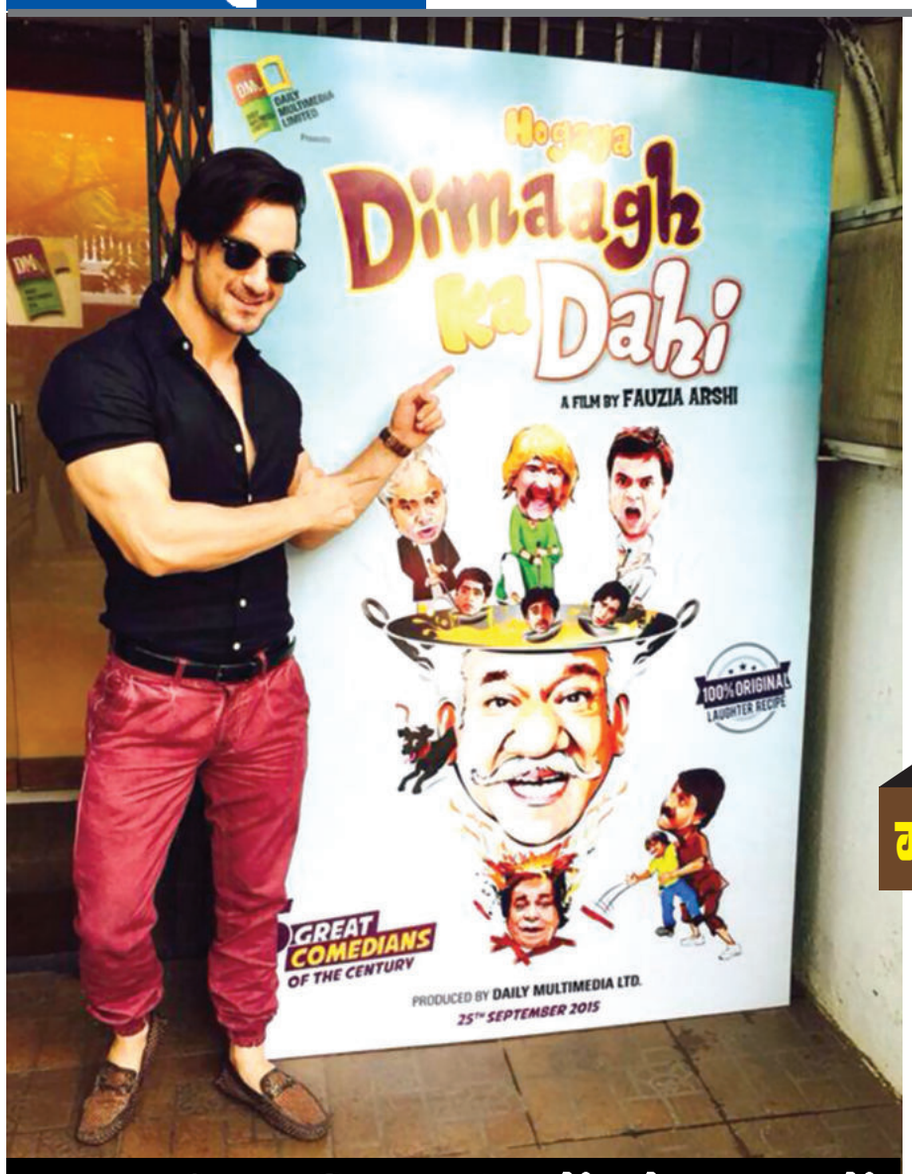

कश्मीर की वादियों से सपनों की दुनिया पहुंचे दानिश

दानिश को संजय मिश्रा, राजपाल यादव, ओम पुरी, रज़ाक खान जैसे कलाकारों के साथ पहली बार काम करने का मौका मिला है. वे कहते हैं कि फिल्म के सभी कलाकार बहुत ही मजाकिया और कॉपोरेटिव है. आप इनसे नॉर्मल बात करेंगे तो उसमें भी ये लोग ह्यूमर डाल देते हैं. कुछ न कुछ पंच लाइन निकाल देते हैं.

कश्मीरी छोरा अब मुंबई में धूम मचाने को तैयार है. अपनी फिल्म हो गया दिमाग का दही को लेकर दानिश भट्ट बेहद एक्साइटेड है. इस फिल्म के लिए उन्हें बहुत महेनत भी करनी पड़ी. वो बताते हैं कि यह बहुत ही फनी फिल्म है. ह्यूमरस फिल्म है. कोई भी बंदा जब इसे देखेगा तो हंस-हंस के पागल हो जायेगा. दानिश का इसमें छोटे भाई का किरदार है. फिल्म में इनका नाम है वीरू, जिसे लड़कियों को देखना अच्छा लगता है. वीरू का बाकी किसी चीजों पर इतना ध्यान नहीं है. वह कभी-कभी सीरियस भी हो जाता है.

दानिश इस फिल्म के डॉयलॉग के बारे में बताते हैं कि इसका हर एक डॉयलॉग पंच लाइन है. आपको मौका नहीं मिलेगा सीट से उठने का. हर पंच के बाद एक पंच मौजूद है.

दानिश को संजय मिश्रा, राजपाल यादव, ओम पुरी, रज़ाक खान जैसे कलाकारों के साथ पहली बार काम करने का मौका मिला है. वे कहते हैं कि फिल्म के सभी कलाकार बहुत ही मजाकिया और कॉपोरेटिव है. आप उनसे नॉर्मल बात करेंगे तो उसमें भी ये लोग ह्यूमर डाल देते हैं. कुछ न कुछ पंच लाइन निकाल देते हैं. दानिश कहते हैं कि उन्हें ओम जी, संजय मिश्रा, राजपाल जी से बहुत कुछ सीखने को मिला है. राजपाल यादव के बारे में वे बताते हैं कि वे तो कुछ ज्यादा ही फनी लगे मुझे. उनसे काफी बातचीत हुई. राजपाल जी हर बात को फनी बना देते हैं. उनको मैंने कभी सीरियस होते हुए सेट पर नहीं देखा है. सिर्फ हंसते और हंसाते ही देखा है. यह सबसे अच्छी चीज है.

दानिश इस फिल्म के गानों को लेकर भी काफी उत्सुक दिख रहे हैं. इस फिल्म के गानों के बारे में दानिश बताते है कि जब मैंने इस फिल्म के गाने सुने तब मैं इसे चुपचाप सुनता ही जा रहा था. इस फिल्म में एक बहुत उम्दा रोमांटिक गाना है. उस गाने से आप कहीं न कही कनेक्ट हो जाते हैं. दानिश की एक ख्वाहिश भी है. वे इंडस्ट्री की ख्याति प्राप्त अभिनेत्रियों जैसे करीना कपूर, दीपिका पादुकोण, कैटरीना कैफ के साथ काम करना चाहते हैं. वैसे दानिश पहले ही प्रियंका चोपड़ा के साथ काम कर चुके हैं. फिलहाल, दानिश को उनकी आने वाली फिल्म हो गया दिमाग का दही के लिए बेस्ट आफ लक.■

चौथी दुनिया ब्यूरो feedback@chauthiduniya.com

रेडियो पर धूम मचा रही है फिल्म

हो गया दिमाग का दही

16 अक्टूबर को रिलीज़ होने वाली फौज़िया अर्शी की फिल्म हो गया दिमाग का दही रेडियो पर अभी से हिट हो गयी है. एफ एम रेनबो (102. 6) के शो बॉलीवुड के मस्ताने पर फिल्म के लिए खेले गए क्विज़ कांटेस्ट में लोग बढ़चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं. फिल्म की पॉपुलैरिटी का अंदाज़ा फिल्म के बारे में जानने के लिए पूरे देश भर से आये हज़ारों लिसनर्स के कॉल्स से ही लगाया जा सकता है. दिल्ली मुंबई ही नहीं बंगाल, झारखण्ड, केरल, राजस्थान सहित 18 राज्यों से फ़ोन और सन्देश आये हैं. इतना ही नहीं कश्मीर और उत्तर पूर्वी राज्यों से भी लोग कॉल कर फिल्म हो गया दिमाग का दही को देखने की उत्सुकता जता रहे हैं. फिल्म के ट्रेलर और गानों को पहले ही सोशल मीडिया और टेलीविज़न पर लोगों ने काफी पसंद किया और अब रेडियो के लिसनर्स भी फिल्म की सराहना के सन्देश भेज रहे हैं. कुछ दिनों में फिल्म हो गया दिमाग का दही को रेडियो पर जिस तरह का रिस्पांस मिला है उसे देख कर यही लगता है कि लोग इस इस कॉमेडी फिल्म का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं.■

बॉलीवुड की सबसे चुलबुली स्टार आलिया भट्ट ने कहा है कि वह शादी का लड्डू चखना चाहती हैं

बॉलीवुड की सबसे चुलबुली स्टार आलिया भट्ट ने कहा है कि वह शादी का लड्डू चखना चाहती हैं. अपनी दोस्त अनुष्का रंजन की पहली फिल्म वेडिंग पुलाव के ट्रेलर लॉन्च के मौके पर कहा कि 32 साल ही शादी करने की सही उम्र होगी.

आलिया ने कहा कि अभी मैं सिर्फ 22 साल की हूं. मेरा मानना है कि वेडिंग पुलाव का स्वाद चखने की सही उम्र 32 साल होगी. मैंने शादी का लड्डू भी नहीं चखा है, इसलिए शायद मुझे इसका अफसोस नहीं होगा.

आलिया ने अपने ड्रीम पार्टनर के बारे में खुलासा करते हुए कहा कि वह ऐसे शख्स के साथ रहना पसंद करेंगी जिसका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा हो. आलिया ने बताया, उसे मुझे हंसाना आना चाहिए. उसके बाद लुक्स का नंबर आता है और सिर्फ इतना ही मायने रखता है. आलिया ने यह भी कहा कि वह कभी नहीं बताएंगी कि उन्हें कैसे इम्प्रेस किया जा सकता है. यह काम उनके पार्टनर को ही करना होगा.■

> आलिया ने अपने ड्रीम पार्टनर के बारे में खुलासा करते हुए कहा कि वह ऐसे शख्स के साथ रहना पसंद करेंगी जिसका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा हो.

चौथी दुनिया ब्यूरो feedback@chauthiduniya.com

गर याद रहे...

कमला बाईः हिन्दी सिनेमा की पहली महिला कलाकार

आज भले ही महिला सशक्तिकरण की बातें जोर-शोर से की जाती हों. लेकिन, यह एक ऐसा मसला है जो सदियों से चला आ रहा है. हर दौर में ऐसी महिलाएं रही हैं जिन्होंने स्थापित परंपराओं और मिथकों को तोड़ने का काम किया है. भारतीय सिनेमा के उस दौर में भी कमलाबाई नाम की एक महिला ने स्थापित परंपराओं और मिथकों को तोड़ने का साहस दिखाया. तमाम पाबंदियों और समस्याओं को एक तरफ रखते हुए रंगमंच की कलाकार कमलाबाई गोखले ने सन 1913 में दादा साहेब फाल्के की फिल्म मोहिनी भस्मासुर में कैमरे का सामना कर भारतीय फिल्मों की पहली अभिनेत्री बन इतिहास रच दिया. उन्होंने सिनेमा में नायिका के किरदार की ऐसी शुरुआत की जो आज भी दिलों की धड़कन बनी हुई है. कमलाबाई महज चार साल की उम्र से ही रंगमंच में अभिनय करने लगी थीं. अपनी मां के साथ कमलाबाई भी छोटी उम्र में नाटकों में काम करने लगी थीं. उसी दौरान छह महीने के लिए जब उनकी नाटक मंडली बंद हो गयी, तभी दादा साहब फाल्के ने उन्हें अपनी फिल्म मोहिनी भस्मासुर में लीड रोल दिया. उसमें उनकी मां दुर्गाबाई को भी पार्वती का रोल दिया गया.

उस फिल्म की शूटिंग के दौरान उन्हें कई मुसीबतों का सामना करना पड़ा. उस दौर में जब महिलाओं के घर से बाहर निकलने पर भी पाबंदी थी, उन मां-बेटी के फिल्म में अभिनय करने से हंगामा मच गया. अभिनय को अपनी रोजी-रोटी बना लेने के कारण उन्हें समाज से बेदखल कर दिया गया. समाज के अनुसार वह एक स्तरहीन काम कर रही थीं, जिससे महिला की गरिमा खराब होती है. दीनानाथ मंगेशकर सहित कई नामचीन चेहरों ने इसका विरोध किया. लेकिन तमाम विरोध के बावजूद कमलाबाई अभिनय करती रहीं और एक के बाद एक फिल्मों का हिस्सा बनती गयीं. एक नाटक में वे अपने पति के साथ काम कर रही थीं. नाटक के दौरान ही उनके पति की तबीयत गंभीर रूप से बिगड़ गयी. ऐसे में कमलाबाई ने बिना धैर्य खोये नाटक में महिला के साथ-साथ अपने पति के पुरुष वाले किरदार को भी निभाया था. अपने कैरियर में कमलाबाई 200 से भी अधिक नाटकों और 35 से अधिक फिल्मों का हिस्सा रही थीं. अभिनय में वे 85 साल से भी अधिक उम्र तक सक्रिय रहीं.■

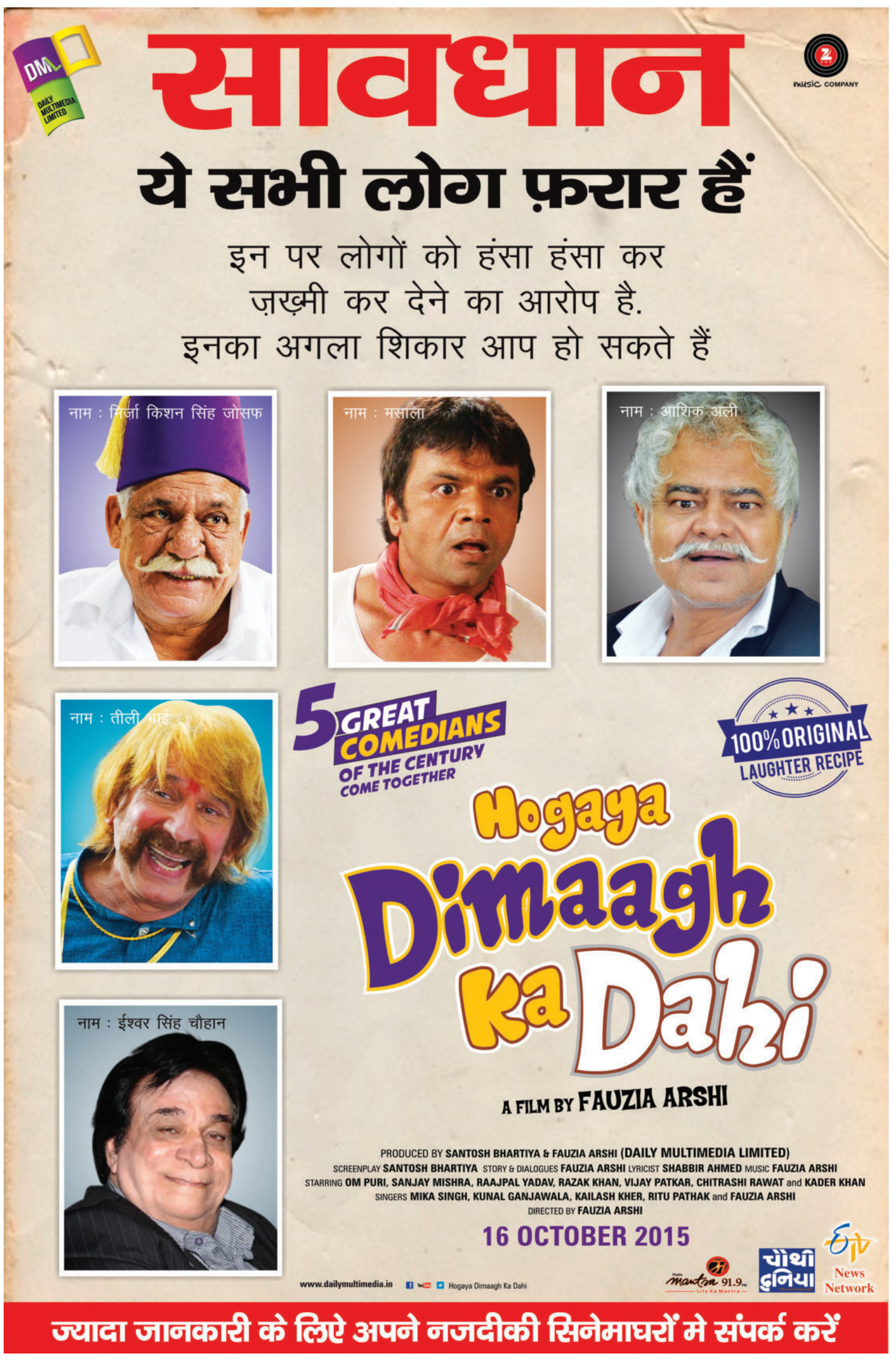

चौथी दुनिया

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

बिहार -झारखंड

31 अगस्त-06 सितंबर 2015 Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2015-17, RNI No. DELHIN/2009/30467

तलवार की धार पर एनडीए का भविष्य

- एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर पेच फंस रहा है
- पप्पू यादव को लेकर भाजपा असमंजस में है
- भाजपा 160 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है
- एनडीए में टूट की संभावना से भी इंकार नहीं

फोटो–*प्रभात पाण्डेय*

जो जैसा दिखता है, वह वैसा ही हो जरूरी नहीं. ऊपर की इस तस्वीर को देखिए, जिसमें एनडीए के सारे नेता एकजुट और प्रसन्न मुद्रा में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अंदरखाने की खबर पर भरोसा करें, तो टिकट बंटवारे के मसले पर यही नेता न एक हैं और न ही खुश हैं. क्या है टिकट बंटवारे की पूरी कहानी? पढ़िए इस खास रिपोर्ट में...

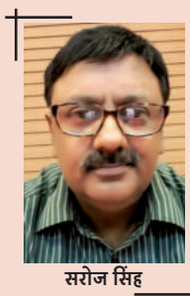

सरोज सिंह

राजनीति में कभी-कभी बनी हुई बात बिगड़ने में और कभी-कभी बिगड़ी हुई बात बनने में समय नहीं लगता है. अभी तक ऊपर-ऊपर देखने में सब कुछ ठीक ठाक लगने वाला एनडीए इन दिनों टिकट बंटवारे को लेकर तलवार की धार पर चल रहा है. भाजपा के सहयोगी दलों लोजपा, रालोसपा और हम के नेताओं की अतिमहत्वाकांक्षा ने एनडीए की एकता पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है. पटना से लेकर दिल्ली तक कोशिश है कि परदे के पीछे ही सारे विवादों को निपटा कर एकजुट एनडीए को चुनावी अखाड़े में उतारा जाए पर यह काम आसान नहीं दिख रहा है. अगर हालात जल्द नहीं बदले तो एनडीए में टूट की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है. भाजपा की अपनी तैयारी और नरेंद्र मोदी की सभाओं में उमड़ने वाली भीड़ की पृष्ठभूमि में भाजपा के रणनीतिकारों ने यह तय कर लिया है कि 160 से कम सीटों पर लड़ना पार्टी के लिए ठीक नहीं होगा. इसके पीछे भाजपा की रणनीति यह है कि चुनाव बाद भाजपा अपने सहयोगी दलों पर बहुत ज्यादा निर्भर नहीं रहना चाहती है. स्थानीय निकाय चुनावों में सहयोगी दलों की तुलना में भाजपा प्रत्याशियों की जीत का प्रतिशत ज्यादा रहा. 2010 के चुनाव में जब भाजपा जदयू के साथ थी तब भी जदयू की तुलना में भाजपा उम्मीदवारों की जीत का प्रतिशत ज्यादा रहा है. यही वजह है कि भाजपा हर हाल में ज्यादा से ज्याद सीटों पर चुनाव लड़ना चाह रही है. इसलिए मौटे तौर पर यह तय कर लिया गया है कि 160 से कम सीटों पर चुनाव लड़ने की नौबत नहीं आने दी जाएगी. अब सहयोगी दलों के लिए बांटने के लिए भाजपा के पास 83 सीटें बच जाती हैं. इसी 83 सीटों में अब बंटवारा होना है. भाजपा कुछ दिन पहले तक इस बात को लेकर निश्चिंत थी कि सीटों के बंटवारे में दिक्कत नहीं आएगी. भाजपा का मानना है कि आमतौर पर एक सांसद की सीट पर छह विधायकों का फार्मूला चलता है. इस लिहाज से लोजपा को चालीस से पैंतालीस और रालोसपा को अठारह से बीस सीटें मिलनी चाहिए. शेष सीटें वह हम को देने का सोच रही थी, लेकिन लोजपा ने 84 और रालोसपा ने 67 सीटों का दावा कर सारे गणित को ही बिगाड़ दिया. इस पर हम के कुछ नेता कहने लगे हैं कि वह लोजपा से एक सीट भी कम नहीं लेंगे. दरअसल यही स्थिति भाजपा को परेशान कर रही है. लालू प्रसाद, नीतीश कुमार और कांग्रेस ने जिस सहजता से सीटों का बंटवारा कर लिया इससे भी भाजपा पर काफी दबाव बन गया है. सहयोगी दल भाजपा पर लगातार सार्वजनिक दबाव बना रहे हैं कि सीटों का बंटवारा जल्द से जल्द हो. भाजपा के केंद्रीय और प्रदेश के नेताओं के बीच भी बेहतर तालमेल न होने से समस्या की जटिलता बढ़ी है. वैशाली के अपने सम्मेलन में रालोसपा ने यह प्रस्ताव दिया था कि 102 सीटों पर भाजपा, 74 पर लोजपा और षेश 67 सीटों पर रालोसपा चुनाव लड़े. गौरतलब है कि 2010 के चुनाव में भाजपा 102 सीटों पर ही लड़ी थी. उपेंद्र कुशवाहा ने यह बात भी रखी थी कि अगर एनडीए में अन्य कोई पार्टी आती है और इसे जितनी सीटें देना तय हो इसे पहले के तीनों दल समानुपातिक आधार पर सीटें दे दे, लेकिन यह बात आई गई हो गई. जानकार सूत्र बताते हैं कि अभी सीटों को लेकर जो वास्तविक स्थिति है यह है कि लोजपा को 35 से 40, रालोसपा को 17 से 22 और हम को 20 से 24 सीट देने पर गहन मंथन भाजपा खेमे में चल रही है. इस फार्मूले पर सबसे ज्यादा नाराजगी हम खेमे में है. हम के नेताओं का दावा है कि उनके पास 22 फीसदी वोट है इसलिए सीटों का बंटवारा इसी आधार पर होना चाहिए. सूत्र बताते हैं कि हम 35 से 40 सीटों पर अपनी रजामंदी दे सकती है. हम के लिए राहत की बात यह है कि इसके कुछ नेता भाजपा में शामिल हो गए हैं. इससे पार्टी के उपर टिकट का दबाव कम हुआ है. उपेंद्र कुशवाहा भी 30 से कम में मानेंगे ऐसा लगता नहीं है. रालोसपा के एक नेता कहते हैं कि लोकसभा का चुनाव व टिकट विधानसभा चुनाव व उसके टिकट का आधार नहीं बन सकता है. लोकसभा में हमें पांच टिकट मिलता तो हम पांच पर भी लड़ सकते थे, लेकिन इस समय नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने की चाहत में सीटों को लेकर जिद करना पार्टी ने उचित नहीं समझा. अब हालात दूसरे हैं. रालोसपा के जहां 25 हजार से ज्यादा सदस्य हैं वहीं पार्टी ने टिकट की मांग की है. सीटों का जल्द से जल्द सम्मानजनक बंटवारा ही एनडीए के हित में है. लोजपा के नेता खुलकर तो नहीं बोल रहे पर उनके दिल में भी 50 से ज्यादा सीटों पर लड़ने की इच्छा है. प्रदेश अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस कहते हैं कि लोकसभा चुनाव में लोजपा के सारे वोटों का लाभ भाजपा और रालोसपा के उम्मीदवारों को मिला था. विधानसभा चुनाव में भी हमारे कार्यकर्ता एनडीए के प्रत्याशियों के लिए जान लगा देंगे. ऐसे में अब भाजपा नेतृत्व को यह तय करना है कि लोजपा के हमारे कार्यकर्ताओं का हौंसला बुलंद रहे. श्री पारस कहते हैं कि चुनाव कार्यकर्ता लड़ते हैं ऐसे में अगर कार्यकर्ताओं को उनका वाजिब हक नहीं मिलेगा, तो अच्छे परिणाम की आशा हम कैसे कर सकते हैं. श्री पारस को पूरा भरोसा है कि एनडीए का जिम्मेदार नेतृत्व मिलजुल कर सम्मानजनक रास्ता निकाल लेगा. उम्मीद तो सभी को है कि सम्मानजक रास्ता निकल जाएगा, लेकिन अगर बात बिगड़ी तो एकाध सहयोगी अगर दूसरे रास्ते पर चलते दिखाई पड़ें, तो आश्चर्य नहीं होगा.■

भाजपा का मानना है कि आमतौर पर एक सांसद की सीट पर छह विधायकों का फॉर्मूला चलता है. इस लिहाज से लोजपा को चालीस से पैंतालीस और रालोसपा को अठारह से बीस सीटें मिलनी चाहिए. शेष सीटें वह हम को देने का सोच रही थी, लेकिन लोजपा ने 84 और रालोसपा ने 67 सीटों का दावा कर सारे गणित को ही बिगाड़ दिया. इस पर हम के कुछ नेता कहने लगे हैं कि वह लोजपा से एक सीट भी कम नहीं लेंगे.

दिल्ली और पटना के बीच फंसे पप्पू

पप्पू यादव को लेकर भाजपा नेतृत्व बड़े ही पशोपेस में है. पप्पू यादव को एनडीए में लाया जाए या उन्हें अकेले चुनाव लड़ने के लिए छोड़ दिया जाए, ऐसे सवालों से भाजपा के रणनीतिकार रूबरू हैं. अनुमान लगाया जा रहा है कि फायदे का सौदा क्या होगा. पप्पू को मिलाना या खुला छोड़ देना. गौरतलब है कि हाल के दिनों में पप्पू यादव की सक्रियता और कोसी और सीमांचल के इलाके में पप्पू यादव के बढ़ते जनाधार ने सभी दलों के नेताओं का ध्यान खींचा है. अब तो खुद लालू प्रसाद भी पप्पू यादव का नोटिस लेने लगे हैं. जानकार सूत्र बताते हैं कि भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व पप्पू यादव को मिलाने के पक्ष में है. बात केवल सीट पर अटकी हुई है. पप्पू यादव ने 25 सीटों की मांग की है जबकि भाजपा पप्पू यादव को 10 से ज्यादा सीट देना नहीं चाहती है, लेकिन भाजपा का प्रदेश नेतृत्व चाहता है कि पप्पू यादव को अकेले चुनाव लड़ने के लिए छोड़ दिया जाए तो पार्टी ज्यादा फायदे में रहेगी. बस बात यही अटकी पड़ी है और यही वजह है कि एनडीए के सहयोगी दलों के बीच भी सीटों का बंटवारा नहीं हो पा रहा है. जनअधिकार मोर्चा सेक्यूलर के प्रधान महासचिव एजाज अहमद कहते हैं कि बिहार की राजनीति में पप्पू यादव को नजरअंदाज करना अब किसी के लिए भी संभव नहीं है. हमारी पार्टी अपने कार्यक्रमों और सिद्धांतों के आधार पर चल रही है और बिहार की जनता का पूरा प्यार हमें मिल रहा है. पप्पू यादव तो हर गरीब और शोसित की आवाज हैं. भरोसेमंद सूत्रों पर भरोसा करें तो पप्पू यादव अभी भाजपा को लेकर निराश नहीं हुए हैं. अभी आठ दस दिन वे इंतजार करने के मूड में हैं अगर बात नहीं बनी, तो बिहार की अन्य छोटी-छोटी पार्टियों को साथ लेकर तीसरे मोर्चे का गठन भी कर सकते हैं. एनसीपी और एनपीपी जैसी पार्टियों से उनकी बात चल भी रही है. समाजवादी पार्टी के विक्षुब्ध गुट को भी वे अपने साथ मिलाना चाहते हैं. कहा जाए तो पप्पू यादव की तैयारी दोतरफा हैं. पप्पू यादव चाहते हैं कि आगामी सरकार के गठन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका हो इसलिए वह इस चुनाव को जीवन मरण की तरह ले रहे हैं.■

feedback@chauthiduniya.com

एक नज़र
चुनावी हलचल

सांसद ने की पीड़ितों से मुलाकात

– गीता कुमार

एसएसबी टीम हुई सक्रिय

– रूपा कुमारी

पीड़ितों से मिलीं कृष्णा यादव

–गीता कुमार

जमुई

जमुई में होगी तालमेल की असली परीक्षा

चिराग पासवान बार-बार कह रहे हैं कि लोजपा से दगा करने वालों का वह विरोध करेंगे. उनके निशाने पर नरेंद्र सिंह हैं और इसलिए आशंका यह जताई जा रही है कि कहीं जमुई के कारण गठबंधन के स्वाद में खटास न आ जाए. जमुई जिले में नरेंद्र सिंह की राजनीतिक ताकत को नजरअंदाज करना किसी के लिए भी आसान नहीं है. दूसरी तरफ चिराग पासवान भी झुकने को तैयार नहीं हैं और उन्होंने जमुई सीट को अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया है. अगर कोई ठोस बात नहीं बनी तो पूरे जिले की राजनीति इससे प्रभावित होगी. इधर महागठबंधन में भी जमुई सीट के लिए टिकट के दावेदारों की भरमार है. बांका सांसद जयप्रकाश यादव के अनुज विजय प्रकाश राजद के टिकट के सबसे प्रबल दावेदार हैं. विजय प्रकाश पहले भी यहां से भाग्य आजमा चुके हैं. इन दिनों वे पूरे मनोयोग से चुनावी तैयारी में जुटे हैं.

नंदन निराला

अजय प्रताप | अनिल सिंह | बिनोद यादव | दामोदर रावत | डॉ नीरज कुमार साह | गोपाल गुप्ता

नेपाली सिंह | रविन्द्र यादव | सुभाष पासवान | सुमित सिंह | विजय प्रकाश | विनोद चौधरी

बिहार में चुनाव हो और जमुई की धरती सुर्खियों में न हो यह संभव ही नहीं है. जिले की चार विधानसभा सीट जमुई, सिकंदरा, झाझा और चकाई के लिए टिकटों के दावेदार पटना से लेकर दिल्ली तक धमाचौकड़ी मचा रहे हैं. एनडीए और महागठबंधन दोनों ही खेमों में बेचैनी है, क्योंकि चुनाव में अब वक्त कम बचा है पर टिकट को लेकर सस्पेंस खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है. बात अगर जमुई से ही शुरू करें, तो यहां के मौजूदा विधायक अजय प्रताप हैं जो जदयू के टिकट पर यहां से जीतकर पहली बार विधानसभा पहुंचे हैं. राजनीतिक हालात बदले और अजय प्रताप अब जीतनराम मांझी के हम में हैं. जानकार सूत्र बताते हैं कि अजय प्रताप जल्द ही भाजपा का दामन थाम कर चुनावी अखाड़े में उतरने वाले हैं. अजय प्रताप के इस कदम से सबसे बड़ा झटका भाजपा से टिकट के दावेदार प्रकाश भगत और विकास सिंह को लग सकता है. ये दोनों नेता लंबे समय से भाजपा के साथ हैं और इस बार इन दोनों को लग रहा था कि इनका नंबर आ सकता है पर राजनीति का चक्र ऐसा घूम रहा है कि लगता है अजय प्रताप उनके इरादों के आगे आ गए हैं. लेकिन राह अजय प्रताप के लिए भी आसान नहीं है, क्योंकि लोजपा जमुई की सीट पर अपना स्वाभाविक दावा मान रही है. यहां के सांसद चिराग पासवान की इच्छा है कि मुख्यालय की सीट लोजपा के लिए छोड़ दिया जाए और अनिल सिंह को चुनावी जंग में उतारा जाए.

चिराग पासवान बार-बार कह रहे हैं कि लोजपा से दगा करने वालों का वह विरोध करेंगे. इनके निशाने पर नरेंद्र सिंह हैं और इसलिए आशंका यह जताई जा रही है, कि कहीं जमुई के कारण गठबंधन के स्वाद में खटास न आ जाए. जमुई जिले में नरेंद्र सिंह की राजनीतिक ताकत को नजरअंदाज करना किसी के लिए भी आसान नहीं है. दूसरी तरफ चिराग पासवान भी झुकने को तैयार नहीं हैं और उन्होंने जमुई की सीट को अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया है. अगर कोई ठोस बात नहीं बनी तो पूरे जिले की राजनीति इससे प्रभावित होगी. इधर महागठबंधन में भी जमुई सीट के लिए टिकट के दावेदारों की भरमार है. बांका सांसद जयप्रकाश यादव के अनुज विजय प्रकाश राजद के टिकट के सबसे प्रबल दावेदार हैं. विजय प्रकाश पहले भी यहां से भाग्य आजमा चुके हैं. इन दिनों वे पूरे मनोयोग से चुनावी तैयारी में जुटे हैं. वैसे जमुई से ताल्लुकात रखने वाले और झारखंड से विधायक रह चुके मलखान सिंह के छोटे भाई प्रवीण सिंह भी टिकट के लिए हाथ पैर मार रहे हैं. राजद की ओर से हमेशा की तरह त्रिपुरारी बाबू के पुत्र शांतनु और कानू समाज के वरिष्ठ नेता गोपाल गुप्ता भी आस लगाए बैठे हैं कि इस बार इनका इंतजार जरूर खत्म होगा. इनके अलावा जदयू कोटे से रविंद्र मंडल भी दौड़ में शामिल हैं. प्रमोद मंडल भी अपनी दावेदारी जमुई सीट के लिए जता रहे हैं. अब बात झाझा की करते हैं. यहां से वर्तमान में भवन निर्माण मंत्री दामोदर रावत विधायक हैं और लगातार यहां से जीत दर्ज करते रहे हैं. इस बार भी वह अपने जीत के प्रति आश्वस्त हैं. उन्हें अपने द्वारा कराये गए कामों पर पूरा भरोसा है. रावत कहते हैं कि उन्हें तो हर समाज के लोग वोट देते हैं इसलिए झाझा में जात-पात की बात कहां आती है. वैसे राजद से प्रगति मेहता भी टिकट के जुगाड़ में लगे हुए हैं. एनडीए से यहां के लिए तीन मजबूत दावेदार हैं. विनोद यादव, रविंद्र यादव और नीरज साव. तीनों नेता अपने-अपने आकाओं के माध्यम से टिकट की बाजी जीत लेने के लिए रात दिन एक किए हुए हैं. पटना के सूत्रों पर भरोसा करें तो एनडीए के टिकट की रेस में फिलहाल विनोद यादव का पलड़ा भारी दिख रहा है. वैसे जमुई के व्यवसायी उमांशकर भगत उर्फ टुनटुन भैया भी झाझा का मैदान मारने के लिए बेताब हैं. सिकंदरा में दोनों ही खेमों में टिकट को लेकर बहुत ही संशय की स्थिति है. जदयू के मौजूदा विधायक रामेश्वर पासवान का टिकट कटना लगभग तय माना जा रहा है. राजद का जिले की दो सीटों जमुई और चकाई पर मजबूत दावा है ऐसे में हो सकता है कि सिकंदरा सीट कांग्रेस के खाते में भी आ सकती है. वैस राजद से विनोद चौधरी और प्रयाग चौधरी मजबूत उम्मीदवार हैं. वैसे विनोद चौधरी कांग्रेस के भी संपर्क में हैं. अगर सीट कांग्रेस के खाते में जाती है, तो यहां विनोद चौधरी का दावा सबसे ज्यादा पुख्ता होगा. लोजपा से सुभाष पासवान और रविशंकर टिकट की दौड़ में सबसे आगे हैं. चकाई में दावेदारों की भरमार है. मौजूदा विधायक सुमित सिंह का हम से चुनाव लड़ना तय है. चिराग पासवान चाहते हैं कि यहां से विजय सिंह लोजपा के प्रत्याशी बनें. एनडीए के घटक दलों के रिश्तों में खटास यहां भी महसूस की जा सकती है. अगर बात नहीं बनी तो यहां और जमुई में दोस्ताना संघर्ष के भी आसार बन सकते हैं. महागठबंधन के टिकट के लिए यहां से नेपाली सिंह और फाल्गुनी यादव की पत्नी का दावा सबसे मजबूत है. नेपाली सिंह को जदयू और राजद दोनों दलों के नेताओं का आर्शीवाद प्राप्त है. वैसे राजद का एक खेमा फाल्गुनी यादव की पत्नी को प्रत्याशी बनाए जाने का पक्षधर है. राजद एमएलसी संजय सिंह भी अपनी पत्नी के लिए राजद का टिकट चाहते हैं. अगर ऐसा नहीं हुआ तो वह अपनी पत्नी को निर्दलीय भी चकाई के चुनावी समर में उतार सकते हैं. जदयू से अशोक सिंह के नाम की भी चर्चा है. पोलुस हेम्ब्रम पहले ही बसपा से प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं.

देखा जाए तो जमुई जिले में दोनों ही खेमों में टिकट को लेकर भारी मारामारी है और कुछ सीटों पर तो तालमेल का भविष्य ही दांव पर लगा है. देखना दिलचस्प होगा कि पटना और दिल्ली में बैठे नेता जमुई जिले का बंटवारा कैसे करते हैं, क्योंकि जमुई की धरती तो हमेशा राजनीतिक सुर्खियों में रहने की आदि है.■

feedback@chauthiduniya.com

चनपटिया विधानसभा क्षेत्र

टिकट के दावेदारों की भरमार

संजय कुमार सिंह

पश्चिम चंपारण के चनपटिया विधानसभा क्षेत्र जिला मुख्यालय से सटा होने के कारण यहां की राजनीति पर जिला मुख्यालय की राजनीति का असर नजर आता है. पूर्णतः कृषि पर निर्भर इस विधानसभा क्षेत्र की प्रमुख फसल धान, गन्ना, गेहूं व दलहन है. सरकार की माने तो यह पूरा विधानसभा क्षेत्र नहरों से सिंचित हैं जबकि हकीकत इससे इतर बतायी जाती है. इस क्षेत्र से होकर गुजरने वाली नहरें सूखी रहती हैं तथा समय से पानी नहीं आने के कारण यहां के किसानों की फसलों की पैदावार पर असर पड़ता है. उद्योग विहीन इस क्षेत्र के लोगों की रोजी-रोटी का साधन परंपरागत खेती है. हालांकि प्रखंड मुख्यालय में पहले एक चीनी मिल हुआ करती थी. जो आज जीर्ण-शीर्ण होकर बंद हो चुकी है. स्थानीय किसान बताते हैं कि चीनी मिल के बंद होते ही उनकी खुशहाली को भी ग्रहण लग गया. अब तो उन्हें अपना गन्ना अनुमंडल मुख्यालय नरकटियागंज स्थित चीनी मिल को देना पड़ता है. जिसके कारण लागत बढ़ने से आमदनी कम हो गयी है.

देवी किरन | डॉ.एन.एन. शाही | राज किशोर प्रसाद | रविन्द्र तिवारी | नरेंद्र शर्मा | अशोक ओझा

बाकी सारी कसर मंहगाई ने पूरी कर दी है. किसानों का यह भी कहना है कि परंपरागत खेती के अलाभकारी होने से समस्या और विकट हो चली है. स्थानीय लोगों की माने तो भारी मुनाफा तथा खेती से होने वाली नगण्य आमदनी ने क्षेत्र के युवाओं को तस्करी जैसी देश द्रोही कार्यों की तरफ भी आकर्षित किया है. मुद्दो की बात करें, तो इस विधानसभा क्षेत्र का सबसे बड़ा मुद्दा है यहां के किसानों की रीढ़ मानी जाने वाली चीनी मिल को चालू कराना. हर चुनाव में इसे चालू कराने की बात तो हर नेता करता है, लेकिन चुनाव जीतते ही नेता इसकी तरफ से आखें फेर लेते हैं. जिससे हर चुनाव में यह मुद्दा बना ही रह जाता है. किसानों की माने तो चीनी मिल को चालू कराने का लक्ष्य तथा चीनी मिल पर किसानों के बकाया का भुगतान करा कर ही किसानों की बिगड़ी आर्थिक स्थिति को संभाला जा सकता है. साथ ही इस क्षेत्र से गुजरने वाली नहरों की वितरणी व उप वितरणी शाखाओं की उचित देखभाल भी जरूरी है. ताकि फसल पैदावार के लिये समय पर सिंचाई की सुविधा मिल सके.

इस विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2010 के विधानसभा के आकड़ों के अनुसार कुल बूथ की संख्या 218 है. साथ ही इस विधानसभा क्षेत्र में कुल मतदाताओं की संख्या 234029 बतायी जाती है. जिसमें पुरूष मतदाताओं की संख्या 128933 तथा महिला मतदाओं की संख्या 105068 है. वर्ष 2010 में यह सीट भाजपा-जदयू गठबंधन के तहत भाजपा को मिली थी. जिसके बाद इस सीट पर भाजपा के स्वच्छ व बेदाग छवि तथा राज्य भाजपा के कद्दावर समझे जाने वाले नेता चंद्रमोहन राय को टिकट दिया तथा उन्होंने इस सीट से जीत हासिल की. उनके निकटम प्रतिद्वंदी के रूप में बसपा के एजाज हुसैन थे. इस चुनाव में श्री राय को 44835 मत प्राप्त हुए. जबकि एजाज हुसैन को 21426 मत मिले. अगर बात करें तो पूरे जिले में इस विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा मारामारी है. सबसे अधिक दावेदार संभवतः हर पार्टी में इसी विधानसभा क्षेत्र में होंगे. जानकारों की माने तो अधिक उम्र के कारण संभवतः चंद्र मोहन राय अपनी मर्जी से चुनाव नहीं लड़ने का एलान कर सकते हैं. हालांकि पार्टी को इस बार के बदले समीकरण में उनकी सबसे ज्यादा जरूरत नजर आ रही होगी, क्योंकि उनके कद व बेदाग छवि का लाभ संभवतः इस विधानसभा चुनाव क्षेत्र में पार्टी को सबसे अधिक सेफ जोन में ला सकती है. जानकारों की माने तो श्री राय के चुनाव नहीं लड़ने के एवज में सबसे अधिक संभावित उम्मीदवारों की कतार भाजपा में ही नजर आ रही है. इस सीट पर भाजपा के कई नए चेहरे अपनी उम्मीदवारी तलाश रहें हैं. इस कतार में सबसे बड़ा नाम प्रदेश कोषाध्यक्ष दीपेंद्र सर्राफ का है. जो अब तक पार्टी के लिये किए गए कार्य तथा लोगों के बीच जमीनी पकड़ को अपनी स्वभाविक उम्मीदवारी मान कर चल रहे हैं. वर्तमान विधायक श्री राय के संबंधी जय राय भी अपने को स्वभाविक उम्मीदवार मान कर चल रहे हैं. उन्हें उम्मीद है कि अगर पार्टी उन्हें टिकट देती है, तो वर्तमान विधायक चंद्रमोहन राज की विरासत को वह आगे बढ़ा सकते हैं. साथ में उन्हें उनकी बेदाग छवि का भी फायदा मिलेगा. कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन गिरेन्द्र नाथ तिवारी को भी कोऑपरेटिव की राजनीति का लंबा तजुर्बा है. साथ ही पार्टी से लंबे समय से जुड़े होने के कारण उन्हें भी भरोसा है कि संभवतः इस बार विधानसभा का टिकट पार्टी उन्हें ही देगी. चनपटिया नगर पंचायत की पूर्व अध्यक्ष किरण देवी भी स्थानीय राजनीति को आधार मान कर अपना टिकट तय मान रही हैं. साथ ही विशेश्वर राय, राज किशोर प्रसाद, विभव चौबे आदि नाम की चर्चा भी काफी जोर-शोर से फिजा में तैर रही है. बहरहाल यह सारा मामला श्री राय के चुनाव नहीं लड़ने के एलान पर ही टिका नजर आ रहा है. जबकि दूसरी तरफ जदयू से जिलाध्यक्ष डॉ.एन.एन. शाही व पूर्व प्रखंड प्रमुख वसंत सिंह के नाम की चर्चा जोरों पर है. जदयू अध्यक्ष की माने, तो विगत दस सालों में नीतीश अपने काम की बदौलत एक ब्रांड बन कर उभरे हैं.

जिसका सीधा लाभ उनकी पार्टी सहित गठबंधन को आगामी विधानसभा चुनाव में मिलेगा. अगर पार्टी उन्हें टिकट देगी तो निश्चित रूप से चुनाव लड़ेंगे साथ में पार्टी को यहां से आगे रखने का प्रयास करेंगे. राजद से विनोद आर्य भी चनपटिया विधानसभा क्षेत्र पर राजद के स्वभाविक दावेदारी की बात कहते हैं. कांग्रेस से नरेंद्र नाथ तिवारी के भी नाम की चर्चा बतायी जाती है. अगर यह सीट कांग्रेस के खाते में आयी तो उन्हें टिकट मिल सकता है.■

feedback@chauthiduniya.com

इंटरव्यू

भाजपा को रोकना ही पार्टी की प्राथमिकता है- अशोक चौधरी

पिछले कई सालों तक बिहार में राज्य करने के बावजूद भी कांग्रेस पार्टी आज अपने जनाधार को मजबूत नहीं कर पाई है. आजादी के बाद बिहार में सबसे अधिक मुख्यमंत्री कांग्रेस से ही थे. पिछले दो दशक से बिहार में कांग्रेस का जनाधार खिसकता जा रहा है, लेकिन इस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस अपने खोए हुए जनाधार को वापस लाने के जुगाड़ में है. राहुल गांधी के उपाध्यक्ष बनने के बाद पार्टी युवाओं को अधिक तरजीह दे रही है. पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों का मानना है कि युवाओं का जोश और जुनून एवं बुजुर्गों का तजुर्बा दोनों मिलकर इस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के जनाधार को मजबूत बनाऐंगे. धीरे-धीरे अपने खिसकते जनाधार एवं कमजोर पड़ चुके संगठन को मजबूत करने का कार्य इस विधानसभा चुनाव में पार्टी करेगी.पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में किस रणनीति के तहत उतरेगी, इस बारे में प्रदेश अध्यक्ष अशोक चौधरी ने चौथी दुनिया की संवाददाता दिव्या त्रिपाठी से बेबाक बातचीत की. प्रस्तुत है खास अंश.

इस बार के विधानसभा चुनाव को आप किस रुप में देखते है?

देश के लिए बिहार का चुनाव महत्वपूर्ण है और भारतीय जनता पार्टी के फैलाव को रोकने के लिए हम सभी एक साथ हैं. पूरे देश की निगाह इस चुनाव पर है. हम इस विधानसभा चुनाव को बहुत ही गंभीरता से ले रहे हैं. पार्टी आलाकमान की निगाह भी इस चुनाव पर है, और वह इस चुनाव को गंभीरता से ले रहे हैं. कांग्रेस विचारधारा की लड़ाई लड़ती रही है. बिहार में भाजपा के फैलाव को रोकना ही पार्टी की प्राथमिकता है.

पहले की कांग्रेस और अब की कांग्रेस में क्या अंतर है?

पहले की कांग्रेस और अब की कांग्रेस में अन्तर सिर्फ इतना है कि राहुल गांधी के उपाध्यक्ष बनने के बाद जब से उनका प्रभाव फैला है उसमें सभी जाति धर्मों के लोगों को पार्टी से जोड़ा गया है. युवाओं की शक्ति को पार्टी में और संगठन में फैला सके हैं. ज्यादातर जिला कांगेस कमेटी एवं प्रदेश के पदाधिकारियों कि औसत आयु 40 से 42 वर्षों की है, जो कि राहुल गांधी के आने के बाद एक बड़ी उपलब्धि है.

युवाओं को बिहार विधान सभा चुनाव में अपने पार्टी से कैसे जोड़ेंगे?

बिहार विधानसभा में युवाओं को जोड़ने के लिए जो पार्टी का चुनावी मेनिफेस्टो आएगा उसमें युवाओं को आकर्षित करने की कोशिश रहेगी कितने युवाओं को टिकट दिया जाऐगा कितने युवाओं को संगठन से जोड़ेंगे. संगठन में युवाओं को जोड़कर हमने युवाओं को संदेश दिया है कि जो हमारी पार्टी और हमारी विचारधारा से जुड़ रहे हैं और उनका भविष्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी में है. टिकट बंटवारे में युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी. यह एक बड़ा आकर्षण का कारण है. युवाओं के लिए सबसे बड़ा आकर्षण हमारी पार्टी में राहुल गांधी हैं, जो आज युवाओं के लिए आइकॉन हैं और युवाओं की सोच है. वह जिस तरह की वे राजनीति करते हैं और युवाओं को प्रोत्साहित करते हैं. उससे युवा हमारी पार्टी कि ओर आकर्षित हो रहे हैं.

जातीय आंकड़ा क्या इस बार के चुनाव में कोई प्रभाव छोड़ेगा?

दो तरह की राजनीति होती है, एक है जातीय राजनीति और एक है युवाओं की राजनीति, हमारा यह मानना है कि हमारा जो युवा पीढ़ी है, वो धर्म एवं जाति से हट कर इस बात की चिंता करती है कि प्रदेश में जो सरकार आए, वो युवाओं के लिए क्या कर रही है? किस तरह का माहौल दे रही है ? प्रदेश में पढ़ाई की स्थिति क्या है? नौकरी की स्थिति क्या है? उन्हें जाति धर्म से कोई मतलब नहीं हैं. हम उस तरह कि राजनीति में विश्वास करते हैं, जो जाति धर्म से ऊपर उठकर युवाओं के सपने को साकार करने में अपनी भूमिका निभा सके. जातीय गणित का आंकड़ा वो बैठाते हैं, जो जाति की राजनीति करते हैं. हम सभी जाति और धर्मों के लोगों को साथ लेकर चलना चाहते हैं. कांग्रेस पार्टी की युवा सोच है. कांग्रेस पार्टी युवाओं के सपने सकार करना चाहती है, हमारा वोट भी वही है. आने वाले समय में हम जाति और धर्म से ऊपर इस समाज को ले जाना चाहते हैं. जब जाति और धर्म से ऊपर यह समाज होगा तब कांग्रेस की विचारधारा को असली जामा पहना पाएंगे, जो हमारे पूवर्जों ने सपना देखा था कि हिन्दु और मुस्लिम में कोई भेद नहीं है, लेकिन जब तक इस तरह की पार्टी रहेगी, जो जाति और धर्म के नाम पर देश को बांटने की कोशिश करेगी तब तक जाति और धर्म बरकरार रहेगा. हमारी तो राजनीतिक सोच और विचारधारा ही अलग है.

क्या नरेन्द्र मोदी का असर इस विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा?

भाजपा का वोट प्रतिशत, जो 2014 लोकसभा चुनाव मे था और जो लोकप्रियता नरेन्द्र मोदी की था उसमें निश्चित ही कमी आई है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में लोगों को जो उम्मीद थी और उन्होंने जो वादा लोगों से किया था. उस पर वह खरे नहीं उतरे हैं. पिछले लोकसभा चुनाव में सेक्युलर वोटों का जो बंटवारा हुआ था वो इस विधानसभा चुनाव में नहीं होगा, क्योंकि सभी सेक्युलर पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ेंगी. 2014 में जो भाजपा की लोकप्रियता थी वह कम हुई है. भाजपा का भविष्य इस राज्य में कहीं नहीं दिख रहा है.

भाजपा से मुख्यमंत्री का कोई नाम सामने नहीं आ रहा है. भाजपा नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ना चाह रही है और उनका ही नाम लेकर जनता के बीच जा रही है. इस पर आपका क्या कहना है?

यह तो राजनीति का एक भाग है, क्योंकि अब तक भाजपा ने जितने भी चुनाव लड़े हैं, वह उस इलाके में जाते हैं और वहां जिस जाति का अधिक वोट है. वहां के उस जाति के नेता को मुख्यमंत्री के रुप में जनता के समक्ष रख देंगे. जहां राजपूत का वोट अधिक है वहां आरएसएस के लोग राधाकृष्ण किशोर का नाम रख देंगे और जिस इलाके में भूमिहार का वोट होगा वहां सीपी ठाकुर को मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट कर देंगे. यह उनकी राजनीति की मांग है. भाजपा अभी तक उतना सशस्त नहीं हो पाई है कि मुख्यमंत्री का नाम भी जनता के समक्ष रख सकें.

कैसे प्रत्याशी को विधानसभा में टिकट दिया जाऐगा?

वैसे प्रत्याशी जो जितने वाले हों और कांग्रेस के संगठन से लंबे समय से जुड़ा हुआ हो तथा संगठन के हित में बेहतर कार्य किया हो. टिकट बंटवारे में युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी. वैसे युवा और कार्यकर्ता जो कांग्रेस की विचारधरा का सम्मान करते हों तथा जिनकी पैठ विधानसभा में अच्छी हो उनको टिकट दिया जाऐगा.

टिकट बंटवारे को लेकर कार्यकर्ताओं में असंतोष के संदर्भ में क्या करना उचित होगा?

असंतोष आना तो लाजमी है हर किसी को टिकट तो नहीं मिल सकता है. प्रत्येक विधानसभा से एक नहीं कई दावेदार रहते हैं, लेकिन टिकट किसी एक को ही मिल सकता है. वैसे में जो कांग्रेस के सच्चे कार्यकर्ता होंगे वे आलाकमान के निर्देश को मानते हुए पार्टी के हित में कार्य करेंगे. हम गठबंधन के तहत चुनाव लड़ रहे हैं. सीट भी हमें कम मिली है. यह तो राजनीति का हिस्सा है की कुछ लोग खुश होते हैं, तो कुछ लोग नाराज होत हैं.■

feedback@chauthiduniya.com

घोशी में होगा रोचक मुकाबला

कोर्ट द्वारा चुनाव लड़ने पर लगी रोक के बाद पूर्व सांसद डॉ. जगदीश शर्मा, हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा पार्टी में पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के साथ (हम) में अपनी जगह बनाई है, और अपने पुत्र राहुल कुमार को एनडीए के साथ घोशी विधानसभा से फिर चुनाव लड़ाने को तैयार हैं.

राहुल कुमार | राजीव नयन | राजेश रंजन

धर्मेन्द्र/रविकांत

बिहार विधानसभा के उदाहरण का पर्याय बन चुका घोशी विधानसभा सीट पर वर्ष 1977 से एक ही परिवार का कब्जा रहा है. पूर्व सांसद डॉ. जगदीश शर्मा, उनकी पत्नी शांति देवी के बाद पुत्र राहुल कुमार विधायक की विरासत को संभाल रहे हैं. बिहार विधानसभा के चुनावी आहट के साथ ही क्षेत्र में राजनीति की खेती शुरू हो गई है. वहीं कोर्ट द्वारा चुनाव लड़ने पर लगी रोक के बाद पूर्व सांसद डॉ. जगदीश शर्मा, हिन्दुस्तान अवाम मोर्चा पार्टी में पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के साथ (हम) में अपनी जगह बनाई है और अपने पुत्र राहुल कुमार को एनडीए के साथ घोशी विधानसभा से फिर चुनाव लड़ाने को तैयार हैं. वहीं एनडीए के बड़े नेताओं के द्वारा घोशी में जगह-जगह सभाएं भी चलायी जा रही हैं. वहीं अगर घोशी विधानसभा की बात करें तो घोशी में जदयू की सीट मानकर महागठबंधन से जदयू एवं राजद नेता अपना दावा जता रहे हैं. जदयू नेता राजेश रंजन इन दिनों घोशी विधानसभा के प्रत्येक क्षेत्रों में घुमने के बाद पार्टी के तरफ से सिम्बल की आश लगाए बैठे हैं. अगर बात करें, तो जदयू नेता एवं पूर्व जिला पार्षद राजीव नयन उर्फ राजू, घोशी विधानसभा में पार्टी कार्यकर्त्ता के माध्यम से सक्रिय दिख रहे हैं. गौरतलब है कि घोशी विधानसभा जाति आधारित सीट के अनुसार यादव एवं भूमिहार बहुमूल्य क्षेत्र है. राजद नेता घोशी विधानसभा से उपचुनाव लड़ चुके प्रो. दिनेश प्रसाद सिन्हा, सशक्त राजद उम्मीदवार के रूप में महागठबंधन के बल पर घोशी विधानसभा से एकबार फिर अपना भाग्य आजमाना चाहते हैं. घोशी विधानसभा क्षेत्र के कार्य में लगे हुए हैं.

घोशी विधानसभा क्षेत्र से जनता पार्टी के टिकट पर विधायक बनने के बाद डा. जगदीश शर्मा, कांग्रेस एवं निर्दलीय से भी चुनाव जीतते रहे हैं. वहीं जदयू के टिकट पर वर्ष 2009 में डॉ.जगदीश शर्मा सांसद बनें.

वहीं 2010 के घोशी विधानसभा से डॉ. जगदीश शर्मा के पुत्र राहुल कुमार जदयू के टिकट पर चुनाव लड़े और जीत हासिल की. हालांकि बाद में जदयू ने दल विरोधी गतिविधि के कारण राहुल को पार्टी से निष्कासित कर दिया. फिलहाल पूर्व सांसद डा. जगदीश शर्मा, पूर्व मुख्यमंत्री के साथ हम पार्टी में वरिष्ठ नेता के रूप में कार्य कर रहे हैं. बात करें तो घोशी से विधायक राहुल कुमार विधानसभा चुनाव में एनडीए के टिकट से मैदान में चुनाव लड़ने को तैयार हैं. घोशी के जो हालात हैं, इसे देखने से लगता है कि इस बार यहां कांटे की टक्कर होगी. सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और उम्मीदवारों का नाम तय होते ही घमासान तेज हो जाएगा.■

feedback@chauthiduniya.com

एक नज़र
चुनावी हलचल

महुआ विधानसभा में घमासान जारी

– नसीम रब्बानी

अक्षयवट में भव्य आयोजन

– नसीम रब्बानी

राष्ट्रध्वज को दी सलामी

– आदित्यानंद

महिषी विधानसभा सीट

कोसी की धारा में पार लगना आसान नहीं

यह सब मारा-मारी खासकर, सिर्फ राजग के प्रमुख दल भाजपा में ही हो रही है. यहां तक कि भाजपा जिला अध्यक्ष राजीव रंजन ने महिषी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने के लिए अध्यक्ष पद से इस्तीफा भी दे दिया है. खुद को फेसबुक पर प्रत्याशी बता रहे हैं.

लाजवंती झा

वैद्यनाथ खिरहर

चंदन बागची

सुरेन्द्र यादव

हिरेन्द्र कुमार मिश्र

धनिकलाल मुखिया

राजीन रंजन

देवनारायण यादव नुनु

शिवन्द्र सिंह जिसु

विपिन यादव

प्रत्याशी चयन को लेकर महिषी विधानसभा सीट पर हागठबंधन तो लगभग नश्चिंत है, लेकिन राजग गठबंधन में जंग की स्थिति अभी से ही पैदा हो गई है. राजग में एक अनार सौ बीमार वाली कहावत चरित्रार्थ हो रही है. यह सब मारा-मारी खासकर, सिर्फ राजग के प्रमुख दल भाजपा में ही हो रही है. यहां तक कि भाजपा जिला अध्यक्ष राजीव रंजन ने महिषी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने के लिए अध्यक्ष पद से इस्तीफा भी दे दिया है. खुद को फेसबुक पर प्रत्याशी बता रहे हैं और इसे लेकर वह काफी आश्वस्त भी हैं. जनसंपर्क व जाति की दुहाई लोगों को दे रहे हैं. ऐसा न हो कि कहीं अध्यक्ष पद की कुर्सी और टिकट एक खास जाति के तिकड़म का शिकार हो जाए. वर्तमान में इस सीट पर राजद का कब्जा है और अब्दुल गफुर विधायक हैं. गफूर फरवरी 2005 व अक्टूबर 2005 का चुनाव हार गए थे. वर्ष 2005 के फरवरी में हुए विधानसभा चुनाव में इस सीट से पहली बार निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में सुरेन्द्र यादव ने जीत हासिल की और उन्होंने अपनी व्यक्तिगत छवि के बदौलत लालू यादव के माय समीकरण को तोड़ा. सुरेंद्र यादव विधायक तो रहे, लेकिन विधानसभा नहीं जा सके, क्योंकि उस समय रामविलास के समर्थन वापस ले लेने से सरकार गिर गई थी और विधानसभा भंग हो गई. तब रामविलास पासवान कहते थे कि विधानसभा की चाबी उनके हाथ में हैं. सहरसा की तत्कालीन लोजपा सांसद रंजीता रंजन से प्रभावित होकर लालू प्रसाद के राजद के साथ चले गए, लेकिन लालू प्रसाद के साथ वह बहुत दिनों तक टिक नहीं सके. महिषी विधानसभा सीट की पूर्व सांसद दिनेश चन्द्र यादव के अतिप्रभाव वाले क्षेत्रों में गिनती होते रही है. इस वजह से खासकर वे जिस दल में रहे प्रत्याशी के चयन में उनके ही चलती रही है. पूर्व विधायक गुंजेश्वर साह को टिकट न देकर राजकुमार साह को जदयू से टिकट दिलवाने का काम पूर्व सांसद श्री यादव ने ही किया. यह सत्य भी है कि फर्श से अर्श तक पहुंचाने का काम पूर्व सांसद दिनेश चन्द्र यादव के स्वभाव में बसा हुआ है. इसलिए भी दिनेश चन्द्र यादव से सहरसा, मधेपुरा और सुपौल जिले के दिग्गज से दिग्गज महारथी बाहर से तो दिखाते नहीं, लेकिन अंदर से खूब भय खाते हैं. इस बार वह खाली बैठे हुए हैं सभी को उनका ही डर सता रहा है. कोसी में नरेन्द्र मोदी से नहीं बल्कि दिनेश चन्द्र यादव से ही लोग सशंकित हैं कि वो किसको टिकट दिला दें और किसका पत्ता साफ करवा दें. सहरसा के पूर्व भाजपा विधायक संजीव कुमार झा इनके ही डसे हुए हैं. सुरेन्द्र यादव महिषी सीट से भाजपा के सबसे सशक्त दावेदार हैं. महिषी विधानसभा क्षेत्र सत्तरकटैया, नवहट्टा व महिषी प्रखंड क्षेत्र के अधीन पड़ता है. हालांकि भाजपा से बैद्यनाथ खिरहर, शिवेन्द्र सिंह जीसू, जिला पार्षद हीरेन्द्र कुमार मिश्र, संजीव कुंवर और एनजीओ की संचालिका लाजवंती झा भी दावेदारी कर रही हैं. कयास यह भी लगाया जा रहा है कि भाजपा का टिकट नहीं मिलने से कुछ नेता पाला भी बदल सकते हैं. कुछ का तो प्रयास अभी से ही शुरू हो गया है. यह भी कहा जा रहा है कि कोसी में रालोसपा के लिए महिषी विधानसभा सीट सबसे महफुज सीट है.

कार्यकर्ता कहते हैं कि रालोसपा सुप्रीमों व केंद्रीय राज्यमंत्री उपेन्द्र कुशवाहा की भी इच्छा है कि गठबंधन में रालोसपा को यह सीट मिले. इस सीट से रालोसपा के जिला अध्यक्ष चंदन कुमार बागची प्रतिदिन की तरह जनसंपर्क में जुटे हैं. बागची को अपने तैलिक वैश्य सहित पचपनिया जाति के वोट का भी भरोसा है. वैश्य समाज के बीच भी इनकी अच्छी पकड़ है. इस आधार वोट पर ही भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष राजीव रंजन व गुंजेश्वर शाह को गुमान है. रालोसपा सुप्रीमो उपेन्द्र कुशवाहा भी कार्यकर्ताओं के बीच वचनवद्ध हैं. अब इन क्षेत्रों में सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी भी काफी सक्रिय हो गई है. इस सीट से देवनारायण यादव उर्फ नूनू यादव भी ताल ठोक रहे हैं. पहले देव नारायण यादव राजद के साथ थे, लेकिन पप्पू यादव जिधर रहते हैं वे उधर चले जाते हैं. इसलिए इस सीट से जन अधिकार पार्टी से देवनारायण यादव का लड़ना तय माना जाता है. यह भगैत संस्कृति व यादव समाज के विकास के लिए अपनी भागीदारी निभाने से नहीं चुकते हैं. महागठबंधन के लिए जदयू जिला अध्यक्ष धनिकलाल मुखिया भी अपनी पारी का इंतजार कर रहे हैं. जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह सांसद शरद यादव व दिनेश चन्द्र यादव के वह काफी करीबी माने जाते हैं. अगर राजद के सीट की अदला-बदली हुई, तो धनिकलाल को मौका मिल सकता है. शरद यादव व नीतीश के साथ-साथ दिनेश चन्द्र यादव की सच्ची सेवा का लाभ उनको मिलने की संभावना है. खैर, कहा गया है-रात अभी बाकी है, बात अभी बाकी है. राजग गठबंधन व महागठबंधन पहले तय करे तभी पता चल सकेगा कि कौन मैदान में उतरेगा. अभी सबके सब कोसी नदी की तेज धारा में पतवार चला रहे हैं. किनारा लगने पर ही अटकलों पर विराम लगेगी.■

feedback@chauthiduniya.com

पक्के खिलाड़ी हैं सुरेन्द्र यादव

पिछले पांच विधानसभा चुनाव पर नजर डालें, तो 1990 एवं 1995 जनता दल से और 2000 में राजद से अब्दुल गॅफूर ही विधायक रहे, जबकि 2000 में ही प्रथम बार सुरेन्द्र यादव जदयू से चुनाव लड़े, तो उन्हें 31 हजार 607 वोट व राजद से अब्दुल गफूर को 49 हजार 431 वोट मिला और अब्दुल गफूर बाजी मार गए.

विधानसभा 2005 के फरवरी में हुए चुनाव में सुरेन्द्र यादव को 40 हजार 417 वोट, राजद के अब्दुल गफूर को 25 हजार 489 वोट व जदयू से गुंजेश्वर शाह को मात्र 27 हजार 539 वोट ही मिल सका. इस बार सुरेन्द्र यादव विधायक तो बन गए, लेकिन राष्ट्रपति शासन लग गया और विधानसभा भी हो गई. इसके बाद जब अक्टूबर 2005 में चुनाव हुआ, तो सुरेन्द्र यादव राजद के टिकट पर चुनाव लड़े. जिसमें इनको 31 हजार 400 वोट व जदयू से गुंजेश्वर शाह ने 38 हजार 243 वोट पाकर विधायक बन गए. उसके बाद फिर 2010 के चुनाव में अब्दुल गफूर को राजद से टिकट मिला, तो उनकी जीत हो गई. इस चुनाव में राजद को 39 हजार 158 वोट मिला. जबकि जदयू के राजकुमार शाह को 37 हजार 441 वोट और निर्दलीय प्रत्याशी की हैसियत से अपने बलबूते चुनाव लड़े, तो भी सुरेन्द्र यादव को 20 हजार 304 वोट प्राप्त हुआ. जबकि निर्दलीय चुनाव लड़े पूर्व विधायक गुंजेश्वर शाह को मात्र 3557 व कांग्रेस के वीरेन्द्र झा अनीश को 4548 वोट पाकर ही संतोष करना पड़ा और राजद के गफूर मात्र 1717 वोट के अंतर से ही विजयी हो सके.

बैकुंठपुर विधान सभा

टिकट के लिए शह-मात का खेल जारी

मंजीत कुमार सिंह

साधु यादव

शैलेश सिंह

शशिकांत सिंह

अखिलेश मिश्र

feedback@chauthiduniya.com

गोपालगंज की 6 विधानसभा सीटों के लिए विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं. राजनीतिक दलों के योद्धा चुनावी समर में उतरने के लिए व्याकूल दिख रहे हैं. इस बार के चुनाव का परिवेश बदला सा नजर आ रहा है. कल तक जो विपक्ष में थे आज वह पक्ष में हैं, जो पक्ष में थे वह आज विपक्ष में है. ऐसे में मतदाता भी उहापोह कि स्थिति में हैं. 2010 के विधानसभा चुनाव में भाजपा और जदयू साथ मिलकर चुनाव लड़े थे और राजद विपक्ष में था. इस बार महागठबंधन में जदयू, राजद और कांग्रेस एक साथ मिलकर चुनाव में उतरेगें. गोपालगंज के 6 विधानसभा सीटों में तीन भाजपा और तीन जदयू के विधायक हैं. अगर 99 बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र की बात करें, तो बैकुंठपुर विधानसभा में पुरुष मतदाता 1,47,487 और महिला मतदाता 1,33,352 हैं. 1980 से विधानसभा चुनाव का परिणाम देखा जाए, तो राजपूत और यादव के बीच लड़ाई रही और इन्हीं दोनों के बीच जीत-हार होती रही. लेकिन इसबार के चुनाव में बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र का परिदृश्य बदला हुआ है. बैकुंठपुर विधानसभा सीट पर जदयू के मुखर विधायक मंजीत कुमार सिंह का कब्जा है, इससे पहले उनके पिताजी ब्रजकिशोर नारायण सिंह का कब्जा रहा है. उनकी लड़ाई हमेशा राजद के साथ रही और इन्हीं दोनों के बीच हार जीत भी रही. इस बार नीतीश कुमार और लालू प्रसाद एक साथ हैं. अब यह सवाल उठता है, कि क्या बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र के यादव मतदाता लालू प्रसाद के साथ होंगे. इसको लेकर राजद मंथन कर रहा है, वहीं भाजपा भी बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र से कौन बने प्रत्याशी, इसको लेकर खासी चिंतित है. वैसे बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र पर एक दर्जन भाजपा नेताओं की नजर लगी है. वे अपनी जमीन बनाने में भी जुटे हुए हैं. वहीं भाजपा के सहयोगी पार्टी के नेताओं की नजर भी इस सीट पर टिकी है. देवदत्त राय के निधन के बाद राजद छोड़ हाल ही में उनके बेटे भाजपा में शामिल हुए हैं. राजनीतिक पंडितों का कहना है कि देवदत्त राय के निधन के बाद से यादवों का नेता यहां कोई नहीं रहा. लालू प्रसाद के साले और जनता दल गरीब सेक्युलर पार्टी से साधु यादव के बैकुंठपुर से चुनाव लड़ने कि घोषणा से उथल पुथल मचा हुआ है. फिर यहां यादव और राजपूत के बीच लड़ाई होने कि संभावना दिख रही है. वहीं नीतीश के नेतृत्व में बने महागठबंधन के लिए बैकुंठपुर सीट को अपने अनुकूल करने के लिए लालू प्रसाद को कड़ी मेहनत करनी होगी. भाजपा नेताओं की माने तो इस सीट पर शीर्ष नेताओं की नजर है. वैसे तो हाल ही में कांग्रेस को छोड़ आए शैलेश कुमार सिंह ने भी लोजपा का दामन थाम लिया है और बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव मैदान में जाने के लिए तैयारी में जुटे हैं. पटना के राजनीति में अपनी मजबूत पकड़ रखने वाले शशिकांत सिंह कि भी इस सीट पर नजर टिकी हुई है. देखना होगा कि इस चुनावी खेल में कौन बाजी मारता है. चुनावी आंकडों को देखा जाए, तो 1980 में जनता पार्टी, 1985 और 1990 में कांग्रेस पार्टी से ब्रजकिशोर नारायण सिंह ने चुनाव लड़ा और जनता दल के देवदत्त राय को 35742 मतों से हराया. 1995 में जनता पार्टी के टिकट पर लालबाबू प्रसाद यादव ने चुनाव लड़ा और कांग्रेस के ब्रजकिशोर नारायण सिंह को 29041 मतों से हराया. लोकसभा के चुनाव में लालबाबू प्रसाद यादव के सांसद बनने के बाद 1996 में खाली पड़े बैकुठंपुर सीट से जनता दल से चुनाव लड़े देवदत्त राय ने 47832 मतों से कांग्रेस के ब्रजकिशोर नारायण सिंह को हराया. 2000 के चुनाव में नीतीश कुमार और लालू प्रसाद अलग हो गए थे और समता पार्टी के टिकट पर मंजीत कुमार सिंह ने चुनाव लड़ा और राजद के लालबाबू प्रसाद यादव को 40963 मतों से हराया. फरवरी 2005 और अक्टूबर 2005 के चुनाव में राजद के देवदत्त राय ने अपनी सीट को सुरक्षित रखा. 2010 के चुनाव में जदयू के टिकट पर चुनाव लड़े मंजीत कुमार सिंह ने 33581 मतों से देवदत्त राय को हराया.■

बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र पर एक दर्जन भाजपा नेताओं की नजर लगी है. वे अपनी जमीन बनाने में भी जुटे हुए हैं. वहीं भाजपा के सहयोगी पार्टी के नेताओं की नजर भी इस सीट पर टिकी है. देवदत्त राय के निधन के बाद राजद छोड़ हाल ही में उनके बेटे भाजपा में शामिल हुए हैं. राजनीतिक पंडितों का कहना है कि देवदत्त राय के निधन के बाद से यादवों का नेता यहां कोई नहीं रहा. लालू प्रसाद के साले और जनता दल गरीब सेक्युलर पार्टी से साधु यादव के बैकुंठपुर से चुनाव लड़ने की घोषणा से उथल पुथल मचा हुआ है.

चौथी दुनिया

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

31 अगस्त–06 सितंबर 2015

Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2015-17, RNI No. DELHIN/2009/30467

उत्तर प्रदेश–उत्तराखंड

मेरठ और हमीरपुर की घटना से खुल गई क़ानून व्यवस्था की पोल

सत्ता के नशे में समाजवादी सरकार

उत्तर प्रदेश में क़ानून व्यवस्था की जगह अपराध का बोलबाला है. आए दिन दुष्कर्म, लूट और हत्या की ख़बरें अलग-अलग स्थानों से आती रहती हैं. प्रदेश में अपराध की यह स्थिति है कि सड़क पर चल रहे व्यक्ति की कब हत्या हो जाए, यह किसी को नहीं पता. अखिलेश सरकार सत्ता के नशे में इतनी चूर है कि उसे कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है.

प्रभात रंजन दीन

उत्तर प्रदेश की बदहाल कानून व्यवस्था के ख़िलाफ पिछले दिनों कांग्रेस ने लखनऊ में विधानसभा के सामने जोरदार प्रदर्शन किया और लाठियां खाईं. कांग्रेस नेता यूपी में बढ़ते अपराध और अराजकता के ख़िलाफ सड़क पर प्रदर्शन करते रहे और पूरा विपक्ष प्रदेश की खराब कानून व्यवस्था के खिलाफ विधानसभा के दोनों सदनों के अंदर प्रदर्शन करता रहा. यूपी में रोजाना ऐसी कई घटनाएं हो रही हैं, जो कानून व्यवस्था के फेल होने की सनद देती हैं, लेकिन हाल की दो घटनाओं ने तो प्रदेश को लोगों को हिला कर रख दिया है. समाजवादी सरकार के कार्यकाल में गुंडों और शोहदों का मनोबल इस कदर बढ़ गया है कि छेड़खानी का विरोध करने पर दिनदहाड़े किसी की भी हत्या कर दी जाती है और युवतियां आत्महत्या करने के लिए विवश कर दी जाती हैं. छेड़खानी की घटनाएं सरेआम हो रही हैं, कोई रोकने वाला नहीं है. प्रदेश के डीजीपी खुद कहते हैं कि प्रदेश की आम जनता सरेआम हो रही गुंडागर्दियों से परेशान है. आए दिन खबरें आती हैं कि छेड़खानी का विरोध करने पर युवती को

मारा गया, उसके पिता या भाई को मारा गया या कोई युवक सामने आया तो उसे मार डाला गया. मेरठ और हमीरपुर की घटनाओं को अगर हम सामने रखें तो उत्तर प्रदेश सरकार के नाकारेपन को प्रमाणित करने के लिए किसी अन्य घटना का हवाला देने की जरूरत नहीं है. युवती से सरेआम छेड़खानी कर रहे गुंडों का विरोध करने पर पिछले दिनों मेरठ में एक फौजी को सड़क पर ही पीट-पीट कर मार डाला गया. इसी तरह हमीरपुर में छेड़खानी से आजिज युवती के बचाव में कोई पुलिस-प्रशासन आगे नहीं आया तो उसने विवश होकर आत्महत्या कर ली. इसके खिलाफ आम लोगों ने प्रदर्शन किया तो पुलिस ने गोली मार कर दो युवकों की हत्या कर दी. हमीरपुर घटना के विरोध में लोगों को गोलबंद होते देख कर सरकार ने फौरन मुआवजा देने और सीबीआई जांच की घोषणा करने की औपचारिकता निभाई, लेकिन औपचारिकताओं के प्रहसन से न युवती की जान वापस आ सकती है और न उस फौजी का सम्मान वापस आ सकता है, जिसने युवती की प्रतिख़ बचाने के लिए खुद जान दे दी.

मेरठ घटना मामले में तूल पकड़ता देख कर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने गुंडों के हाथों मारे गए फौजी वेदमित्र चौधरी के परिजनों को 10 लाख रुपये का मुआवजा देने की घोषणा की. मेरठ में कुछ बदमाशों द्वारा की जा रही छेड़खानी से युवती को बचाने की कोशिश कर रहे फौजी वेदमित्र चौधरी को गुंडों ने बीच सड़क पर ही भारी हथियार और लोहे की रॉड से पीट-पीट कर मार डाला, लेकिन कोई बचाने नहीं आया. गुंडों ने एक सैनिक की नृशंस हत्या कर आजादी का जश्न मनाया और प्रदेश के लोगों को स्वतंत्रता की असलियत का एक बार फिर से अहसास हुआ. महज 33 साल के वेदमित्र चौधरी सेना की 416वीं इंजीनियर ब्रिगेड में लांस नायक के पद पर तैनात थे. लांस नायक वेदमित्र चौधरी 2001 में भारतीय सेना में भर्ती हुए थे. चौधरी वर्ष 2006 में संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन पर सूडान में तैनात थे. उनकी पत्नी बबिता देवी और नौ साल की बेटी और सात साल का बेटा है. फौजी ने अपना कर्तव्य निभाते हुए लड़की के साथ हो रही छेड़खानी का विरोध किया, तो उसे इसका हर्जाना अपनी जान देकर चुकाना पड़ा. जिस तरह सत्ता नौटंकी करती है उसी तरह पुलिस और प्रशासन तंत्र भी नौटंकीबाज है. कार्रवाई चल रही है का नाट्य-संवाद जारी है, जबकि मारे गए फौजी के अंतिम संस्कार की रस्में भी अब पूरी होने पर हैं.

छेड़खानी का शिकार लड़की घर के पास ही डेयरी का व्यवसाय करने वाले अपने पिता को चाय देने गई थी. इस दौरान वहां मौजूद कुछ लोग उससे छेड़छाड़ करने लगे. सेना के लांस नायक वेदमित्र चौधरी उसी दुकान पर दूध लेने गए थे. लड़की से छेड़खानी होती देखकर उन्होंने गुंडों को ऐसा करने से रोका, लेकिन आरोपियों ने उल्टे उन्हीं पर हमला बोल दिया. लड़की के पिता भी इस हत्याकांड के चश्मदीद गवाह हैं. वे बताते हैं कि फौजी वेदमित्र ने जब गुंडों को रोकने की कोशिश की, तो उनमें से एक लड़के ने फौजी को चांटा मार दिया और इससे झगड़ा बढ़ गया. इतने में गांव के कुछ और लोग हथियार लेकर वहां पहुंच गए और उस जवान को पीट-पीटकर वहीं मार डाला. लड़की के 17 वर्ष के भाई ललित कुमार ने कहा कि फौजी को लोग पीटते रहे और पचासों लोग तमाशाई बने देखते रहे. लड़की का कहना है कि पिछले कई दिनों से आरोपी उसके साथ छेड़खानी कर रहे थे, लेकिन डर के मारे उसने परिवार को नहीं बताया था. लड़की को यह डर था कि छेड़खानी की शिकायत करने पर उसके अभिभावक उसकी पढ़ाई बंद करा देंगे. फौजी की हत्या के बाद लड़की का परिवार और घटना का चश्मदीद गवाह उसके पिता दहशत में हैं. पुलिस का कोई अधिकारी पूछने भी नहीं आया, सुरक्षा की तो बात ही दूर रही. कई हत्यारे अब तक पकड़े नहीं गए हैं. यह प्रदेश की कानून व्यवस्था का हाल है. पुलिस से कार्रवाई के बारे में पूछा गया तो जवाब मिला, पुलिस स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों में व्यस्त है.

इसी तरह हमीरपुर के बिंवार इलाके में युवती स्वीकृति खरे से लगातार छेड़खानी की जा रही थी. स्वीकृति के बचाव में न पुलिस आई और न 1090 की सियासी-नौटंकी काम आई. छेड़खानी से आजिज आकर आखिरकार स्वीकृति ने 25 जुलाई को अपने ही शरीर में आग लगा कर आत्महत्या कर ली. इस घटना के ख़िलाफ जब लोगों ने लोकतांत्रिक विरोध जताया, तो पुलिस ने गोली मार कर 18 साल के युवक रोहित पांडेय और 23 साल के कल्लू खां को मार डाला. पुलिस की फायरिंग में जयकरन समेत दो युवक बुरी तरह जख्मी हुए. तनाव इतना बढ़ा कि गुस्साए लोगों ने पुलिस की जीप जला दी और पथराव किया. इस घटना के बाद जब प्रदेश की सियासत गर्म होने लगी तो मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने हमीरपुर के एसपी दिनेशपाल सिंह और बिंवार के थाना प्रभारी गिरेंद्र सिंह को निलंबित कर दिया. गुंडागर्दी के ख़िलाफ नाराजगी जताने वाले लोगों पर फौरन गोलियां दागने वाली पुलिस ने शोहदों को गिरफ्तार करने में कोई त्वरित सक्रियता नहीं दिखाई. बाद में जीतेंद्र यादव नाम का एक शोहदा पकड़ा गया, लेकिन दूसरे गुंडे मौज कर रहे हैं.

स्वीकृति खरे की खुदकुशी का मामला धीरे-धीरे गरमाता जा रहा है. समाजवादी पार्टी की सरकार को इसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहने की राजनीतिक-सामाजिक चुनौतियां-चेतावनियां मिलने लगीं, तब सरकार ने मामले की सीबीआई से जांच कराने और स्वीकृति के परिवार और पुलिस की गोली से मारे गए युवकों के परिवार को पांच-पांच लाख रुपये का मुआवजा देने की घोषणा की. सीबीआई जांच की घोषणा पर हैरत जताते हुए स्थानीय लोगों ने कहा कि भ्रष्टाचार के बड़े-बड़े मामलों पर तो सरकार सीबीआई जांच से कन्नी काटती है, लेकिन हमीरपुर-बिंवार में छेड़खानी की घटना रोजाना सार्वजनिक रूप से होती रही, लोग-बाग इसके बारे में अच्छी तरह जानते हैं और इसके गवाह हैं, इसके बावजूद सरकार ने इसकी सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी, यह आश्चर्यजनक है. ■

feedback@chauthiduniya.com

अब अपने ही कहने लगे कानून व्यवस्था खराब

अखिलेश यादव ने उन्हें विधान परिषद का सदस्य मनोनीत किया और वे एमएलएसी बनते ही कहने लगे कि यूपी में कानून व्यवस्था बहुत खराब है. अखिलेश यादव ने उन्हें सारी मर्यादाएं लांघ कर प्रदेश का पुलिस महानिदेशक बनाया और वे डीजीपी बनते ही कहने लगे यूपी में बहुत अपराध है. एमएलसी रामवृक्ष यादव और डीजीपी जगमोहन यादव कुछ भी बोलें, वे तो अखिलेश यादव के अपने हैं. आईपीएस अमिताभ ठाकुर या आईएएस सूर्य प्रताप सिंह बोलें तब सरकार को दिक्कत होने लगती है और ऐसे अफसरों को औकात में रखने का मुख्यमंत्री को मन करने लगता है. अखिलेश के चहेते डीजीपी जगमोहन यादव ने पिछले दिनों इलाहाबाद में पत्रकारों से कहा कि यूपी में अपराध बेतहाशा बढ़ गए हैं और प्रदेश की जनता बढ़ते अपराधों से परेशान है. उनका कहना है कि सड़कों पर गुंडागर्दी हो रही है और जनता इससे त्रस्त है. दिन के वक्त सड़कों पर होने वाली गुंडागर्दी की घटनाएं लोगों के मन में पुलिस को लेकर गलत सोच पैदा कर रही हैं. डीजीपी ने कहा कि हत्या-डकैती और लूट जैसी घटनाओं पर तो लोग मानते हैं कि देर-सबेर उसका खुलासा हो जाएगा, लेकिन सड़कों पर हो रही गुंडागर्दी की घटनाएं लोगों में डर पैदा कर रही हैं. सड़कों, चौराहों व दूसरी सार्वजनिक जगहों पर गुंडागर्दी करने वाले लोगों के ख़िलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए. जगमोहन यादव ने बात सही और सटीक कही, अपराध रोकने वाले तंत्र के मुखिया होने के नाते उनके इस बयान ने इशारा किया है कि सत्ता-पोषित गुंडागर्दी के कारण पुलिस भी सख्त कार्रवाई करने से लाचार है. डीजीपी जगमोहन यादव ने अभी हाल ही में यह भी कहा था कि कुछ पुलिस अधिकारियों ने पुलिस मुख्यालय में लूट और अंधेरगर्दी मचा रखी है. डीजीपी का यह बयान अखबारों में तो छिटपुट छप कर रह गया, जबकि यह एक गंभीर स्वीकारोक्ति है और इस पर सरकार को फौरन सख्त कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन सरकार की प्राथमिकताएं कुछ और हैं. वाराणसी में कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक में डीजीपी जगमोहन यादव ने यह भी कहा कि पुलिस से दलाली का दाग मिटाना आसान नहीं है. डीजीपी ने यह भी कहा कि जेलों में बंद माफिया जो धंधा चला रहे हैं, उसके पीछे दलाली में पुलिसकर्मी शामिल हैं. जमीन-जायदाद पर कब्जा करने की घटनाओं में भी पुलिस किसी न किसी के पक्ष में खड़ी हो जाती है. प्रॉपर्टी को लेकर लगातार बढ़ रहा अपराध और हिंसक संघर्ष इसी वजह से है. प्रदेश के पुलिस महानिदेशक के इस तरह के वक्तव्य पर भाजपा के प्रवक्ता विजय बहादुर पाठक ने कहा, प्रदेश के डीजीपी तो ठीक मुलायम सिंह यादव का अनुसरण कर रहे हैं. मुलायम भी मंचों पर यूपी सरकार के मंत्रियों के भ्रष्टाचार और उनकी संदिग्ध गतिविधियों के बारे में सब कुछ जानने का दावा करते हैं, लेकिन कार्रवाई की कोई ठोस पहल नहीं करते. डीजीपी भी कार्रवाई के बजाय केवल बयानबाजी ही कर रहे हैं. बहरहाल, नव-मनोनीत एमएलसी रामवृक्ष यादव ने भी यूपी की बदहाल क़ानून व्यवस्था के लिए प्रदेश की जनता से माफी मांगी है. एमएलसी बनने के बाद इलाहाबाद पहुंचे विधायक रामवृक्ष यादव ने साफ तौर पर कहा कि यूपी में कानून व्यवस्था के जो हालात हैं, उस पर उन्हें खेद है. रामवृक्ष ने बात संभालने की कोशिश भी की, लेकिन बात निकल गई तो संभलती कहां है. वे फिर बोल गए कि अपराध की वारदातों पर उन्हें कोई अफसोस नहीं है, लेकिन इन घटनाओं पर वह लोगों से खेद जरूर जताना चाहते हैं. फिर रामवृक्ष यादव ने यह भी कह दिया कि उत्तर प्रदेश की आबादी ज्यादा है इसलिए अपराध भी ज्यादा है और इसीलिए सरकार को क़ानून व्यवस्था संभालने में दिक्कत पेश आती है. अब आप समझ ही सकते हैं कि अखिलेश यादव के चयन की प्राथमिकताएं क्या हैं और उनके चयन-स्तर पर बार-बार उंगली उठाने वाले राज्यपाल राम नाईक की चिंता क्या है. बहरहाल, प्रदेश की कानून व्यवस्था की बदहाली के ख़िलाफ कांग्रेस के जोरदार प्रदर्शन के जवाब में भारतीय जनता पार्टी ने भी राष्ट्रपति से मिल कर यूपी सरकार के ख़िलाफ चार्जशीट पेश करने का फैसला किया है. भाजपा की प्रदेश इकाई केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह के समक्ष भी यूपी की बदतर स्थिति का प्रमाण पेश करेगी और समुचित कार्रवाई की मांग करेगी. पार्टी का प्रदेश नेतृत्व इस मामले में राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह से भी हस्तक्षेप करने का आग्रह करने जा रहा है. भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. लक्ष्मीकांत बाजपेयी ने यह जानकारी देते हुए कहा कि यूपी की बदहाल कानून व्यवस्था के ख़िलाफ राष्ट्रपति से मिलने जा रहे भाजपाई प्रतिनिधिमंडल में भाजपा के प्रदेश के सभी सांसद, सभी विधायक, सभी प्रदेश पदाधिकारी और अन्य नेता शामिल रहेंगे. मुलाकात के लिए राष्ट्रपति से समय मांगा गया है.

पोस्टमॉर्टम कराए बिना अंतिम संस्कार

छेड़खानी से आजिज आकर खुदकुशी करने वाली स्वीकृति खरे के शव का पोस्टमॉर्टम कराए बगैर पुलिस ने जल्दी-जल्दी अंतिम संस्कार करा दिया. स्वीकृति की मां किरण खरे ने आरोप लगाया है कि पुलिस ने कोई जांच या पोस्टमॉर्टम कराए बगैर ही शव की अंत्येष्टि कर दी. हालांकि जिलाधिकारी संध्या तिवारी इस आरोप का खंडन करती हैं. लड़की का परिवार सरकार का मुआवजा लेने से इन्कार कर रहा है. पूरे इलाक़े में अब भी भीषण तनाव व्याप्त है. ■

पुलिस के ख़िलाफ दुष्कर्म के 23 मामले

पुलिस थानों और दूसरी जगहों पर 2014 जनवरी से लेकर फरवरी 2015 के बीच पुलिस वालों के ऊपर बलात्कार के 23 मामले दर्ज हुए हैं. विधानसभा में भाजपा विधायक श्यामदेव रायचौधरी के सवाल पर सरकार ने यह आधिकारिक आंकड़ा पेश किया. सरकार ने अपने जवाब में बताया बलात्कार के इन मामलों में पुलिस के 29 कर्मचारी नामजद हुए, जिनके खिलाफ कार्रवाई या विभागीय जांच चल रही है. आपको याद ही होगा कि लखनऊ के ही उप-शहर बाराबंकी के कोठी थाने में एक पत्रकार की मां के साथ थाना प्रभारी और एक दारोगा ने मिल कर बलात्कार करने की कोशिश की थी और नाकाम रहने पर उसे जला कर मार डाला था. ■

उत्तर प्रदेश की खबरें इंटरनेट पर पढ़ने के लिए www.up.chauthiduniya.com लॉगऑन करें.

www.chauthiduniya.com
चौथी दुनिया

मुलायम सिंह ने कहा पंचायत चुनावों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए, लेकिन मुझे तो कोई तैयारी दिख नहीं रही है. मुलायम ने अखिलेश यादव से पूछा, पंचायत चुनाव सिर पर हैं, उसके लिए पार्टी की क्या तैयारी है? अगले साल विधान परिषद के 36 सदस्यों का चुनाव भी होना है. मैं नहीं जानता कि उसके लिए क्या तैयारी की जा रही है. मुलायम सिंह ने कहा, मैं विधानसभा चुनाव का टिकट चाहने वाले लोगों से कहना चाहता हूं कि पंचायत चुनाव में अगर वे अपने क्षेत्र में सपा प्रत्याशियों को जीत नहीं दिला सके, तो पार्टी उनकी उम्मीदवारी पर दोबारा विचार करेगी.

वरिष्ठ आईएएस अधिकारी सूर्य प्रताप सिंह की छलकी पीड़ा

बेलगाम सरकार से नौकरशाह त्रस्त

प्रदेश की क़ानून व्यवस्था पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा सुर्य प्रताप सिंह ने कहा कि हर चौराहे पर दुःशासन और दुर्योधन खड़ा है. मां-बेटियां घर से निकलती हैं, तो यह गारंटी नहीं होती है कि वे सुरक्षित घर लौट पाएंगी या नहीं.

संतोष देव गिरि

उत्तर प्रदेश में कुछ भी ठीक-ठाक नहीं चल रहा है. कानून व्यवस्था हो या सरकार की नीतियां, सभी लचर हैं और सब पर विरोध हो रहा है. मंत्रियों और विधायकों के आचरण पर सरेआम उगंलियां उठ रही हैं. सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव खु ही सरकार के कामकाज पर उंगली उठाते रहते हैं. सरकार के अधिकारी भी कहने लगे हैं प्रदेश में सब कुछ ठीक नहीं है. सरकार की लचर नीतियों, भ्रष्टाचार और बदहाल कानून व्यवस्था पर बेबाक टिप्पणी करने वाले नौकरशाह प्रमुख सचिव सार्वजनिक उद्यम डॉ. सूर्य प्रताप सिंह ने एक बार फिर समाजवादी पार्टी सरकार पर हमला बोला. पिछले दिनों जौनपुर आए सूर्य प्रताप सिंह ने कहा कि मौजूदा समय में प्रदेश का किसान परेशान हो गया है. कानून व्यवस्था की हालत ऐसी हो गई है कि मानों प्रदेश के हर चौराहे पर दु:शासन और दुर्योधन खड़ा है. यही नहीं आईएस और आईपीएस अधिकारी भी डरने लगे हैं. उन्होंने कहा कि सरकार में 40 फीसदी मंत्री और विधायक अपराधी हैं. उन्होंने कहा कि वह प्रदेश के सभी जनपदों का दौरा कर सरकार का कच्चा चिट्ठा खोलेंगे. हर जगह की पांच समस्याओं को उठाएंगे, जो वहां के आमजन से जुड़ी होगी. इसके पीछे उनका उद्देश्य सरकार या किसी व्यक्ति की आलोचना करना नहीं, बल्कि जरूरी मसले उठाना और उसके समाधान के लिए दबाव बनाना है. उन्होंने कहा कि भारी बरसात से किसानों की फसलों को हुई छति का मुआवजा अभी मात्र 33 फीसदी ही मिला है. 2014 के सूखा राहत का एक भी पैसा किसानों को नहीं दिया गया है. गन्ना किसानों का करोड़ों रुपया सरकार पर बकाया है.

उन्होंने कहा कि मां-बेटियां घर से निकलती हैं, तो यह गारंटी नहीं होती है कि वे सुरक्षित घर लौट पाएंगी या नहीं. हालात इतने खरा हैं कि आज आईएएस आईपीएस अधिकारी भी प्रदेश में सुरक्षित नहीं हैं. सूर्य प्रताप सिंह ने यमुना एक्सप्रेस-वे का विरोध करते हुए कहा कि 20 हजार करोड़ रुपये क्यों खर्च किए जा रहे हैं. जबकि उस जगह दो-दो नेशनल हाईवे हैं. उनको सुधारने में पांच सौ करोड़ रुपये लगेंगे. उन्होंने आरोप लगाया कि आगरा, लखनऊ एक्सप्रेस वे को केवल 4-5 जनपदों को लाभ पहुंचाने के लिए बनाया जा रहा है. यदि हाईवे बनाना ही है, तो सरकार लखनऊ से बलिया व वाराणसी तक बनाए ताकि 10-12 जनपदों के लोगों को लाभ मिले. उन्होंने नेताओं, मंत्रियों और अधिकारियों से सवाल किया कि क्या उन्हें एनएच-56 की दुर्दशा नहीं दिखाई देती है. सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा कि यमुना एक्सप्रेस वे बनने से पहले सरकार से जुड़े दलालों ने जमीन औने-पौने दामों में खरीद ली थी. उसके बाद सरकार को चार गुना दामों में बेच कर वे करोड़पति बन गए. यह सुनियोजित खेल था, जिसमें नेता, नौकरशाह और दलाल शामिल थे. सूबे में आम आदमी के लिए अलग कानून है और अमीर आदमी के लिए अलग. यहां बिना जुगाड़ के थानों में रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है. छोटी-छोटी समस्याओं के लिए रिश्वत देना पड़ता है. इन समस्याओं के निदान की बात की जाती है तो कहा जाता है कि नेतागीरी कर रहे हैं. यदि नेतागीरी बुरी बात है तो जो लोग राजनीति करते है वे राजनीति छोड़ क्यों नहीं देते.

सूर्य प्रताप सिंह कहते हैं कि प्रदेश में राजनेता बनने के लिए स्कूल माफिया होना चाहिए. खनन माफिया होना चाहिए और 50 गुंड़े होने चाहिए. यही नहीं 4-5 करोड़ रुपये भी होने चाहिए.

सूर्य प्रताप सिंह कहते हैं कि प्रदेश में राजनेता बनने के लिए स्कूल माफिया होना चाहिए. खनन माफिया होना चाहिए और 50 गुंड़े होने चाहिए. यही नहीं 4-5 करोड़ रुपये भी होने चाहिए. इसके बाद पैसे के बल पर टिकट लेकर सांसद-विधायक बन सकेंगे. जब प्रदेश में आईएएस आईपीएस अधिकारी ही डर कर रहता है, तो प्रदेश की कानून व्यवस्था का अंदाजा लगाया जा सकता है. नियुक्तियों में भ्रष्टाचार पर सिंह बोले कि लोकसेवा आयोग के अध्यक्ष अनिल यादव के भ्रष्टाचार और जातिवाद के साथ यूपी बोर्ड में नकल मुख्य मसला है. लोकसेवा आयोग संवैधानिक संस्था है, सरकार की जातिगत जागीर नहीं. जहां प्रतिभा और गुणवत्ता को दरकिनार किया जा रहा है. युवाओं की मेहनत बेकार जा रही है. एक सवाल के जवाब में सूर्य प्रताप सिंह ने कहा कि नौकरी से स्वैच्छिक अवकाश मांगने पर उसे खारिज कर दिया जाता है और कार्रवाई का कुचक्र रचा जाता है. अब रिटायरमेंट के कुछ ही महीने बचे हैं, इसके बाद वे सीधे आमजनों के साथ सड़क पर उतरेंगे. ■

feedback@chauthiduniya.com

ताकि राजनीति में हनक बनी रहे

उत्तर प्रदेश खासकर पूर्वांचल की राजनीति में अपराध जगत से नाता रखने वाले दागियों की दखलंदाजी कोई नई बात नहीं है. ऐसे दागदार माननीयों की एक लम्बी फेहरिस्त है जो अपने बचाव के लिए राजनीति का दामन थामे रहते हैं. माफिया से माननीय बने पूर्वांचल के एक बाहुबली अपनी पत्नी को राजनीति में उतारने के बाद अब अपने बड़े भाई को भी इस फील्ड में उतारने की तैयारियों में जुट गए हैं. बस औपचारिक घोषणा होनी बाकी है. पूर्वांचल के चर्चित माफिया माननीय श्यामनारायण उर्फ विनीत सिंह वर्तमान में सोनभद्र, मिर्जापुर विधान परिषद सीट से बसपा कोटे से एमएलसी हैं. इनकी पत्नी प्रमिला सिंह जिला पंचायत मिर्जापुर की अध्यक्ष हैं. एमएलसी विनीत सिंह के बड़े भाई और वाराणसी जिले के चोलापुर ब्लाक के पूर्व ब्लाक प्रमुख त्रिभुवन सिंह भी अब राजनीति में पैर जमाने की तैयारी में हैं. वे इसके लिए अपनी मातृभूमि वाराणसी को कर्मभूमि चुनने के बजाए मिर्जापुर को चुनने जा रहे हैं. 15 अगस्त को स्वंत्रता दिवस पर एक प्रमुख समाचार पत्र में छपे विनीत सिंह और प्रमिला सिंह के संग त्रिभुवन सिंह के बधाई संदेश ने इन कयासों की पुष्टि की है. वाराणसी में राजनीति में विफल होने के बाद उन्होंने विंध्य और सोनांचल की धरती की ओर रुख किया और बसपा का दामन थाम कर वाया मिर्जापुर विधान परिषद पहुंचे. फिर उन्होंने अपनी पत्नी को जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पर काबिज करा दिया. इस कुर्सी पर लगातार दो बार से समाजवादी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष शिवशंकर सिंह यादव की पत्नी प्रभावती देवी काबिज होती आ रही थीं. प्रदेश में 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने के बाद कई जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पर खतरे के बादल मंडराने लगे थे और उन पर सपा अपनों को बैठाने में कामयाब भी हुई, लेकिन जिला पंचायत मिर्जापुर की कुर्सी के लिए जोर आजमाइश खूब हुई पर सपा के लिए परिणाम निराशाजनक रहा. इससे विनीत सिंह का दबदबा और भी कायम हुआ. बताया जाता है कि एमएलसी विनीत सिंह अब अपनी कर्मभूमि चंदौली जनपद से विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं और अपने बड़े भाई पूर्व प्रमुख त्रिभुवन सिंह को विधान परिषद की सदस्यता दिलवाना चाहते हैं. पूर्वांचल में माफियाओं और माननीयों का घालमेल कोई नया नहीं है. गाजीपुर में मुख्तार अंसारी, वाराणसी, चंदौली में बृजेश सिंह, इलाहाबाद में अतीक अहमद, जौनपुर में धनंजय सिंह, आजमगढ़ में रमांकात यादव, भदोही में विजय मिश्रा जैसे कई नाम हैं जो माफियाई राजनीति के गौरव-चिन्ह हैं.

उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव

मुलायम की फटकार के बाद नींद से जागी समाजवादी पार्टी

मुलायम सिंह ने कहा पंचायत चुनावों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए, लेकिन मुझे तो कोई तैयारी दिख नहीं रही है. मुलायम ने अखिलेश यादव से पूछा, पंचायत चुनाव सिर पर हैं, उसके लिए पार्टी की क्या तैयारी है?

प्रभात रंजन दीन

मुलायम सिंह यादव द्वारा आड़े हाथों लेने के बाद उस तगड़े झटके से उबरने की कोशिश करती समाजवादी पार्टी की प्रदेश इकाई पंचायत चुनाव की तैयारियों में जुट गई है. 2017 के विधानसभा चुनाव में उतरने के पहले समाजवादी पार्टी के लिए पंचायत चुनाव में अपनी पकड़ दिखाना अनिवार्य हो गया है, लेकिन पार्टी की अंदरूनी स्थिति की असलियत को आईना खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव पिछले दिनों दिखा चुके हैं और लगातार दिखाते रहे हैं. इसके बावजूद पार्टी सुधरने का नाम नहीं ले रही है. अनुशासनहीनता की हालत यह है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा बार-बार मांगने के बावजूद उन्हें लोकसभा चुनाव में हार की समीक्षा रिपोर्ट नहीं दी जा रही है. मुलायम सिंह यादव ने पिछले दिनों सार्वजनिक मंच से कहा कि लोकसभा चुनाव में पार्टी की करारी हार के कारणों के बारे में उन्हें अब तक रिपोर्ट नहीं दी गई, जबकि प्रदेश नेतृत्व को इस बारे में बार-बार निर्देश दिया गया. सपा के एक नेता ने कहा कि छोटी-छोटी ग़लतियों पर भी पार्टी कार्यकर्ताओं पर अनुशासनिक कार्रवाई करने में देरी नहीं होती, लेकिन मुलायम सिंह के पुत्र ही अनुशासनहीनता कर रहे हैं, तो कार्रवाई कैसे होगी? अखिलेश यादव पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं. समीक्षा रिपोर्ट न मिलने से नाराज़ मुलायम सिंह ने कहा कि अगले विधानसभा चुनाव में बड़ी संख्या में प्रदेश के मंत्री चुनाव हारने जा रहे हैं. मुलायम सिहं ने कहा, हमने आपसे लोकसभा चुनाव में कड़ी मेहनत करने को कहा था, लेकिन आपने हमें कहीं का नहीं छोड़ा. सिर्फ़ परिवार के पांच लोग ही लोकसभा पहुंच सके. मुलायम ने कहा, मुझे लोगों से जानकारी मिली है कि बड़ी संख्या में मंत्रियों को 2017 के विधानसभा चुनाव में हार का स्वाद चखना पड़ेगा. अब भी समय है, आप मंत्री लोग वातानुकूलित कमरों से बाहर निकलिए और लोगों तक सरकार के कार्यों को पहुंचाइए.

मुलायम सिंह ने कहा पंचायत चुनावों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए, लेकिन मुझे तो कोई तैयारी दिख नहीं रही है. मुलायम ने अखिलेश यादव से पूछा, पंचायत चुनाव सिर पर हैं, उसके लिए पार्टी की क्या तैयारी है? अगले साल विधान परिषद के 36 सदस्यों का चुनाव भी होना है. मैं नहीं जानता कि उसके लिए क्या तैयारी की जा रही है. मुलायम सिंह ने कहा, मैं विधानसभा चुनाव का टिकट चाहने वाले लोगों से कहना चाहता हूं कि पंचायत चुनाव में अगर वे अपने क्षेत्र में सपा प्रत्याशियों को जीत नहीं दिला सके, तो पार्टी उनकी उम्मीदवारी पर दोबारा विचार करेगी. मुलायम बोले कि पंचायतों के बल पर ही मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने पश्चिम बंगाल पर 34 सालों तक राज किया. मुलायम सिंह ने सपाइयों को हिदायत दी कि वे अराजकता से बाज आएं और ज़िलों में प्रशासन के अधिकारियों पर दबाव न डालें. सार्वजनिक रूप से डांट खाने के बाद पार्टी कुछ हरकत में आई और प्रदेश में साइकिल यात्राएं करने का निर्णय लिया गया. एक ज़मीनी सपा नेता ने कहा कि पार्टी नेतृत्व को अभी भी भ्रम है. सपा को लगता है कि पिछली बार अखिलेश यादव द्वारा साइकिल से घूमने से वोट मिला था, जबकि सपा को वोट मायावती शासनकाल की अराजकता, भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी के कारण मिला था. लेकिन, सत्ता मिलते ही सपा खुद मायावती का अनुसरण करने लगी, लिहाजा, इस बार सपा के लिए बहुत मुश्किल होगी. साइकिल यात्राओं से लोगों की नाराज़गी बढ़ रही है. लोगों का कहना है कि अब तक मुख्यमंत्री एवं मंत्रियों को सड़क और जनता नहीं दिखी. जब पंचायत चुनाव आया, तो सड़क दिखने लगी.

प्रशासनिक तैयारियां जोरों पर

पंचायत चुनाव की तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं. पहले चरण में 77,925 क्षेत्र पंचायतों एवं 3,128 ज़िला पंचायतों के सदस्य पदों के लिए चुनाव होने हैं. दूसरे चरण में 59,163 ग्राम प्रधानों एवं 7,45,603 ग्राम पंचायत सदस्यों के लिए चुनाव होंगे. प्रदेश में एक साथ प्रत्येक चरण के दोनों पदों के लिए हर ज़िले को ब्लॉक वार चार-पांच भागों में बांटकर चुनाव कराए जाएंगे. 2010 में चुनाव में कुल 7,62,277 पंचायत प्रतिनिधियों (ग्राम पंचायत के प्रधान एवं सदस्य, क्षेत्र पंचायत एवं ज़िला पंचायत के सदस्य) को सीधे जनता ने चुना था. 1995 के बाद पहली बार पूरे प्रदेश में पुनर्गठन के बाद इस बार 8,85,819 पदों के लिए चुनाव होंगे. मतदान के लिए 1.85 लाख बूथ बनाए जाएंगे. उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आरक्षण की पुरानी व्यवस्था बनी रहेगी. अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जातियों के लिए प्रदेश में आरक्षित किए जाने वाले कुल पदों का निर्धारण 2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर होगा. 2011 की जनगणना के मुताबिक, अनुसूचित जाति की आबादी 20.69 प्रतिशत और अनुसूचित जनजाति की आबादी 0.56 प्रतिशत है. त्वरित सर्वेक्षण में 2015 के आधार पर प्रदेश की ग्रामीण जनसंख्या में पिछड़े वर्गों का प्रतिशत 53.33 है. प्रदेश में ग्राम पंचायतों की संख्या 59,163 है, जबकि 821 क्षेत्र पंचायतें और 75 ज़िला पंचायतें हैं.

एआईएमआईएम लड़ेगी पंचायत चुनाव

ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलमीन (एआईएमआईएम) उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का सेमी फाइनल माने जा रहे त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों की जंग लड़ने की तैयारी में है. असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी राज्य में 2017 में होने वाले विधानसभा चुनाव की रणनीति तैयार करेगी. राज्य में क़रीब तीन करोड़ 60 लाख मुसलमान हैं. 80 में से क़रीब 34 लोकसभा क्षेत्र ऐसे हैं, जहां इनका खासा प्रभाव माना जाता है. एआईएमआईएम के नेता तौगीग अहमद सिद्दीकी ने राज्य के पंचायत चुनावों में उतरने का संकेत देते हुए कहा कि पार्टी कुछ ही स्थानों पर प्रत्याशी खड़ा करेगी.

महिलाओं को कुछ नहीं मिला

प्रदेश में पंचायत चुनाव होने वाले हैं. हमेशा की तरह इस बार भी पंचायतों में महिलाओं के लिए पचास प्रतिशत सीटों के आरक्षण का मुद्दा जहां का तहां खड़ा है. केंद्रीय मंत्रिमंडल की ओर से अगस्त 2009 में महिलाओं के आरक्षण के मुद्दे को लेकर बने विधेयक में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी जा चुकी है, जिसके बाद कई राज्यों ने पंचायतों में महिलाओं के लिए पचास प्रतिशत सीटें आरक्षित कर दीं. इस मामले में बिहार सबसे आगे रहा. महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, केरल एवं कर्नाटक में भी यह आरक्षण लागू किया गया. उत्तर प्रदेश में इस साल होने वाले पंचायती चुनावों में महिला मतदाताओं की संख्या क़रीब पांच करोड़ है, जबकि पुरुष मतदाता क़रीब साढ़े छह करोड़ हैं. महिला मतदाताओं की इतनी बड़ी तादाद के बावजूद अखिलेश सरकार उनके लिए कुछ नहीं कर रही है. ■

feedback@chauthiduniya.com

परियोजना से बिजली उत्पादन के प्रारम्भ नहीं होने का खामियाजा प्रदेश की जनता को भुगतना पड़ रहा है. परियोजना से बिजली उत्पादन प्रारम्भ नहीं होने के कारण प्रदेश सरकार को 2015-16 के लिए अतिरिक्त बिजली खरीदनी पड़ रही है, जिससे 864 करोड़ रुपये का बोझ जनता पर पड़ा है. यही नहीं, परियोजना के निर्माण कार्यों में लगी संविदा कम्पनियों ने भी अरबों रुपये के विभिन्न टैक्स, रॉयल्टी आदि की चोरी की, वहीं सरिया और सीमेन्ट की भी बड़े पैमाने पर चोरी हुई.

हजार मेगावाट की अनपरा डी विद्युत परियोजना आठ वर्षों में 7027 करोड़ रुपये से बनी

धन का फंडा, देरी का हथकंडा

महेंद्र अग्रवाल

1000 मेगावाट की अनपरा डी विद्युत परियोजना को लेकर न केवल मायावती ने अपने कार्यकाल में बल्कि अखिलेश यादव ने भी अपने कार्यकाल में उत्तर प्रदेश को बिजली संकट से छुटकारा दिलाने के लिए बड़े-बड़े वादे किए, लेकिन जिस परियोजना का निर्माण 2011 में ही पूरा हो जाना चाहिए था तथा जिसके निर्माण के लिए उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम ने रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन (आरईसी) से 5000 करोड़ का लोन भी 12.5 प्रतिशत ब्याज पर लिया था. तमाम कवायद के बाद बमुश्किल इसका निर्माण हो पाया और 30 मार्च 2015 को मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पूरे लाव-लश्कर के साथ पहुंच कर लोकार्पण भी किया, लेकिन विद्युतगृह के उत्पादन का स्विच दबाने के कुछ ही घंटों में उत्पादन ठप्प हो गया. विद्युतगृह प्रबन्धन का दावा है कि प्रारम्भ में 50 मेगावाट तक उत्पादन हुआ था, लेकिन सरकार और निगम के अधिकारियों के हर सम्भव प्रयास के बावजूद विद्युतगृह से बिजली उत्पादन शुरू नहीं हो पाया. कब उत्पादन चालू होगा इसका जबाव किसी के भी पास नहीं है.

ऐश पॉण्ड पर बनने वाला यह एशिया का पहला विद्युत गृह है, जिसका निर्माण राख के ऊपर किया गया है. इसके निर्माण के लिए पाइलिंग कर प्लेटफॉर्म बनाने का काम एल एण्ड टी को दिया गया था तथा विद्युतगृह का निर्माण बीएचईएल ने किया. बताया जाता है कि लगभग 66 हजार पाइलिंग करके प्लेटफॉर्म बनाया गया. प्रत्येक पाइलिंग राख के अंदर 25 से 35 मीटर तक गहराई में की गई है. अनपरा अ और बी के निस्तारित राख के बांध पर विद्युत गृह बनाने का निर्णय लेते समय यह दावा भी किया गया था कि परियोजना के लिए जमीन का अधिग्रहण नहीं करना पड़ेगा तथा निर्माण लागत कम आएगी. बावजूद इसके निर्माण की लागत लगभग 5300 करोड़ का आकलन किया गया था, लेकिन आज परियोजना पर 7000 हजार करोड़ रुपये से अधिक का खर्च किया जा चुका है. अभी और कितनी रकम सम्बन्धित अधिकारी खाएंगे, पता नहीं है. लेकिन इतना तो तय है कि सत्ताधारी नेताओं और नौकरशाहों ने जमकर कर अपना घर भरा है. वर्ना इतनी लागत किसी भी स्थिति में नहीं आती और न ही इतनी देरी होती.

परियोजना से बिजली उत्पादन के प्रारम्भ नहीं होने का खामियाजा प्रदेश की जनता को भुगतना पड़ रहा है. परियोजना से बिजली उत्पादन प्रारम्भ नहीं होने के कारण प्रदेश सरकार को 2015-16 के लिए अतिरिक्त बिजली खरीदनी पड़ रही है, जिससे 864 करोड़ रुपये का बोझ जनता पर पड़ा है. यही नहीं, परियोजना के निर्माण कार्यों में लगी संविदा कम्पनियों ने भी अरबों रुपये के विभिन्न टैक्स, रॉयल्टी आदि की चोरी की, वहीं सरिया और सीमेन्ट की भी बड़े पैमाने पर चोरी हुई. कई कम्पनियां तो श्रमिकों की मजदूरी का पैसा लेकर ही भाग गईं. बताते हैं कि पाइलिंग के काम में जमकर भ्रष्टाचार हुआ तथा अधिकारी माला-माल हो गए. 5300 करोड़ रुपये की लागत वाली परियोजना पर 7000 करोड़ रुपये के खर्च पर न तो सरकार और न ही सम्बन्धित अधिकारी स्पष्टीकरण दे पा रहे हैं. इसके पीछे की वजह केवल भ्रष्टाचार है. विद्युत गृह का निर्माण करने वाली कम्पनी बीएचईएल अभी तक उत्पादन प्रारम्भ होने में आ रही दिक्कतों का पता नहीं लगा पाई है. कभी कहते हैं कि बेयरिंग में खराबी के कारण उत्पादन प्रारम्भ नहीं हो पा रहा है, तो कभी ब्वॉयलर के ट्यूबों में खराबी बता रहे हैं. सच्चाई तो उच्चस्तरीय जांच से ही पता चलेगी.

सूत्रों की मानें तो 30 मार्च को मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को बेवकूफ बनाकर उत्पादन प्रारम्भ होने का दावा किया गया. जबकि वास्तविकता यह है कि मुख्यमंत्री ने जो बटन दबाया था वह किसी और कार्य का बटन था. दरअसल मुख्यमंत्री के विशेष दबाव में आकर आनन-फानन में लोकार्पण और उत्पादन प्रारम्भ होने का कार्यक्रम तो आयोजित कर दिया गया, लेकिन विद्युतगृह से बिजली उत्पादन शुरू होने की स्थिति में ही नहीं था. उत्पादन में देरी तथा लागत में लगातार हो रहे वृद्धि को लेकर राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश वर्मा ने राज्य विद्युत नियामक आयोग के समक्ष शिकायत दर्ज कराते हुए पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की है. इसे गम्भीरता से लेते हुए विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष देश दीपक वर्मा ने पूरे प्रकरण पर आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है. विद्युत गृह के निर्माण से जुड़े सभी अधिकारियों सहित संविदा कम्पनियों की भी गहन जांच हो, तो परियोजना निर्माण में देरी एवं लागत बढ़ने के बहुत बड़े गोरखधंधे का खुलासा हो पाएगा. ■

feedback@chauthiduniya.com

गनर की हनक के ख्वाब पर ग्रहण

प्रदेश सरकार के 228 महानुभावों यानी दायित्वधारियों की गनर की हनक के ख्वाब पर ग्रहण लग गया है. प्रदेश शासन के गृह विभाग ने सरकार के इस फैसले पर अपनी आपत्ति जाहिर कर दी है. सूत्रों के मुताबिक गृह विभाग ने प्रदेश सरकार को सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले का हवाला देते हुए अपने फैसले पर पुनर्विचार करने को कहा है. सुप्रीम कोर्ट नेताओं की सुरक्षा और लालबत्तियों व अनावश्यक सुविधाएं दिए जाने को लेकर सख्त गाइड लाइन जारी कर चुका है. जिसके बाद प्रदेश में भी विभिन्न आयोगों व परिषदों के दायित्वधारियों की सुविधाओं को वापस ले लिया गया था. सूत्रों के मुताबिक गृह विभाग ने कहा है कि अगर महानुभावों को गनर मुहैया कराया ही जाना है, तो पहले प्रदेश सरकार का वह आदेश निरस्त किया जाना चाहिए, जिसमें विभिन्न पदों पर बैठे लोगों की सुरक्षा वापस लेने का आदेश दिया गया था. इसी चार जून को तत्कालीन मुख्य सचिव एन रविशंकर ने गोपन (मंत्रिपरिषद)विभाग की ओर से कार्यालय ज्ञाप जारी कर इन दायित्वधारियों को एक गनर मुफ्त मुहैया कराने का प्राविधान किया था. दरअसल प्रदेश में जो भी दल सत्ता में आता है, इसके कार्यकर्ता व नेता चाहते हैं कि जब वे प्रदेश में घूमें तो इनके साथ सत्ता की हनक भी दिखाई दे. इसी हनक के प्रदर्शन के लिए इन्हें या तो लालबत्ती चाहिए होती है या फिर सरकारी गनर की सुरक्षा, गनर भी इसलिए नहीं कि इनकी जान को कोई खतरा हो बल्कि इन्हें लगता है कि सरकारी गनर मिलने के बाद ही लोग महसूस करेंगे कि अमुक महानुभाव सत्ता में हैं. प्रदेश में दायित्वधारियों की तादाद को लेकर भाजपा और कांग्रेस हमेशा एक दूसरे को घेरते और कोसते रहे हैं. एक अनुमान के मुताबिक प्रदेश सरकार ने जितने दायित्व धारियों को सुविधाएं दी हैं. इसके हिसाब के एक दायित्वधारी सरकारी खजाने पर हर महीने करीब डेढ़ लाख रुपये का बोझ डालता है. पहले पार्टी कार्यकर्ताओं के दबाव और पार्टी की अंदरूनी राजनीति में संतुलन कायम करने या अपने करीबियों के लिए पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ते-छोड़ते कांग्रेस नेताओं को कई दायित्व दे गए. इस समय लालबत्तियां बांटने के कड़े विरोधी रहे हरीश रावत सत्ता में आए, तो इन्होंने भी दायित्व बांटने शुरू कर दिए. अब आलम यह है कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार 228 कांग्रेस नेताओं को दायित्व बांट चुकी है. कइयों को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया तो इनके मुंह पर लगाम लग गई, लेकिन कुछ को केवल दर्जे का कागज मिला तो वे सरकार पर वेतन भत्ते, अधिकार व हनक के लिए गनर मुहैया कराने का दबाव बनाने लगे. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने जब दायित्वधारियों से पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए मदद मांगी तो कई दायित्वधारियों ने कहा कि इन्हें जिम्मेदारी तो दी गई है. इनके पास ऐसा अधिकार नही हैं कि वे अपने संबंधित विभाग के अधिकारियों से काम करा सकें. बिना अधिकार के जब वे जनता के काम नहीं करा पाएंगे तो जनता का पार्टी को समर्थन कैसे मिलेगा. ■

-चौथी दुनिया ब्यूरो

उत्तराखंड में जैव विविधता बोर्ड की नियमावली ही नहीं

रेनू शर्मा

राज्य सरकार खुद जैव विविधता के लिए योजनाएं बनाने का दावा करती है, कड़वी सच्चाई यह है कि राज्य सरकार का वन विभाग आज तक जैव विविधता बोर्ड की नियमावली ही राज्य गठन के पन्द्रह वर्ष बाद भी नहीं बना पाया है. ऐसे में बिना नियमों के जैव विविधता सहेजने के लिए कोई काम होना संभव ही नहीं है. हालत यह है कि प्रदेश सरकार के आला अधिकारियों को भी यह पता नहीं कि जैव विविधता बोर्ड की नियमावली नहीं बनी है. आओ मनाएं हरेला अभियान के दौरान अपर मुख्य सचिव एस राजू ने पिछले माह जैव विविधता बोर्ड की बैठक बुलाई, तब पता चला कि नियमावली ही नहीं है, तो बैठक आनन-फानन में निरस्त कर दी गई. इतना ही नहीं पर्यावरण संरक्षण से जुड़ीं कई अर्द्ध सरकारी एजेंसियों से बोर्ड को मिलने वाला फंड भी प्रभावित हो रहा है. रूटीन में केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से मिलने वाला पैसा राज्य को मिलता जरूर है, यह कैसे और कहां खर्च होता है, किसी को पता नहीं. केंद्र सरकार ने जैव विविधता बोर्ड के संबंध में वर्ष 2002 में अधिनियम बनाया था. इसके बाद वर्ष 2004 से उत्तराखंड में जैव विविधता बोर्ड की नियमावली पर काम हो रहा है. राष्ट्रीय जैव विविधता बोर्ड के बार-बार पूछने पर वन विभाग ने कागजी काम दिखाना शुरू कर दिया. न्याय पंचायत स्तर पर जैव विविधता समितियां बनाने का भी दावा किया गया, जब नियमावली ही नहीं है, तो काम कैसे हो पाएगा. उत्तराखंड की जैव विविधता बचाने के लिए सरकार हाय-तौबा मचाए रहती है. साथ ही केंद्र सरकार की नमामि गंगे, निर्मल गंगा समेत कई योजनाएं ऐसी हैं, जिनमें जैव विविधता पर सबसे अधिक जोर रहता है.

(जैव विविधता बोर्ड की नियमावली तैयार हो रही है, बहुत जल्द इस संबंध में कार्य पूरा हो जाएगा. बीते माह विधायी विभाग को इसे भेज दिया गया है.- डॉ. रणबीर सिंह, प्रमुख सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग) ■

केदार नाथ में कब तक पूरा होगा मरम्मत कार्य

राजकुमार शर्मा

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग देहरादून सर्किल केदारनाथ मंदिर में चल रहे सुधार और मरम्मत कार्य को इस सीजन में पूरा करने की बात कह रहा है. धीमी गति से चल रहे सुधार और मरम्मत काम पर क्षेत्रिय विधायक शैला रानी ने गहरी पाराजगी व्यक्त की है. अब तक मंदिर के पूर्वी गेट पर आपदा में छिटके पत्थरों के स्थान पर 40 नए पत्थरों को लगाने का काम भी पूरा नहीं हो पाया है. आपदा के बाद से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की टीम चार बार केदारनाथ पहुंचकर वहां दो से तीन माह रह चुकी है.आपदा से बुरी तरह क्षतिग्रस्त धाम में अत्याधुनिक उपकरण भी सेना के हेलिकॉप्टर द्वारा पहुंचाए जाने के बावजूद भी काम की गति धीमी होने से लोग हैरान है. 25 से 35 सदस्यीय दल हर बार पहुंच रहा है. बावजूद इसके अब तक पश्चिमी गेट के टूटे दरवाजे के स्थान पर नया दरवाजा लगाने के सिवाय अन्य काम पूरे नहीं हो पाए हैं. मंदिर के पूर्वी गेट के पिलर पर 40 नए पत्थरों को लगाने में सबसे अधिक समय लग रहा है. पश्चिमी गेट के निकट सीढ़ियों के निर्माण पर भी 15 से 20 दिन का समय लग सकता है. जबकि केदारनाथ मंदिर के चारों तरफ सुरक्षा दीवार का निर्माण सहित परिसर के फर्श का सुधार जैसे बड़े काम होने शेष हैं. मंदिर के अंदर और बाहर की तरफ दीवारों की केमिकल से सफाई सहित सभा मंडप और गर्भ गृह में बिजली फिटिंग और एक्जॉस फैन भी लगने हैं. सूबे की सरकार के मुखिया हरीश रावत जिस तरह धाम को शीघ्र सजाना सवारना चाहते हैं. इस पर सरकारी तंत्र की सुस्ती भारी पड़ रही है.

"हमारे काम का कोई पैमाना नहीं होता है. केदारनाथ में पूर्वी गेट के पिलर पर तराशे गए 40 नए पत्थरों को लगाने का काम लगभग पूरा होने वाला है. पश्चिमी गेट के समीप सीढ़ियां बन रही हैं. सुरक्षा दीवार, फ्लोरिंग सहित कुछ अन्य काम भी होने हैं.

- डॉ. वीके स्वर्णकार पुरातत्वविद, एएसआई देहरादून सर्किल

जिस गति से एएसआई केदारनाथ धाम में मरम्मत व सुधार कार्य कर रहा है, इससे काम पूरा होने में वर्षों लग जाएंगे. यात्रा अब लगभग ढाई माह की रह गई है. ऐसे में इस सीजन में भी कार्यों का पूरा होना संभव नहीं है. प्रदेश सरकार और बीकेटीसी अध्यक्ष को भी इस संबंध में मैंने अवगत करा दिया है.

- शैलारानी रावत, विधायक केदारनाथ विधानसभा"

सभी जनपद वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं

एन. एन. पाण्डेय
उप प्रभागीय वनाधिकारी
निघासन, खीरी

जी. पी. सिंह
प्रभागीय वनाधिकारी
उत्तर खीरी वन प्रभाग
लखीमपुर खीरी

उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव आलोक रंजन को अदालत के फैसले को तामील कराने का निर्देश देते हुए कहा कि वह यह सुनिश्चित करें कि सरकारी, अर्द्धसरकारी विभागों के कर्मचारी, जन प्रतिनिधियों, न्यायपालिका और सरकारी खजाने से वेतन, मानदेय या धन प्राप्त करने वालों के बच्चे अनिवार्य रूप से यूपी बोर्ड द्वारा संचालित स्कूलों में शिक्षा प्राप्त करें. न्यायालय ने स्पष्ट कहा कि यदि कोई अफसर या कर्मचारी अपने बच्चे को कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाता है, तो फीस के बराबर राशि उसे हर महीने सरकारी खजाने में जुर्माने के बतौर जमा करानी होगी.

इलाहाबाद उच्च न्यायालय का ऐतिहासिक फ़ैसला

सरकारी स्कूलों में पढ़ेंगे नौकरशाह और एमपी-एमएलए के बच्चे

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 18 अगस्त को ऐतिहासिक फ़ैसला सुनाते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया कि सभी नौकरशाहों और सरकारी कर्मचारियों के लिए उनके बच्चों को सरकारी प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाना अनिवार्य कर दिया जाए. यह व्यवस्था अगले शिक्षा-सत्र से लागू हो जाएगी.

दीनबंधु कबीर

नेताओं और नौकरशाहों की उपेक्षा के कारण बर्बाद हो रहे सरकारी स्कूलों की प्राण-रक्षा के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय अब ताल ठोक कर आगे आ गया है. अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए प्राइवेट स्कूलों की तरफ भागने वाले नेताओं और नौकरशाहों के कदम उच्च न्यायालय के फैसले के कारण ठिठक गए हैं. उच्च न्यायालय ने स्पष्ट कहा है कि नौकरशाहों और नेताओं के बच्चे अब प्राइवेट स्कूलों में नहीं, बल्कि सरकारी स्कूलों में पढ़ेंगे, ताकि सरकारी स्कूलों को बर्बाद होने से बचाया जा सके. इलाहाबाद उच्च न्यायालय के इस फैसले को शिक्षाविद और आम नागरिक ऐतिहासिक फैसला बता रहे हैं.

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 18 अगस्त को यह ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया कि सभी नौकरशाहों और सरकारी कर्मचारियों के लिए उनके बच्चों को सरकारी प्राथमिक विद्यालय में पढ़वाना अनिवार्य कर दिया जाए. यह व्यवस्था अगले शिक्षा-सत्र से लागू हो जाएगी. सरकार को इसका अनुपालन सुनिश्चित कराने को कहा गया है. न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने शिवकुमार पाठक व अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया. याचिका में कहा गया था कि सरकारी परिषदीय स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति में नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है, जिसके चलते अयोग्य शिक्षकों की नियुक्ति हो रही है. इस वजह से बच्चों को स्तरीय शिक्षा नहीं मिल पा रही है. इसकी चिंता न तो संबंधित विभाग के अधिकारियों को है और न ही प्रदेश के आला प्रशासनिक अधिकारियों को इसकी कोई फिक्र है. इस पर नाराज उच्च न्यायालय ने सख्ती से यह निर्देश दिया कि प्रदेश के आईएएस-आईपीएस अधिकारी, सरकारी कर्मचारी और जन-प्रतिनिधियों के बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाना अनिवार्य किया जाता है.

अदालत ने सरकार को यह भी निर्देश दिया कि इस फैसले की अनदेखी करने वाले व्यक्ति के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान किया जाए. जिनके बच्चे कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ेंगे, वहां की फीस के बराबर रकम उनके वेतन से जुर्माने के बतौर काट ली जाए. साथ ही ऐसे लोगों का कुछ समय के लिए इन्क्रीमेंट व प्रमोशन रोकने की व्यवस्था भी की जाए. अगले शिक्षा सत्र से इस व्यवस्था को लागू किया जाए. न्यायालय ने स्पष्ट कहा कि जब तक इन लोगों के बच्चे सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ेंगे, वहां के हालात नहीं सुधरेंगे. अदालत ने राज्य सरकार को छह माह के भीतर यह व्यवस्था करने का आदेश देते हुए की गई कार्रवाई की रिपोर्ट न्यायालय में पेश करने को कहा है.

न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल ने जूनियर हाईस्कूलों में गणित व विज्ञान के सहायक अध्यापकों की चयन प्रक्रिया को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान सरकारी स्कूलों की दुर्दशा सामने आने पर जूनियर हाईस्कूलों में गणित व विज्ञान के सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए 1981 की नियमावली के नियम-14 के मुताबिक नए सिरे से चयन सूची तैयार करने का निर्देश दिया और कहा कि चयन सूची में शामिल लोगों को ही नियुक्त किया जाए. अदालत के संज्ञान में लाया गया कि उत्तर प्रदेश के एक लाख 40 हजार जूनियर व सीनियर बेसिक स्कूलों में अध्यापकों के दो लाख 70 हजार पद रिक्त हैं. सैकड़ों स्कूलों में पानी, शौचालय, बैठने की व्यवस्था जैसी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है. अनगिनत स्कूलों में तो छत भी नहीं है. सरकार, नेता व अफसर इस बदहाली से पूरी तरह वाक़िफ़ रहने के बावजूद इन सरकारी स्कूलों की अनदेखी करते हैं, क्योंकि उनके बच्चे सरकारी स्कूलों में नहीं, प्राइवेट स्कूलों और कॉन्वेंटों में पढ़ते हैं.

सरकारी स्कूलों की बदहाली का दृश्य देख कर उच्च न्यायालय ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि प्रदेश में तीन तरह की शिक्षा व्यवस्था है, अंग्रेजी माध्यम के कॉन्वेंट स्कूल, प्राइवेट स्कूल और बेसिक शिक्षा परिषद से संचालित स्कूल.

न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल

अदालत ने सरकार को यह भी निर्देश दिया कि इस फैसले की अनदेखी करने वाले व्यक्ति के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान किया जाए. जिनके बच्चे कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ेंगे, वहां की फीस के बराबर रकम उनके वेतन से जुर्माने के बतौर काट ली जाए. साथ ही ऐसे लोगों का कुछ समय के लिए इन्क्रीमेंट व प्रमोशन रोकने की व्यवस्था भी की जाए. अगले शिक्षा सत्र से इस व्यवस्था को लागू किया जाए.

आजादी के 68 साल बीत जाने के बावजूद सरकारी स्कूलों में मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं, यह दुर्भाग्यपूर्ण है. ऐसा अफसरों, नेताओं, न्यायिक अधिकारियों के बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ना अनिवार्य न होने के कारण हुआ है. इसी वजह से इन स्कूलों में न योग्य अध्यापक हैं और न मूलभूत सुविधाएं हैं. सरकारी खजाने से वेतन व सुविधाएं हासिल करने वालों के बच्चे जब तक सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ेंगे, तब तक इन स्कूलों की हालत में सुधार नहीं होगा.

उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव आलोक रंजन को अदालत के फैसले को तामील कराने का निर्देश देते हुए कहा कि वह यह सुनिश्चित करें कि सरकारी, अर्द्धसरकारी विभागों के कर्मचारी, जन प्रतिनिधियों, न्यायपालिका और सरकारी खजाने से वेतन, मानदेय या धन प्राप्त करने वालों के बच्चे अनिवार्य रूप से यूपी बोर्ड द्वारा संचालित स्कूलों में शिक्षा प्राप्त करें. न्यायालय ने स्पष्ट कहा कि यदि कोई अफसर या कर्मचारी अपने बच्चे को कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाता है, तो फीस के बराबर राशि उसे हर महीने सरकारी खजाने में जुर्माने के बतौर जमा करानी होगी. इस धन का इस्तेमाल सरकारी स्कूलों की बेहतरी के लिए होगा. ■

feedback@chauthiduniya.com

- स्कूलों में मूलभूत सुविधाओं का अभाव
- शिक्षकों के लाखों पद खाली पड़े हैं
- 80.9 प्रतिशत स्कूलों में पेयजल की व्यवस्था नहीं है
- शिक्षकों की नियुक्तियों में धांधली

क़ानून की तो ऐसी तैसी

शिक्षा के अधिकार का कानून लागू है. उस पर सर्वशिक्षा अभियान जैसी कई योजनाएं चल रही हैं, लेकिन इन सारे कानून और योजनाओं की जमीनी स्तर पर ऐसी-तैसी हो रही है. शिक्षा के स्तर की पड़ताल करने वाली गैर सरकारी एजेंसी एनुअल स्टेटस आफ एजुकेशन रिपोर्ट (असर) की रिपोर्ट देखें तो आपको यह एहसास होगा. रिपोर्ट बताती है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले पांचवीं स्तर के केवल 48.1 फीसदी विद्यार्थी और आठवीं स्तर के केवल 75 फीसदी विद्यार्थी ही कक्षा दो की किताबें पढ़ पाते हैं. सरकारी स्कूलों की तुलना में प्राइवेट स्कूलों में बच्चों का नामांकन लगातार बढ़ रहा है. वर्ष 2013 में 49 फीसदी बच्चे निजी स्कूलों में भर्ती हो रहे थे, 2014 में इनकी संख्या बढ़ कर 51.7 फीसदी हो गई. यह प्रतिशत लगातार बढ़ता ही जा रहा है. हिन्दी क्षेत्रों से जुड़े स्कूलों की स्थिति और भी खराब है. उत्तर प्रदेश समेत कई हिन्दी राज्यों में निजी स्कूलों में एडमिशन लेने वाले बच्चों की संख्या में लगातार इजाफा होता जा रहा है. सरकारी स्कूलों की दशा निराशाजनक है. इस बदहाली के लिए सरकारी नियम और क़ानून ही जिम्मेदार हैं. उत्तर प्रदेश में जिस तरह शिक्षकों की नियुक्तियां की गई हैं, उसमें खुल कर धांधली हुई. शिक्षा मित्र योजना के तहत भर्ती का अधिकार जबसे पंचायतों के हवाले किया गया है, उसमें सिर्फ गुटबाजी और रिश्वत को ही प्राथमिकता दी जाती है. इसका नतीजा यह निकला है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक परीक्षा बोर्ड के हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षाओं में बड़ी संख्या में (18 प्रतिशत) छात्र हिंदी में फेल हो गए. कथित हिन्दी प्रेमी सरकार की लापरवाही से राज्य में शिक्षा का स्तर ऐसा गिरा कि स्थिति यहां तक आ गई. सपा शासन में राज्य में शिक्षा व्यवस्था को बदहाली अधिक देखनी पड़ी है. शिक्षकों के लाखों पद खाली पड़े हैं. योग्यता नौकरी की तलाश में सड़क पर भटक रही है और जाति-पैसे वाले अयोग्य लोग नौकरियां पा रहे हैं. ■

बदहाल हैं सरकारी स्कूल

उत्तर प्रदेश में प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूलों की तादाद एक लाख 40 हजार है. इनमें एक करोड़ 75 लाख बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन हालत यह है कि इनमें से 80.9 प्रतिशत स्कूलों में पेयजल की व्यवस्था नहीं है. 49.1 प्रतिशत स्कूलों में ही टॉयलेट हैं, लेकिन वह भी बिल्कुल खस्ता हाल में. 52.4 फीसदी स्कूलों में कक्षा-एक के बच्चों को अक्षर का ज्ञान तक नहीं है. 15.4 प्रतिशत स्कूल ऐसे पाए गए हैं, जिनके 8वीं क्लास तक के बच्चे 1 से 9 तक के अंक नहीं पहचानते. उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 3,89,269 शिक्षक हैं, जबकि दो लाख 70 हजार शिक्षकों की कमी है. लेकिन इस दुर्दशा की तरफ देखने के लिए कोई तैयार नहीं है. जबकि इसके लिए अलग मंत्रालय है, विभाग है, अधिकारी हैं और कर्मचारियों की भारी फौज है. इस पर विद्रोही तेवर के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी सूर्य प्रताप सिंह कहते भी हैं कि उच्च न्यायालय की मंशा तो ठीक है, पर यह कैसे होगा यह देखना सरकार का प्राथमिक दायित्व है. ■

सबने सराहा, पर कुछ ने की कुटिल टिप्पणी

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के इस ऐतिहासिक फैसले की समाज के सभी वर्गों ने सराहना की है. ऐसे लोग जिनके निजी हित टकरा रहे हैं, उन्होंने बड़ी कुटिल टिप्पणी की है. प्रमुख समाजसेवी मैगसेसे पुरस्कार विजेता संदीप पांडेय ने इस फैसले का स्वागत किया है. उन्होंने कहा कि वे और उनकी सोशलिस्ट पार्टी उच्च न्यायालय के इस फैसले का स्वागत करती है और अदालत का अभिवादन करती है. संदीप पांडेय ने कहा कि विडंबना यह है कि प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार है, लेकिन वह सरकारी स्कूलों की तरफ उपेक्षा का भाव रखती है. जबकि समाजवादी चिंतक डॉ. राममनोहर लोहिया ने गरीब और अमीर के बच्चों को एक ही जगह पढ़ाने की बात कही थी. सोशलिस्ट पार्टी (इंडिया) पिछले दो साल से इसी मांग को लेकर आन्दोलन कर रही है. उन्होंने कहा कि जो लोग सरकार से ठेके लेते हैं उन सब के बच्चों को भी सरकारी स्कूलों में ही पढ़ना अनिवार्य किया जाना चाहिए. उन्होंने यह मांग की कि जो व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहता है वह सरकारी स्कूल से ही पढ़ा हुआ हो और उसके बच्चे भी सरकारी स्कूल में ही पढ़ रहे हों, यह भी अनिवार्य किया जाए. सरकारी स्कूलों में पढ़े लोगों को ही सरकारी नौकरी भी मिलनी चाहिए. उत्तर प्रदेश राज्य निगम कर्मचारी महासंघ के महामंत्री मनोज मिश्रा ने कहा कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई न होने के कारण कर्मचारी अपने बच्चों को मजबूरी में प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं. जब अधिकारी और शिक्षकों के बच्चे वहां पढ़ेंगे, तो सब अपने आप सही हो जाएगा. उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष शशि मिश्रा का मानना है कि सरकार अपने स्कूलों पर बड़ी रकम खर्च करती है, लेकिन बजट का ज्यादातर हिस्सा शासन स्तर पर बैठे लोग खा जाते हैं. हम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करते हैं. चतुर्थ श्रेणी राज्य कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष रामराज दुबे कहते हैं कि उच्च न्यायालय का फैसला बहुत सही है. हम इस फैसले का स्वागत करते हैं, लेकिन शासन और उच्च पदों पर बैठे लोग इस फैसले को किस तरह लागू करा पाते हैं, इस पर नजर रखने की जरूरत है. उत्तर प्रदेश प्रधानाचार्य परिषद के अध्यक्ष जेपी मिश्रा ने कहा कि प्रधानाचार्य परिषद ने 15 साल पहले शासन से यह मांग की थी, लेकिन शासन ने इसे स्वतंत्रता के अधिकारों का हनन बताया था. सरकारी स्कूलों के सुधार का यह एकमात्र रास्ता है. शिक्षक संघ के प्रदेश मंत्री डॉ. आरपी मिश्रा ने कहा कि उच्च न्यायालय के इस फैसले के बाद सरकारी स्कूलों की स्थिति में सुधार होगा. जब अधिकारियों के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे, तो उसकी स्थिति बेहतर करने के लिए वे खुद प्रयास करेंगे. राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद (तिवारी गुट) के प्रदेश महामंत्री जेएन तिवारी का कहना था कि उच्च न्यायालय के फैसले से किसी को एतराज नहीं होगा. इससे तो कर्मचारियों का खर्च ही कम होगा, लेकिन सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर भी सुधारने की जरूरत है. उच्च न्यायालय के इस फैसले पर आईएएस एसोसिएशन ने अपनी कुटिल टिप्पणी जारी की. एसोसिएशन के सचिव आईएएस भुवनेश कुमार ने कहा कि उच्च न्यायालय के आदेश की भाषा देखनी होगी. अगर न्यायालय ने ऐसा आदेश दिया है, तो पहले सरकार कोई निर्णय लेगी. जरूरत पड़ेगी तो एसोसिएशन की सामान्य सभा में भी चर्चा की जाएगी. उत्तर प्रदेश सिविल सेवा कार्यकारी शाखा संघ के अध्यक्ष रमाकांत पांडेय ने भी ऐसे ही लहजे में कहा कि न्यायालय का फैसला अभी देखा नहीं है. अगर न्यायालय ने कहा है तो कुछ बेहतर करने के लिए ही कहा होगा. अदालत के आदेशों का पालन किया जाएगा. लखनऊ में निजी स्कूलों की श्रृंखला चलाने वाले सीएमएस समूह के संस्थापक जगदीश गांधी ने कहा कि अब उच्च न्यायालय का आदेश है, तो इस पर कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती. हमारे स्कूल में जो आएगा, हम उसे तो एडमिशन देंगे ही. लखनऊ पब्लिक स्कूल समूह के संस्थापक एसपी सिंह ने नपे-तुले अंदाज में कहा कि उच्च न्यायालय का आदेश तो ठीक है, लेकिन पहले सरकार को इन स्कूलों का स्तर सुधारना होगा. अगर सरकारी स्कूलों का स्तर बेहतर होता, तो लोग हमारे स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाते ही क्यों. ■